मूल्य 20 रुपये

चौथी दुनिया

दिल्ली रविवार 9 अगस्त 2009

हिन्दी का पहला साप्ताहिक अखबार

भीतर

4 भारत में भी होंगी बेहतरीन सड़कें : परिवहन सचिव

7 बुंदेलखंड राज्य के लिए भड़कने लगी आग

9 संस्कृति के ख़िलाफ़ है समलैंगिकता

हिन्दुस्तान पाकिस्तान बलूचिस्तान

पाक की आंख में क्यों चुभता है बलूचिस्तान | पाकिस्तान से त्रस्त है बलूच जनता | प्रधानमंत्री ने उलटे पाक को ही फंसाया | बलूची चला रहे हैं धर्मनिरपेक्ष आंदोलन

मनीष कुमार

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान पर ऐतिहासिक कूटनीतिक जीत हासिल की है. पाकिस्तान ने मुंबई हमले पर अपनी जांच की पूरी रिपोर्ट 11 जुलाई को भारत को सौंपी है. इस सरकारी दस्तावेज़ में पहली बार पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर यह माना कि भारत में आतंकवादी हमलों के लिए ज़िम्मेदार आतंकवादियों का सरोकार पाकिस्तान से है. पाकिस्तान ने मान लिया कि मुंबई धमाके की साज़िश, हमले का संचालन, उसका मास्टर माइंड और हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी पाकिस्तानी हैं. सोचने वाली बात यह है जो पाकिस्तान अब तक इस बात से इंकार करता आया है कि वह आतंकवादियों का पनाहगार है, वह आधिकारिक तौर पर यह मानने को कैसे तैयार हो गया. एक महीने पहले रूस में मुलाक़ात के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गिलानी ने मनमोहन सिंह से साफ–साफ कहा था कि वह सिर्फ़ इतना कह सकते हैं कि भारत पर होने वाले आतंकवादी हमले के लिए पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है. सोचने वाली बात है कि एक महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया. क्या मिस्र में भारत–पाकिस्तान के संयुक्त बयान में बलूचिस्तान का ज़िक्र होना इसकी क़ीमत है ? अगर यह सही है तो प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं. प्रधानमंत्री का फ़ैसला सराहनीय है. और ऐसा इसलिए है, क्योंकि बलूचिस्तान का इतिहास, उसकी समस्या और वहां के लोग इस बात के गवाह हैं कि

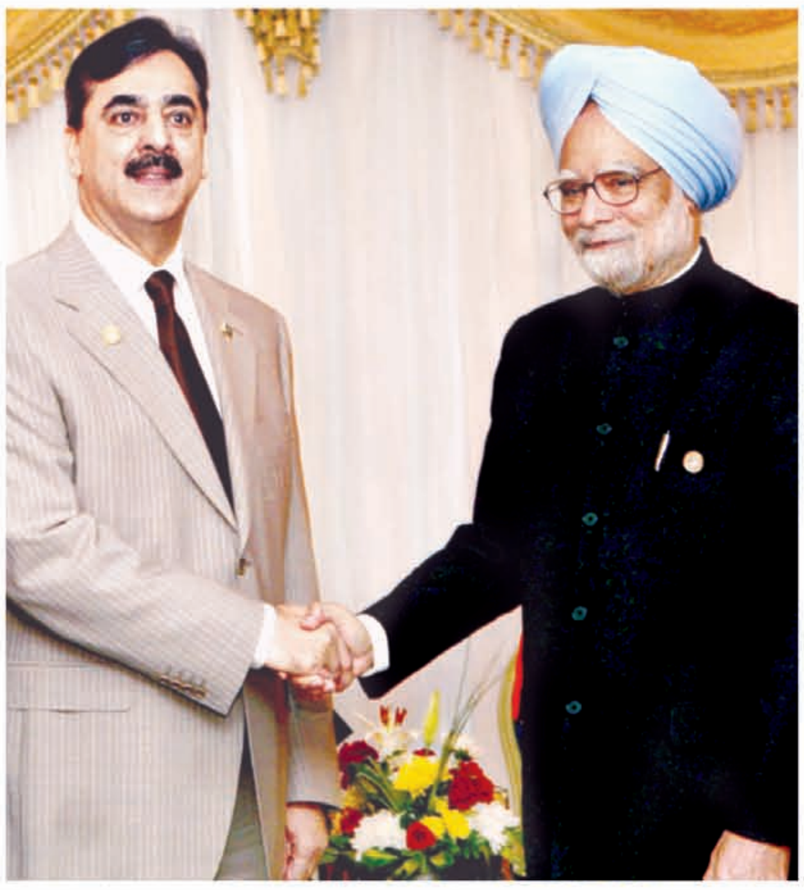

बलूचिस्तान में अशांति का कारण इस इलाक़े की ग़रीबी और पाकिस्तान की नीति है.

मिस्र में भारत–पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों का साझा बयान क्या आया, मानो तूफ़ान आ गया. भारत में विरोधी दलों और अंतरराष्ट्रीय मामले के विशेषज्ञों ने एक तरफ़ से इसे एक भूल बताया. टेलीविजन मीडिया तो एक क़दम आगे निकल गया और प्रधानमंत्री को ही कठघरे में खड़ा कर दिया. इतना हंगामा हुआ कि कांग्रेस पार्टी भी बैकफुट पर चली गई. उधर पाकिस्तान पहुंचते ही प्रधानमंत्री गिलानी यह कहने में देर नहीं लगाई कि हमने भारत को इस बात को मानने के लिए मजबूर कर दिया कि बलूचिस्तान में चल रही हिंसा के पीछे भारत का हाथ है. पाकिस्तान सरकार ने इस बयान को एक जीत के तौर पर दिखाने के लिए सारी शक्ति लगा दी है. हमारे देश के लोग भी इस बात को लेकर भ्रमित हैं, लेकिन बलूची नेता कहते हैं कि भारत ने आज तक उनकी कोई मदद नहीं की है. अगर मदद की होती तो बलूचिस्तान का सूरतेहाल कुछ और होता. असलियत यह है कि भारत–पाकिस्तान के साझा बयान आने के बाद बलूचिस्तान के लोगों को राहत मिली है. पहली बार बलूचिस्तान की बात अंतरराष्ट्रीय मंच उठी है. बलूच नेता सुलेमान ख़ान भारत के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने पहली बार यह माना कि उनके पड़ोस में कुछ गड़बड़ है, अगर वह इस मसले में कोई भूमिका निभाए तो बेहतर होगा.

साझा बयान में ऐसा क्या था जिससे इतना बड़ा बवंडर आ गया? साझा बयान में लिखा था कि प्रधानमंत्री गिलानी ने बातचीत के दौरान बताया कि पाकिस्तान के पास बलूचिस्तान और अन्य इलाक़ों में ख़तरे को लेकर कुछ जानकारियां हैं. बस. ये जानकारियां कैसी हैं, कितनी सच और कितनी झूठ है, क्या ये जानकारियां ये बताती है कि बलूचिस्तान में आतंकवादी हमले के पीछे भारत का हाथ है, ये सब बातें फ़िलहाल कहने–सुनने की हैं. असलियत यह है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी पूरी दुनिया को है. वहां किस तरह से पाकिस्तान की सरकार आम जनता पर सैनिक हमले करती है, दुनिया भर के मानवाधिकार और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के ज़रिए इसकी जानकारी मिलती रहती है. हमने सिर्फ़ अपनी आंखें बंद कर ली है. असलियत यह है कि बलूच मानवाधिकार काउंसिल का आरोप यह है कि पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान के असल मुद्दे को उलझाने के लिए भारत का नाम लेती है. ग़ौर करने वाली बात यह है बलूचिस्तान का आंदोलन पाकिस्तान का अकेला धर्मनिरपेक्ष आंदोलन है. यह आंदोलन इस्लाम की बातें नहीं करता और न ही इसका संचालन मुस्लिम धर्मगुरु या मौलवी करते हैं. बलूचिस्तान का

(शेष पृष्ठ 2 पर)

बलूचिस्तान आंदोलन का इतिहास

बलूचिस्तान के निवासियों और पाकिस्तान की सरकार के बीच की यह तकरार नई नहीं है. पाकिस्तान की समस्या यह है कि 1947 से बलूचिस्तान में लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं. बलूच समुदाय शोषण के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं. बलूचिस्तान की प्राकृतिक संपदाओं और औद्योगीकरण से उनका फ़ायदा नहीं हुआ है. इसका फ़ायदा बाहर के लोग उठा रहे हैं. पंजाब और सिंध के लोगों के हितों को बचाने केलिए सरकार यहां सैनिकों का जमावड़ा करती है और वक़्त–बेवक़्त उनका इस्तेमाल बलूचिस्तान की असहाय जनता पर करती है. परवेज मुशर्रफ और वर्तमान सरकार के दमन के बावजूद बलूचियों की लड़ाई जारी है. कूटनीति, इतिहास में दर्ज़ घटनाओं को बदल नहीं सकती है. 1947 से बलूचिस्तान का इतिहास पाकिस्तानी सेना और सरकार के दमन की कहानी है. बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रही लड़ाई के मुख्य बिंदु इस तरह हैं–

पहली लड़ाई (1948)

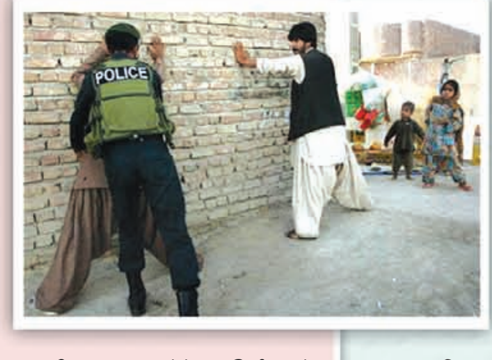

1947 में भारत के विभाजन केसमय बलूचिस्तान पाकिस्तान में नहीं था. अप्रैल 1948 में पाकिस्तान सरकार ने सेना भेजी, जिसने मीर अहमद यार ख़ान को अपने राज्य को पाकिस्तान के हवाले करने को मजबूर कर दिया. उनके भाई, प्रिंस अब्दुल करीम ख़ान ने पाकिस्तान सरकार केसाथ संघर्ष करने का फ़ैसला किया. वह अफ़ग़ानिस्तान में रहकर पाकिस्तान की सेना के साथ गुरिल्ला युद्ध करते रहे. 16 मई 1948 को अब्दुल करीम ने एलान कर दिया कि वह बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए आंदोलन करेंगे. उन्होंने बलूचिस्तान के बड़े राजनीतिक दलों का एक गठजोड़ बनाया. प्रिंस अब्दुल करीम ख़ान का संबंध न सिर्फ़ वहां के शाही परिवार से था बल्कि वह मकरान राज्य के पूर्व गवर्नर भी थे.

दूसरी लड़ाई (1958–59)

जब प्रधानमंत्री चौधरी मोहम्मद अली ने पाकिस्तान में एक यूनिट की पॉलिसी का एलान किया तो बलूचिस्तान में हंगामा मच गया. इस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान का मक़सद संघीय ढांचे को ख़त्म करके चारों राज्यों को एक साथ मिलाना था. नवाब नवरोज ख़ान ने इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ हथियार उठा लिए. उन्हें और उनके समर्थकों को देशद्रोह का दोषी बता कर पाकिस्तान की सरकार ने गिरफ़्तार कर लिया. उन्हें हैदराबाद जेल में डाल दिया गया. जब वह जेल में थे तभी उनके परिवार के पांच सदस्यों को फांसी दे दी गई. इसके बाद जेल के अंदर ही नवाब नवरोज ख़ान की मौत हो गई.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

आतंक की कहानी पाक की ज़ुबानी

पाकिस्तान की सरकार ने अपने आधिकारिक दस्तावेज़ में जो बातें लिखी हैं, उनसे यह साफ हो जाता है कि किस तरह पाकिस्तान की ज़मीन से आतंकवादी भारत विरोधी साज़िश को अंजाम देते हैं. इस दस्तावेज़ से यह भी पता चलता है किस तरह पाकिस्तान के अंदर बिना रोकटोक के आतंकवादी अपना काम करते हैं. सवाल है कि यह कैसे संभव है कि इतने ख़तरनाक आतंकवादी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हों और पाकिस्तान की सरकार को इसका पता न हो? जबकि यह जगज़ाहिर है कि पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई पाकिस्तान के चप्पे–चप्पे पर मौजूद है. इस पाकिस्तानी दस्तावेज़ में दिए गए सबूत कुछ इस तरह हैं–

- फोन नंबर की जांच से पता चला कि नंबर किसी शाहिद जमील रियाज़ के नाम से था. 30 अक्टूबर 2008 को शाहिद के नाम से ही रजिस्टर्ड एक नंबर से पहले नंबर के चोरी होने की रिपोर्ट मिली. इस नंबर से एबीएल बैंक की दरीग़ बाग़ शाखा, कराची को 21 बार कॉल किए गए. यहां शाहिद रियाज़ के नाम से एक चालू खाता था. इसका पता आर–44, मिल्लत टाउन, कराची का था.
- बैंक खाते की जांच से पता चला है कि आरोपी ने एआरज़ेड स्पोर्ट्र्स से एक यामाहा इंज़न, एक हवा भरने वाली नाव, लाइफ जैकेट आदि की ख़रीद की. शाहिद रियाज़ और अमीन सादिक़ के खातों से रक़मों का भारी लेनदेन हुआ.
- जांच से यह भी पता चला कि अमीन सादिक़ जो पहले आर–44, मिल्लत टाउन, कराची में रहा करता था, अब आर–46 में रह रहा था. उसने माना कि वह लश्कर का सदस्य है और उससे पहले आर–46, अमजद ख़ान में रहा करता था.
- अमीन सादिक़ की निशानदेही पर कराची में अज़ीज़ाबाद के नाम से चल रहे एक ट्रेनिंग कैंप पर छापा मारा गया. वहां आतंकवादी साहित्य, दो लाइफ बोट्स, भारतीय तटीय इलाक़ों का नक़्शा और मोहम्मद सबीर सल्फी (अल–हुसैनी नाव पर काम करने वाले) के नाम पर एक सेलुलर फोन का एग्रीमेंट आदि बरामद हुए.
- उसी की निशानदेही पर थाथा में एक लश्कर कैंप पर छापा मारा. यहां से बोट के लिए पीटर इंज़न, दो बोट, एक लंगर, दो पॉकेट डायरियां मिलीं, जिनमें आरोपियों और दूसरे लोगों के नाम और कैंप का ख़र्च लिखा था. वहां से जांच करने वालों को कंप्यूटराइज्ड राष्ट्रीय पहचान पत्रों (सीएनआईसी) की फोटो कॉपी (उनमें मोहम्मद सबीर सल्फी और अमजद ख़ान के भतीजे शाहिद जमील वल्द मोहम्मद सिद्दीकी के कार्ड्स भी थे), अमीन सादिक़ के खाते में जमा करने की एक रसीद, कुछ हथियार आदि बरामद हुए.
- अमीन सादिक़ ने यह भी बताया कि अमजद ख़ान के पास एक कार है–एईएक्स 094.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

लाली को अब मिलेगा पुरस्कार

पिछली सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री के तौर पर आनंद शर्मा को इस बात का श्रेय तो दिया ही जाना चाहिए कि चुनाव के दौरान उनकी पार्टी को ज़रूरी कवरेज़ मिला. शर्मा ने प्रियरंजन दासमुंशी के बीमार पड़ने के बाद यह मंत्रालय संभाला था. बहरहाल, सरकार को अपनी योजनाओं और उपलब्धियों के लिए सरकारी चैनल पर सही प्रसारण मिला. हालांकि वह चाहते हैं कि जो आदमी इसका सही हक़दार है, उसे ही यह हक़ मिले. तब बीएस लाली प्रसार भारती के सीईओ थे. शर्मा अब इसके लिए उनको पुरस्कृत करना चाहते हैं. यह दूसरी बात है कि लाली अपनी वर्तमान स्थिति को लेकर काफी दबाव में हैं. नई सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने इस पर विचार नहीं किया है कि लाली को क्या और कब दिया जाना है. इसमें संदेह नहीं कि यह राजनैतिक विवाद का एक हिस्सा है. बोर्ड में चापलूसी और आरोपों के सिलसिले काफी तेज़ी से फैले हैं और कुछ महीने पहले बोर्ड के चेयरमैन अरुण भटनागर का त्यागपत्र आंबिका सोनी ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है. यह लाली के लिए शर्म की वजह है, और इस वजह से वह गुस्से में भी हैं. वास्तव में अनुभवी बाबू लाली के लिए, जिन्होंने हमेशा आईएस अधिकारी के रूप में काम किया, यह दोहरे लाभ का मामला है. उनकी तरक़्क़ी हो सकती है और उन्हें इससे इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ) में चेयरमैन का पद दिया जा सकता है. इसके अतिरिक्त वह अपने पसंद के मंत्रालय में भी काम कर सकते हैं.

एक नई पहल

अब जबकि सरकार ने फ़ैसला ले लिया है, तो हमें यह देखने को मिलेगा कि कॉरपोरेट हस्तियां बाबुओं की अपेक्षा सरकारी कार्यक्रमों को कितनी अच्छे तरह से संचालित कर सकेंगी. इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलकेणी को सरकार ने यूनिक पहचान पत्र कार्यक्रम का मुखिया बनाया है. ऐसा दायित्व संभालने वाले कॉरपोरेट जगत की वह पहली हस्ती हैं.

पहले से ही नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल बदहाल एयर इंडिया को उबारने के लिए रतन टाटा से आस लगाए थे. सूत्रों के मुताबिक टीसीएस (टाटा कंसल्टेंसी सर्विस) के सीईओ रामदोरई और इंफोसिस के चेयरमैन एनआर नारायण मूर्ति भी बोर्ड में आ सकते हैं. जबकि ख़बर के अनुसार प्रधानमंत्री ने एल एन मित्तल, इंदिरा नूई और विक्रम पंडित से एक संयुक्त कार्यक्रम विकसित करने के लिए सरकार की मदद करने को कहा है. कॉरपोरेट सीईओ पर सरकार का इस तरह का विश्वास स्वागतयोग्य है, लेकिन स्पष्ट रूप से जिस पथ पर नीलकेणी एंड कंपनी आगे बढ़ रही है, वह दूसरे के लिए आसान नहीं है. सरकार के अनुभवी रक्षकों ने इन सीईओ से सावधानी बरतने की सलाह दी है. वे उन्हीं लोगों को नियुक्त करेंगे, जिनमें प्रबंधन की योग्यता होगी और वे नीलकेणी के पसंदीदा वर्ग के साथ काम करने की शपथ लेंगे.

साउथ ब्लॉक

अंजुम ए ज़ैदी

शीला की जगह सुभाष चंद्रपाणि

उड़ीसा काडर के 1972 बैच के आईएएस अधिकारी सुभाष चंद्रपाणि- जो फ़िलहाल योजना आयोग के सचिव हैं- को अगले आदेश तक इंडियन ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आईटीपीओ) के प्रमुख का पद सौंपा गया है. सुभाष चंद्रपाणि, वर्तमान आईटीपीओ मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी) शीला भिडे (आंध्र प्रदेश काडर, बैच 1973) की जगह लेंगे.

यूपीएससी में बना नया पद

संघीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में अतिरिक्त सचिव स्तर के एक नए पद का सृजन किया गया है, जो संयुक्त सचिव के पद के समकक्ष होगा. जम्मू व कश्मीर काडर के 1986 बैच के अधिकारी राकेश कुमार गुप्ता नेशनल कॉपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया (एनसीसीएफ) में मुख्य निगरानी अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक इस नए पद पर उनकी नियुक्ति होने वाली है.

सुरजीत मित्रा का कार्यकाल समाप्त!

लगता है कि आईएएस सुरजीत मित्रा का कार्यकाल अब ख़त्म होने वाला है. वह भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत भारी उद्योग विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं. उनका कार्यकाल इससे पहले एक बार 31 जुलाई 2009 तक के लिए बढ़ा दिया गया था. हालांकि, इस बार उन्हें सरकार की तरफ़ से ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है.

हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और बलूचिस्तान

पृष्ठ एक का शेष

आंदोलन हक़ और प्रजातांत्रिक अधिकारों की लड़ाई है. साझा बयान पर सवाल उठाने वाले मीडिया और राजनीति के वे लोग हैं जिन्हें यह पता नहीं है कि आख़िर बलूचिस्तान क्या है? वहां के लोगों की समस्या क्या है? वहां के आंदोलन का आधार क्या है? मनमोहन सिंह ने बलूचिस्तान में चल रही घटनाओं पर चिंता ज़ाहिर कर उस कर्तव्य का पालन किया जिसे राजनीति की मजबूरी के चलते इंदिरा गांधी नहीं कर पाईं. भारत-पाकिस्तान के संयुक्त बयान में बलूचियों को लाकर मनमोहन सिंह ने हिम्मत का परिचय दिया है. भारत को अगर विश्व राजनीति में कोई अहम भूमिका निभानी है, तो पड़ोस में चल रहे नरसंहार पर चुप रहना उचित नहीं है. बलूचियों के मुद्दे को उठाना भारत की ज़िम्मेदारी है. भारत सरकार को पाकिस्तान पर दबाव डालने की ज़रूरत है कि बलूचियों को भारतीय एजेंट बता कर उन पर ज़ुल्म करना बंद करे.

जो लोग मनमोहन सिंह का विरोध कर रहे हैं उनकी मानसिकता 20 साल पुरानी है. आज के ज़माने में जब दुनिया में संचार का ऐसा नेटवर्क फैला है, बलूचिस्तान में कई आंतर्राष्ट्रीय संगठन काम कर रही है. इसलिये पाकिस्तान के इस झूठ को कोई मानने वाला नहीं है. हक़ीक़त यह है पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए अमेरिका से मिले हेलीकॉप्टर और हथियार का इस्तेमाल बलूचियों पर कर रही है. इंटरनेट पर ऐसी कई रिपोर्ट मौज़ूद हैं, जो पाकिस्तान की सेना की करतूत का पर्दाफाश करती हैं. मनमोहन सिंह सरकार की चिंता बलूचिस्तान की बदहाली और वहां के लोगों समस्या होनी चाहिए. साथ ही आतंकवाद के नाम पर बलूचियों के नरसंहार को रोकने में भारत की सरकार को अंतरराष्ट्रीय नियमों और क़ानून के तहत जो भी क़दम उठाए जा सकते हैं, उठाने चाहिए.

बलूच आंतकवादी नहीं हैं

पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान. यह पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है जो दक्षिण से अरब सागर, पश्चिम से ईरान और उत्तर में अफ़ग़ानिस्तान की सीमा से सटा है. यह पाकिस्तान के क्षेत्रफल का 43 प्रतिशत है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से यहां पाकिस्तान की कुल जनसंख्या के सिर्फ़ पांच प्रतिशत लोग ही रहते हैं. इसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान का ज़्यादातर इलाक़ा पहाड़ और रेगिस्तान है. पानी की कमी है, इसलिए जनसंख्या कम है. बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है. यहां के मुख्य निवासी बलूच और पठान हैं. बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे ग़रीब और विकास की धारा से सबसे दूर है. इसी बदहाली का नतीजा है कि लोग पाकिस्तान की हुक़ूमत को अपना नहीं मानते. बलूचिस्तान खनिज पदार्थों का भंडार है, लेकिन यहां के लोग ग़रीब हैं. इस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है. पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान के लोगों को शिक्षा, रोज़गार, पीने का साफ पानी, स्वास्थ्य सेवा आदि ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराने में असफल रही है. लोग अपनी परेशानियों को लेकर आंदोलित हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है. इसलिए आए दिन बलूचिस्तान से हिंसा की ख़बरें आती रहती हैं. जब भी लोग अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करते हैं, तो पाकिस्तान की सरकार और एजेंसी इन्हें कभी आतंकवादी तो कभी भारत का एजेंट बताकर उनके ख़िलाफ़ सैनिक कार्रवाई करते हैं. बलूचिस्तान में हिंसा का मुख्य कारण है अफ़ग़ानिस्तान से पश्तून शरणार्थी, जो यहां की डेमोग्राफी को बदल रहे हैं. इनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनमें से कुछ आतंकवादियों के समर्थक हैं. बलूची एक सेकुलर समुदाय है. उनको लगता है कि धर्मनिरपेक्ष बलूच राष्ट्रवाद को ख़त्म करने के एजेंडे के तहत इस्लामाबाद ने जानबूझ कर रिफ्यूजियों के लिए सीमा को खोल दिया है. आज हालात ये हैं कि बलूचिस्तान सीधे तौर पर आईएसआई के अधीन है और वह यहां पर चल रहे आंदोलन को बाहरी ताक़तों की करतूत बता कर अपनी चाल चल रही है.

एक ही झूठ को अगर बार-बार बोला जाए, तो लोग इसे सच मानने लगते हैं. बलूच भारतीय एजेंट हैं, यह पाकिस्तान की सरकार का दुष्प्रचार है. इसका असर पाकिस्तान की जनता पर भी दिखता है. यह पाकिस्तान की सामूहिक चेतना का हिस्सा बन चुका है, लेकिन उसकी अलग कहानी है. बलूचिस्तान के लोगों ने भारत के विभाजन का समर्थन नहीं किया था. बलूचिस्तान के लोग मानते हैं कि पाकिस्तान ने बंदूक की नोक पर बलूचिस्तान को छीन लिया और अपनी हुक़ूमत स्थापित कर दी. बलूचिस्तान के लोगों ने आज़ादी से पहले जिन्ना से ज़्यादा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू को अपना नेता माना. आज भी उनकी आज़ादी के गीतों में भगत सिंह का नाम होता है.

विभाजन के बाद जब 1947 में आज़ादी के बाद भारत-पाकिस्तान में दंगे हो रहे थे, तब पाकिस्तान से हिंदू, सिख और ग़ैर-मुस्लिमों को भगाया जा रहा था. उस वक़्त भी बलूचिस्तान अकेला ऐसा इलाक़ा था जहां से किसी को भगाया नहीं गया, कोई क़त्लेआम नहीं हुआ. 1992 में जब हिंदू संगठनों ने भारत में बाबरी मस्जिद को गिरा कर देश को तोड़ने का काम किया तो पाकिस्तान में इसकी प्रतिक्रिया हुई. पाकिस्तान के पंजाब में अधिकारियों की मदद से हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया. इस दौरान भी बलूचिस्तान शांत रहा. बलूचिस्तान में एक भी मंदिर पर हमले नहीं हुआ और न ही किसी हिंदू को क्षति पहुंची. ख़ैरबख्श मारी, अताउल्लाह ख़ान मेंगल, अकबर ख़ान बुग्ती जैसे कई बलूच नेताओं ने इस दौरान हिंदुओं और मंदिरों को अपने संरक्षण में ले लिया. इन नेताओं ने हिंदुओं को न सिर्फ़ बचाया, बल्कि अपनी निगरानी में पूजा-पाठ भी कराया. बलूचियों और हिंदुओं की निकटता का गवाह है नवाब खान बुग्ती की हत्या. अगस्त 2006 में जब परवेज मुशर्रफ की सरकार ने एक सैनिक हमले में उनकी हत्या की, तो उनके साथ मरने वालों ने कई हिंदू थे, जो उनके समर्थक थे.

जवान या बूढ़े, शहरी या ग्रामीण, पढ़े-लिखे या अनपढ़-सेकुलरिज़्म बलूचियों के ख़ून में है. यह बात भी सोचने वाली है कि इतनी ग़रीबी और पिछड़ेपन के बावजूद बलूच किसी जिहादी आतंकवादी संगठन के सदस्य नहीं बनते और न ही किसी बलूची का नाम भारत में आतंक फैलाने वालों की लिस्ट में है. बलूच न तो अल-क़ायदा के समर्थक हैं और न ही तालिबान के. न ही आजतक कोई ऐसा उदाहरण है जिसमें यूरोप या अमेरिका में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादियों में कोई बलूच हो और आज तक कोई बलूच आत्मघाती आतंकवादी नहीं बना. हां, कुछ ऐसे उदाहरण ज़रूर हैं, जैसे कि डेनियल पर्ल की किडनैपिंग और हत्या, जिसमें येमेनी बूलच भी शामिल थे. यह उदाहरण एक अपवाद की तरह है, लेकिन साधारण तौर पर कहा जा सकता है कि बलूच जिहादी आंतकवाद के समर्थक नहीं हैं.

बलूच आतंकवादी नहीं हैं. वहां की समस्या आतंकवाद नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है. पाकिस्तान अगर बलूचिस्तान को भारत-पाकिस्तान के रिश्तों के बीच मोहरा बनाता है तो आगे आने वाले दिनों में इसके भयानक परिणाम हो सकते हैं. यह बात भी तय है कि बलूचिस्तान में सेना और हथियारों के इस्तेमाल से शांति नहीं आने वाली है. पाकिस्तान को बलूचिस्तान में शांति के लिए सैनिकों को वापस बैरक में भेजना होगा. बलूचियों को राजनीतिक और प्रजातांत्रिक अधिकार देने होंगे और बलूचियों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी बलूच समूदाय के हाथों में देने की ज़रूरत होगी. साथ ही बलूचिस्तान में पाकिस्तान और विदेशी मीडिया पर लगे प्रतिबंधों को ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि यहां की हक़ीक़त पाकिस्तान सरकार और दुनिया के सामने आए. पाकिस्तान सरकार को बलूचिस्तान के नेताओं के साथ मिलकर हर समस्या का हल निकालना होगा और बलूचिस्तान में विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए मिलजुल कर काम करना होगा. अगर ऐसा नहीं होता है तो यह बलूचिस्तान के साथ अन्याय होगा. पाकिस्तान की सरकार को यह समझना चाहिए कि बंदूक के सहारे आतंकवादियों से तो लड़ा जा सकता है लेकिन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए लड़ने वाली जनता का सामना टैंक नहीं कर सकते. बलूचिस्तान की समस्या के पीछे विदेशी ताक़तें नहीं हैं, पाकिस्तान की ख़ुद की नासमझी है.

manish@chauthiduniya.com

बलूचिस्तान आंदोलन का इतिहास

पृष्ठ एक का शेष

तीसरी लड़ाई (1963-69)

नवाब नवरोज ख़ान की मौत के बाद पाकिस्तान की सरकार ने बलूचिस्तान में सैनिकों को तैनात करना शुरू कर दिया. इसके विरोध में शेर मोहम्मद बिजरानी मारी ने गुरिल्ला युद्ध शुरू किया. इन लोगों ने रेलवे लाइन पर बमबारी की और कई सैनिक ठिकानों को अपना निशाना बनाया. पाकिस्तानी सेना ने इसका भयानक जवाब दिया और मारी जनजाति के कई इलाक़ों को तबाह कर दिया. इस युद्ध का नतीजा यह रहा कि याहया ख़ान ने 1969 में एक यूनिट की पॉलिसी को ख़त्म कर दिया और बलूचियों के साथ शांति स्थापित की. इस पॉलिसी के ख़त्म होते ही बलूचिस्तान को नई पहचान मिली. आज यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है.

चौथी लड़ाई (1973-77)

1972 में राजनीतिक दलों फिर से एकजुटता दिखाई और पाकिस्तान की ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरकार के ख़िलाफ़ आंदोलन शुरू किया. उन्होंने सरकार में बलूच समुदाय की हिस्सेदारी का सवाल उठाया. इसके जवाब में पाकिस्तान सरकार ने वहां की सरकार गिरा दी, जिससे बलूचिस्तान में हिंसा भड़क उठी. उस लड़ाई में आठ हज़ार से ज़्यादा बलूचियों की मौत हुई.

पांचवीं लड़ाई 2004 से अब तक

2005 में बलूच लीडर नवाब अकबर ख़ान बुग्ती और मीर बचाच मारी ने पाकिस्तान सरकार के सामने 15 प्वाइंट का एजेंडा रखा. इसमें बलूचिस्तान की प्राकृतिक संपदा, बलूचों की सुरक्षा और इलाक़े में सैनिक अड्डा बनाने पर रोक जैसे मुद्दे थे. सरकार ने इसे नज़रअंदाज़ कर दिया. पाकिस्तान सरकार के शोषण के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान में फिर से आंदोलन शुरू हो गया. पाकिस्तान सरकार ने राजनीतिक हल निकालने के बजाय बलप्रयोग किया. सैकड़ों राजनीतिक कार्यकर्ता, छात्रों, डॉक्टरों और नेताओं की बिना किसी ज़ुर्म के गिरफ़्तारी शुरू हो गई. इनमें से कई आज तक वापस लौट कर नहीं आए हैं. कई लोगों को जेल में यातना दी गई जिससे उनकी मौत हो गई. अगस्त 2006 को पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए नवाब अकबर ख़ान बुग्ती की मौत हो गई. 3 अप्रैल 2009 में बलूच नेशनल मूवमेंट के अध्यक्ष ग़ुलाम मोहम्मद बलूच और उनके साथी लाला मुनीर और शेर मोहम्मद को सरेआम गिरफ़्तार किया गया और पांच दिन बाद एक सुनसान जगह में उनकी लाशें मिलीं. उनकी लाशें गोलियों से छलनी थीं. बलूचिस्तान के लोग मानते हैं कि यह काम आईएसआई का है.

आतंक की कहानी पाक की ज़ुबानी

पृष्ठ एक का शेष

इस कार की दो नंबर प्लेटें लश्कर कैंप से बरामद हुई थीं.

- पारिवारिक रिकाड्‌र्स, स्कूल, वोटर लिस्ट और लोगों के बयानों के आधार पर अजमल कसाब (ओकारा) और इमरान बब्बर (मुल्तान) की पहचान की गई.
- भारत द्वारा जुटाए गए जीपीएस डाटा और कॉर्डीनेट्स की जांच एसआईजी कराची के विश्लेषक ने की. उसने निष्कर्ष निकाला कि आरोपी अमीन सादिक़ द्वारा पहचाने गए अज़ीज़ाबाद के कैंप और गुलशन-ए-ग़ज़ाली, बाग़-ए-रफ़ी, शाह फ़ैसल टाउन, कराची में स्थित चार आरोपियों के घरों में गए थे.
- ओकारा और मुल्तान में अजमल कसाब और अमजद ख़ान के बारे में जांच के दौरान नई बातें सामने आईं. कहा गया था कि मारे जाने वालों में एक इमरान बब्बर वल्द शहाबुद्दीन (मुल्तान) भी था. राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के एनडीए मिलाने से यह साबित हो गया कि शहाबुद्दीन मुंबई में मारे गए आतंकवादी इमरान बब्बर का पिता था.
- भारत ने सात फिंगरप्रिंट्स भी भेजे. उनमें से एक का निशान मोहम्मद अल्ताफ़ वल्द नाज़िर अहमद से मिलता हुआ था. डीएनए जांच में यह साफ हो गया कि नाज़िर अहमद मुंबई में मारे गए आतंकी अब्दुर रहमान छोटा(असल नाम मोहम्मद अल्ताफ) के पिता हैं.
- भारतीय सरकार से मिले जीपीएस डाटा को इंस्पेक्टर एसआईजी कराची भेजा गया. उन्होंने गूगल अर्थ की जांच की और दिए गए ठिकानों को ए) कराची बंदरगाह पर खड़ी अल-फौज बोट, बी) नाव पर काम करने वाले आरोपित के घर, सी) अमीन सादिक़ का घर, डी) कराची का लश्कर ट्रेनिंग कैंप, ई) लश्कर का थाथा स्थित कैंप, और एफ) नावों के रूप में उनकी पहचान की है.
- कराची में हुई जब्ती के बाद - जिसमें यामाहा मोटर इंजन(नं. 1020015)- जिसे मुंबई में पकड़ा गया था और अमजद और शाहिद जमील रिआज़ ने ख़रीदा था-लश्कर के छुपने के ठिकानों और प्रशिक्षण केंद्रों के पते से मिली चीज़ें- लश्कर के आतंकियों से बरामद छोटी नावें इंजन और क्रीक -ये सब कुछ थाथा कैंप के पास बरामद हुए थे -और आतंकियों की जीपीएस रिकार्डिंग, शाहिद रिआज़, अमीन सादिक़ के साथ लश्कर के वित्तीय प्रबंधकों के रिकार्ड और आरोपियों के सेलफोन रिकार्ड बताते हैं कि उन्हें भारत के आतंकियों ने भी फोन किए. जांच से यह बात भी पता चलती है कि लश्कर के छुपे हुए आतंकी जिनका नाम चार्जशीट में आया है-जैसे अमजद ख़ान, शाहिग घटूर, मोहम्मद उस्मान, अतीक-उर-रहमान, अब्दुल रहमान, मोहम्मह सफीर सल्फी, मोहम्मद नईम, अब्दुल शकूर, मोहम्मद मुश्ताक़, शकील अहमद और उनके सहयोगियों ने-मिलकर इस पूरी कार्रवाई के हर पहलू को अंजाम दिया. इसके साथ मिले सबूत ज़ाकिर- उर-रहमान लखवी, मज़हर इक़बाल और अब्दुल वाज़िद को भी इस षड्यंत्र से जोड़ते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिन्दी का पहला साप्ताहिक अखबार

आर एन आई रजि.न.45843/86

वर्ष 23 अंक 21, 3 अगस्त-9 अगस्त 2009

प्रधान संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन
चौधरी बिल्डिंग
कनाट प्लेस
नई दिल्ली 110001

फोन न.
संपादकीय +91 011 47149999
विज्ञापन +91 011 47149916
प्रसार +91 011 47149905
फैक्स न. +91 011 47149906

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

आतंकवाद के ख़िलाफ़ सरकार की हवाई योजनाएं

■ गठन के साथ ही दम तोड़ रही राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी

रूबी अरूण

आतंक का साया सिर पर बुरी तरह मंडरा रहा है, लेकिन सरकार की लालफीताशाही अपनी जगह क़ायम है. देश आतंकी ख़तरे से चौतरफा घिरा है. इंटेलीजेंस ब्यूरो की दी हुई चेतावनी देश की सुरक्षा और संरक्षा के लिहाज़ से बेहद ख़ौफ़नाक है. पर सरकार की जड़ता बरकरार है. देश की सुरक्षा और आतंक से निपटने के मसले पर घोषणाएं होती रही हैं और घोषणाएं हो रही हैं. पर उन पर अमल के नाम पर कैसे मज़ाक किया जा रहा है, इसकी बानगी देखिए. मुंबई हमलों के बाद बड़े ही ताम–झाम और शोर–शराबे के बीच देश के गृहमंत्री ने नेशनल इनवेस्टिगेटिव एजेंसी (एनआईए) के गठन की घोषणा की. गृह मंत्रालय के एक आला अधिकारी बताते हैं कि इस एजेंसी के गठन को लेकर तत्कालीन यूपीए सरकार और ख़ुद गृहमंत्री पी चिदंबरम इतने उत्साहित थे कि एजेंसी के गठन का पूरा प्रारूप, उसका मसौदा सब कुछ उन्होंने ख़ुद ही ड्राफ्ट किया. इरादा ज़ाहिर किया गया कि अमेरिका के एफबीआई की तर्ज़ पर एनआईए की संरचना होगी. एकबारगी लगा, जैसे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा. एनआईए के पहले चीफ की नियुक्ति में भी काफी सतर्कता बरती गई. गृहमंत्री की पसंद के मुताबिक जम्मू–कश्मीर काडर के सुयोग्य अधिकारी राधा विनोद राजू को इस पद की महती ज़िम्मेदारी दी गई. अब मुश्किल आई कि एनआईए चीफ का दफ्तर कहां पर हो. उनके पद की गरिमा और महत्ता के मुताबिक कौन सी जगह आवंटित की जाए. उनका अमला कहां से कामकाज करे.

हालांकि सवाल अनसुलझा ही रहा. कुछ दिनों तक तो आर वी राजू नार्थ ब्लाक में ही इधर–उधर टहलते रहे. फिर तरस खाकर उन्हें गृह मंत्रालय में ही एक कोना पकड़ा दिया गया. उनके मातहतों के लिए हालांकि कोई जगह नहीं मिली. कुछ ही दिनों बाद एनआईए चीफ की उपस्थिति गृह मंत्रालय के बाबुओं को अखरने लगी. वैसे एनआईए का अमला भी बढ़ने लगा था. लिहाज़ा तय किया गया कि एनआईए का दफ्तर कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए. जगह की तलाश तो हुई, पर बेमन से. कोई इमारत या मकान नहीं मिला. मिला तो एक होटल. सोचिए ज़रा. देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, नेशनल इंवेस्टिगेटिव एजेंसी, जिस पर दारोमदार है देश को आतंकी हमलों से बचाए रखने का, आतंकवादियों पर नकेल कसने का, वह गठन के बाद से ही दूसरों की मोहताज़ है. इतने बड़े देश की सबसे अहम जांच एजेंसी, पर उसका ठिकाना सुरक्षा और गोपनीयता के लिहाज़ से सबसे घटिया जगह पर– होटल सेंटूर में, जो दिल्ली के महिपालपुर में अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास है और जिसे स्टार प्लस के टूरिज़्म वेबसाइट ने सबसे गंदा होटल करार दिया है. उसके कमरा नंबर 3084 से लेकर 3097 तक कुल 14 कमरों में चल रही है यह एजेंसी. देश को सुरक्षित रखने का आश्वासन देने वाली एजेंसी ख़ुद ही सुरक्षा की मोहताज़ है. न तो माकूल स्टाफ हैं न ही ज़रूरी तकनीकी उपकरण. न तो आवश्यक साज़ो सामान ही हैं. फौरी तौर पर कम से कम 123 पदों की मंज़ूरी दी गई है, पर हैं कुल आधे भी नहीं. मूलभूत ढांचे के लिए ज़रूरत करोड़ों की है, पर मिले सिर्फ़ 50 लाख रुपये.

> **मुंबई हमलों के बाद बड़े ही ताम–झाम और शोर–शराबे के बीच देश के गृह मंत्री ने नेशनल इनवेस्टिगेटिव एजेंसी (एनआईए) के गठन की घोषणा की. गृह मंत्रालय के एक आला अधिकारी बताते हैं कि इस एजेंसी के गठन को लेकर तत्कालीन यूपीए सरकार और ख़ुद गृह मंत्री पी चिदंबरम इतने उत्साहित थे कि एजेंसी के गठन का पूरा प्रारूप, उसका मसौदा सब कुछ उन्होंने ख़ुद ही ड्राफ्ट किया.**

राधा गोविंद राजू

केपीएस गिल

अब चूंकि कहने को एक एजेंसी बना दी गई है, लिहाज़ा उसे कुछ काम भी तो करना है. इसलिए खानापूरी के लिए उसे तीन केस भी पकड़ा दिए गए हैं. मई 2009 में असम में हुए दो आतंकी वारदातों की और इसी साल मई में मुंबई में फ़र्ज़ी नोटों के पकड़े गए जखीरे की. यह इसलिए कि अगर कोई सवाल करे तो यह कहने को तो हो कि एजेंसी मशरूफ़ है. एक कड़वा सच यह भी है कि अधिकारीगण भी एनआईए आना नहीं चाह रहे. न ही सरकार ऐसे बेहतर हालात पैदा कर रही है कि पुलिस अधिकारियों का रुझान एनआईए की ओर बढे. एनआईए के बोर्ड में अभी तक सिर्फ़ 45 अधिकारी हैं, जबकि 95 प्रस्तावित हैं. इनमें आईपीएस अधिकारियों की संख्या सिर्फ़ सात है. वहीं वारदातों की जांच कर रहे विशेषज्ञों की भी घोर कमी है. इसी बीच एनआईए का कार्यालय सीबीआई मुख्यालय से भी चला गया. गृह मंत्रालय से आश्वासन यही मिला है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद स्थायी कार्यालय मिल जाएगा.

यह घोर लापरवाही तब है जब आईबी बार–बार सरकार को चेता रही है. आईबी द्वारा गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र के मुताबिक, भारत की जड़ों को कमज़ोर कर विश्व पटल पर भारत की छवि एक बेहद कमज़ोर देश के रूप में दिखाने की ख़ातिर लश्करे तैयबा ने तटीय क्षेत्रों पर स्थित उद्योगों, पर्यटन क्षेत्रों और प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की तैयारी पूरी कर ली है. ख़ास तौर पर गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा जैसे तटीय इलाक़ों में आतंकी संगठन अपना जाल बिछा चुके हैं. यह इसलिए कि पर्यटकों और विदेशी निवेशकों के लिए भारत को असुरक्षित देश के रूप में पेश कर सके. यक़ीनन यह स्थिति भारत के आर्थिक ढांचे की कमर तोड़ने के लिए काफी होगी. हालात पर ग़ौर करें तो यह बात आईने की तरह साफ होती है कि सरकार एनआईए के अस्तित्व को लेकर ही गंभीर नहीं है. यह कोशिश विपक्षियों के हमलों को रोकने भर की ही थी. इसीलिए यह तय किया गया कि एनआईए मुंबई ब्लास्ट या पहले हुए किसी भी आतंकी वारदात की जांच नहीं करेगी. मतलब यह कि आतंक से देश की रक्षा करने का नहीं बल्कि सरकार की ख़ामियों को छुपाने का एक ज़रिया भर है एनआईए.

ruby@chauthiduniya.com

नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) का हाल भी बदतर

आतंकी वारदातों से निपटने के मामले में बेहद प्रतिष्ठित नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी सरकार की घोर लापरवाही का शिकार है. मुंबई पर हुए आतंकी हमले के बाद भी सरकार की काहिली गई नहीं है. एनएसजी के पास भी संसाधनों की भारी कमी है. इस सैन्य बल के जवानों को मामूली सी चीज़ें भी मुहैया नहीं हैं. गृह मंत्रालय ने मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई में एनएसजी के हब तो बना दिए हैं पर उसे संसाधनों से लैस नहीं किया है. न ही कोई विशिष्ट उपकरण ही दिए गए हैं. ऐसे शर्मनाक हालात हैं कि एनएसजी जैसे विशिष्ट सैन्य बल को भी अत्यंत ज़रूरी चीज़ें हासिल करने की ख़ातिर टेंडर की भारी भरकम प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है. इस प्रक्रिया में कम से कम 6–7 महीने लग जाते हैं. अगर इस बीच देश पर आतंकी हमला होता है तो फिर भगवान ही मालिक है. एनएसजी में इन कमियों का ख़ामियाज़ा मुंबई हमलों के वक़्त भुगतना पड़ा था. आठ आतंकियों पर क़ाबू पाने में उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी. इस सैन्य बल के पास घुटनों तक पहनने वाले जूते नहीं हैं. न ही वे हैंड फ्री रेडियो ही हैं जिसके ज़रिए आपातकालीन स्थितियों में ये आपस में बात कर सामंजस्य बना सकें और दुश्मनों पर फतह हासिल कर सकें. स्टेन ग्रेनेड, रात के वक़्त देखने वाले उपकरण, ब्लास्ट प्रूफ आइवेयर, बुलेट प्रूफ जैकेट– इन सबकी घोर कमी है. और तो और, इनके पास अपना हेलीकॉप्टर तक नहीं है. किसी आपदा में ये आनन–फानन में एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकते. पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक के पी एस गिल साफ कहते हैं कि सरकारें आतंकवाद को ख़त्म करने की महज़ बड़ी बड़ी बातें करती हैं. उसका मक़सद नहीं होता. वरना आतंकवाद से निपटने के लिए चारों शहरों में जो हब बनाए गए हैं उन्हें ज़रूरी संसाधनों से लैस भी कर दिया जाता. इन हबों का मक़सद यही है कि कहीं कोई आतंकी हमला होता है तो एनएसजी कमांडो वहां जल्द से जल्द पहुच सकें. पर उनके पास संसाधन नहीं हैं. वैसे भी एनएसजी का ज़्यादा इस्तेमाल तो होता नहीं. जिस शहर में ये हब बने है वहां भी अगर कोई वारदात होती है तो ट्रैफिक वग़ैरह की मुश्किलें पेश आएंगी. इससे तो बेहतर यही था कि सरकार हब बनाने में लगे करोड़ों रूपयों से स्थानीय पुलिस का आधुनिकीकरण करती. बात बिल्कुल सही है. एनएसजी जैसे सुरक्षा बलों की ज़रूरत तब पड़ती है जब आतंकी कहीं फंस गए होते हैं या फिर उनके ख़िलाफ़ मोर्चा लेना पड़ता है. पिछले दिनों सिर्फ़ गांधीनगर और मुंबई में ही एनएसजी के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ी. पंजाब के आतंकवाद से दो–दो हाथ करने वाले राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक और सुरक्षा सलाहकार सी पाल सिंह कहते हैं कि आतंकवाद से निपटने के लिए 20 साल पहले भी देश में यूनिफाइड कमांड बनाई गई थी. इसे कश्मीर, असम और मणिपुर में लागू कर के देखा गया था, पर नतीजा सिफ़र निकला. यूनिफाइड कमांड में पुलिस और पैरामिलिट्री समेत सभी सुरक्षा बल सेना के नीचे काम करते हैं. जब इसका गठन किया गया था तो यह सोच थी कि सेना के अंदर आने से सभी बलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सकेगा. ऐसा हो ही नहीं सका. उलटे इसका नुक़सान ही देखने को मिला. एक तो सेना के अधीन आने से पुलिस बेकार सी होने लगी. उस पर से लोगों का विश्वास उठने लगा था. चुकि सेना की आदत ही नहीं है कि वह जनता से सीधे ताल्लुक रखे, लिहाज़ा लोगों से भी दूरियां बढ़ने लगीं. ज़ाहिर है, एनएसजी के प्रति सरकार अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं करती है और उसका सही इस्तेमाल नहीं करती है तो यह सैन्य बल भी निष्प्रभावी होने को अभिशप्त हो जाएगा.

फोटो–प्रभात पाण्डेय

देश की सुरक्षा पर हावी लालफीताशाही

अब भारत सरकार की लालफीताशाही के कुछेक करतब और देखिए. संसद ने फरवरी के आख़िरी हफ्तों में प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउन्डरिंग बिल तो पास कर दिया, पर क़ानूनों में संशोधन कर उसे फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स के मुताबिक नहीं बनाया. एफएटीएफ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो मनी लाउन्डरिंग और टेरर फंडिंग के ख़िलाफ़ नीतियां बनाता है. यूएस के सुरक्षा विशेषज्ञों ने भारत को साफ शब्दों में यह चेतावनी दी है कि पाकिस्तान समर्थित लश्कर ए तैयबा ग्लोबल जिहादीस्ट सिंडिकेट की मदद से अमेरिका के साथ–साथ भारत को भी नेस्तनाबूद करने के मंसूबे संजो रहा है. ऐसी सनसनीखेज़ सूचना भी सरकार के लिए कोई ख़ास महत्व नहीं रखती. और तो और, मुंबई हमलों से निबटने में जो ख़ामियां उजागर हुई हैं, उनसे भी सरकार ने सबक़ नहीं लिया है. हमले के बाद केंद्र सरकार ने शहरी आतंकवाद से निबटने के लिए एक नई विशेष कमांडो फोर्स के गठन पर विचार ज़रूर शुरू किया था. प्रधानमंत्री कार्यालय में दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा. तय किया गया कि स्पेशल कमांडो फोर्स में नौसेना, वायुसेना और थल सेना के कमांडो के अलावा एनएसजी के कमांडो को शामिल किया जाएगा. लेकिन आज तक हुआ कुछ नहीं. गृह मंत्री पी.चिदंबरम ने राष्ट्रीय सुरक्षा का ढांचा मज़बूत करने के लिए सात सूत्रीय योजना घोषित की थी. इनमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना, जिसके पास अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय अपराधों की जांच की विशेष शक्ति होगी, तटीय समुद्री क्षेत्र में सघन गश्त के लिए कोस्ट गार्ड के तहत एक तटीय कमान की स्थापना, आतंकवाद विरोधी क़ानून बनाना और फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना करना, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना करना, नागरिक विमानन और वायुसेना के प्राधिकरणों द्वारा देश के आकाश में हर तरह के विमानों पर लगातार नज़र रखने की व्यवस्था, ख़ुफ़िया ढांचे को मज़बूत बनाना, राज्य पुलिस की कमांडो यूनिटों को विद्रोही और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने में दक्ष बनाने के लिए बीस नए स्कूलों की स्थापना करना वग़ैरह शामिल था. शर्म और तकलीफ़ की बात तो यह है कि इनमें से ज़्यादातर घोषणाएं आज भी फाइलों की शोभा बनी हुई हैं. तय यह भी हुआ था कि देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों नेवी, कस्टम, सीमा शुल्क, कोस्टल गार्ड और राज्य पुलिस विभागों में तालमेल होगा और सभी अपनी ख़ुफ़िया सूचनाओं को साझा करेंगे. पर आज तक इस आदेश पर अमल शुरू नहीं हुआ. सरकार ने तटीय सुरक्षा की ज़िम्मेदारी पूरी तरह नौ सेना को सौंप दी . यह घोषणा भी कर दी गई कि कि नौसैनिक संसाधनों और नौसैनिक अड्डों की रक्षा के लिए अलग से एक हज़ार विशेष प्रशिक्षित जवानों वाले सागर प्रहरी बल नाम की नई फोर्स का गठन किया जाएगा. योजना यह भी बनी कि कोस्ट गार्ड के जवानों की तादाद में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी. पर ये सारे प्रस्ताव बस ज़ुबानी जमा–ख़र्च बन कर रह गए. इतना बड़ा आघात झेलने के बाद समुद्री सुरक्षा एजेंसियों मसलन नौसेना और तटरक्षक बल के पोतों, हेलीकॉप्टर, नौकाओं, विमानों और मानव संसाधनों को भी बढ़ाने का फ़ैसला लिया गया था, पर यह सब कुछ वक़्ती ही साबित हुआ. सरकार इस मसले पर कितनी गंभीर है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 26 नवंबर 2008 को इतना बड़ा झटका झेलने के बाद भी समुद्री और तटीय सुरक्षा संबंधी बड़ी योजना को हरी झंडी फरवरी 2009 के आख़िर में मिली. मुंबई पर हमले के बाद समुद्री निगरानी का ज़िम्मा मुंबई पुलिस से लेकर कोस्ट गार्ड को दे दिया गया है. मुंबई पुलिस समुद्री सीमा में ज़ीरो नाटिकल से 12 नाटिकल माइल्स तक निगरानी किया करती थी. 12 से 200 नाटिकल माइल्स से आगे की समुद्री सुरक्षा की ज़िम्मेदारी कोस्ट गार्ड के पास थी. गृह मंत्रालय की सिफ़ारिश पर यह क़दम उठाया गया. यह कहते हुए कि समुद्री सीमा में चुस्त चौकसी करने की ख़ातिर ज़रूरी संसाधन मुंबई पुलिस के पास नहीं हैं. तो क्या सरकार को यह बात पहले नज़र नहीं आई थी? क्या सरकार इसकी ख़ातिर मुंबई हमले का इंतज़ार कर रही थी? जबकि मुंबई पुलिस पहले भी कई बार कह चुकी थी कि उसके पास समुद्री सुरक्षा के लिए वे उपकरण नहीं हैं जो कोस्ट गार्ड या नेवी के पास हैं. न ही उसके पास कोस्ट गार्ड की तरह के बोट हैं जो प्रति घंटा 40 नाटिकल माइल्स की रफ्तार से चल सकें. सबसे बड़ी बात कि मुंबई पुलिस समुद्री सुरक्षा के मामले में प्रशिक्षित भी नहीं. इसके अलावा, भारतीय समुद्र में विचरण कर रहे विभिन्न पोतों के बारे में पूरी जानकारी रखने के लिए एक नेशनल कमांड, नेशनल कंट्रोल, कम्यूनिकेशन और इंटेलिजेंस नेटवर्क स्थापित करने की निहायत ज़रूरत भी बताई गई थी, जो दिल्ली स्थित नौसेना और कोस्ट गार्ड के आपरेशंस रूम से जुड़ा रहे. यह काम भी अधर में ही लटका हुआ है. सरकार ने समुद्री सुरक्षा एजेंसियों मसलन नौसेना और तटरक्षक बल के पोतों, नौकाओं, हेलीकॉप्टर, विमानों और मानव–संसाधनों की तादाद बढ़ाने का भी फ़ैसला किया था. सारी घोषणाएं हवा–हवाई साबित हुईं. वर्ष 2000 में ही वोहरा कमिटी ने करगिल रिपोर्ट की रोशनी में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर अधिकारियों का एक अलग कैडर बनाने की अनुशंसा की थी. उसका कहना था कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कैबिनेट सेक्रेटेरियट, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल सेक्रेटेरियट आदि के लिए अधिकारी इसी कैडर से ही लिए जाएं. पर अभी तक इस अनुशंसा पर ग़ौर ही नहीं किया गया. हैरतअंगेज़ तथ्य तो यह भी है कि ये सारी बातें विपक्ष के लिए कोई मुद्दा नहीं. क्यों नहीं ख़ुफ़िया तंत्र को अभी तक आधिकारिक निर्देश मिले हैं कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमिटी को नियमित रूप से हर पखवारे महत्वपूर्ण जानकारियों से रूबरू कराए? अभी तो यही स्थिती है कि जब मुसीबत सिर पर होती है तभी ख़ुफ़िया एजेंसियां राष्ट्रीय नेतृत्व को ख़बर करती हैं. जब तक हम कुछ करने की स्थिती में आते हैं, तब तक वारदात हो चुकी होती है और हम बेबस खड़े लकीर पीटते नज़र आते हैं.

भारत में भी होंगी बेहतरीन सड़कें : परिवहन सचिव

देशभर में सड़कों और राजमार्गों के फैलाव की ज़िम्मेदारी वाले जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अभी सबकुछ बेहद तेज़ी से हो रहा है. इस पूरे काम की ज़िम्मेदारी है मंत्रालय के सचिव ब्रह्मदत्त पर, जिनकी काम की गति उनके मंत्रालय जैसी ही तेज़ है.

कर्नाटक काडर के 1973 बैच के आईएएस ब्रह्मदत्त एक विधि स्नातक हैं और उनके पास इकॉनोमिक्स और फीजिक्स में मास्टर्स डिग्री हैं. वे टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स के अध्यक्ष भी हैं. ट्रक हड़ताल ख़त्म कराने के दौरान अपनी अहम भूमिका के कारण चर्चित रहे ब्रह्मदत्त से **अंज़ुम ए जैदी** और **एस रिज़वी** की बातचीत के प्रमुख अंश–

आप जिस मंत्रालय में हैं, उसमें नए मंत्री आए हैं. आपकी वर्तमान प्राथमिकताएं और फोकस क्या हैं?

हमारा सबसे प्रमुख फोकस विश्वस्तरीय सड़कें बनाना है और वह भी तेज़ गति से. परिवहन के मामले में सुधार का एक विस्तृत एजेंडा है.

सड़क परिवहन के क्षेत्र में इन सुधारों की लंबे समय से ज़रूरत रही है. हमारा लक्ष्य है कि हम देश में लोगों और पर्यटकों के परिवहन को आसान और आरामदायक बना सकें. इसी तरह माल ढुलाई में भी सुधार की ज़रूरत है, ताकि माल देश के एक हिस्से से दूसरे में आसानी से आ–जा सके.

राष्ट्रीय परमिट और टूरिस्ट परमिट की वर्तमान व्यवस्था पर ध्यान देने की ज़रूरत है. तेज़ी और आसानी से परिवहन में इससे बड़ी परेशानी पैदा होती है. हालांकि यह राज्यों का विषय है, फिर भी हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है. हम मोटर वेहिकल्स एक्ट में संशोधन की बात भी सोच रहे हैं.

इस तरह के सुझाव आए हैं कि केंद्र सरकार को अपनी अथॉरिटी बनानी चाहिए, जो नेशनल परमिट देने का काम करे. ऐसा एक प्रस्ताव है कि केंद्र एक जगह से ही नेशनल परमिट का टैक्स वसूले और उसे राज्यों में बांट दे.

इस मामले में कई बैठकें हुई हैं जिनमें ट्रकर्स कमिटी और राज्य परिवहन सचिवों, राज्य परिवहन कमिश्नरों, राज्य वित्त सचिवों ने भाग लिया और सर्वसम्मति से यह कहा कि केंद्र सरकार को नेशनल परमिट पर चल रहे ट्रक का टैक्स वसूलना चाहिए और देश में कहीं भी जाने की अनुमति होनी चाहिए. फ़िलहाल नेशनल परमिट का मतलब चार राज्य ही हैं. कुछ और मुद्दे भी हैं, जैसे राज्यों की कमाई में कमी, इन पर विचार चल रहा है.

टूरिस्ट परमिट पर क्या चल रहा है?

इस मामले में मुश्किलें ज़्यादा हैं क्योंकि हर राज्य के अपने नियम हैं. टूरिस्ट वाहनों की संख्या मालवाहकों से काफी कम है. इस मामले में पर्यटन विभाग के साथ अंतर–मंत्रालय बैठक हो चुकी है. उन्होंने भी टूरिस्टों के लिए बिना परेशानी के यात्रा का अनुरोध किया है. जयपुर, दिल्ली और आगरा में पायलट आधार पर एक प्रोजेक्ट चलाने का अनुरोध भी किया गया है.

अभी टूरिस्ट बसों को दो–दो बार सीमाओं पर रुकना पड़ता है. हम पायलट आधार पर जो प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं. उसमें एक ही बार में सभी जांचों की व्यवस्था होगी.

एक्सप्रेस– वे का एक राष्ट्रीय ग्रिड बनाने की बात हुई थी, उसमें कहां तक विकास हुआ है?

हां, काफी विकास हुआ है. एक्सप्रेस– वे का एक राष्ट्रीय ग्रिड तैयार हो रहा है. इस के लिए सलाहकार एक साल पहले ही नियुक्त हुए थे और उन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट दे दी है. आख़िरी रिपोर्ट की तैयारी हो रही है. जब एक्सप्रेस–वे का एक राष्ट्रीय ग्रिड तैयार हो जाएगा, तब हम राष्ट्रीय राजमार्गों पर ध्यान देंगे. इसमें ऐसे उपाय होंगे जिनसे से टूरिस्ट और माल परिवहन का रास्ता आसान हो जाएगा. उन्हें कई चेकपोस्ट्स से गुज़रने के बजाय बस एक बार आने और जाने के समय एक्सप्रेस–वे और राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाज़ा पर टैक्स देने के लिए रुकना होगा. इससे उन्हें काफी लाभ भी होगा.

आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं को ऐसे एक्सप्रेस–वे की ज़रूरत है. 4 से 6 लेन में चौड़ा करना तो ज़रूरी है ही, पूरे देश में इसके नेटवर्क को फैलाना भी ज़रूरी है.

सुरक्षा उपायों पर आपकी क्या राय है?

परिवहन क्षेत्र में मोटर वेहिकल्स एक्ट में संशोधन के अलावा कमिटी ने कई और बदलावों की अनुशंसा की है. ये बदलाव राजमार्गों और एक्सप्रेस–वे पर सुरक्षा से जुड़े हैं. शराब पीकर वाहन चलाने और बीमा नीति में बदलाव की ज़रूरत है. ग़लत तरीक़े से वाहन चलाने वालों पर हमें कड़ी कार्रवाई करनी होगी. इस प्रस्ताव को तैयार कर लिया गया है और संसद में संबंधित विधेयक जल्द ही आएगा.

कहा जाता है कि राजमार्गों पर बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, आपात सेवा के बारे में क्या विचार हैं?

यूं तो सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, हम आपात सेवा की ज़रूरत के बारे में भी खुले दिमाग़ से सोच रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले साल इस योजना के तहत ट्रॉमा सेंटर्स के लिए 600 करोड़ रुपये दिए थे. हम राजमार्गों के किनारे 100 ट्रॉमा सेंटर्स बनाने की सोच रहे हैं. भूतल परिवहन मंत्रालय की ओर से 20 करोड़ रुपये की मदद से 100 एंबुलेंस उतारने की भी योजना है. हम चाहते हैं कि हर पचास किलोमीटर में एक एंबुलेंस रहे, और भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी उन पर नज़र रखे. हमने निजी अस्पतालों से बैठक कर उनके साथ तालमेल बैठाने की कोशिश की है. हमें बीमा नियम में भी बदलाव करने होंगे.

सड़कों के बारे में क्या कहेंगे? क्या हम विश्व स्तरीय सड़कों के लिए तकनीक आयात कर रहे हैं?

हां, बेहतर सड़कों के लिए तकनीक के आयात पर कोई बंधन नहीं है. अगर वे हमारे उद्देश्य को पूरा करते हैं और अपने देश में उन्हें मान्यता मिली हुई हो, तो आयात किए जा सकते हैं.

साथ ही वाहनों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है. 1947 में संख्या तीन लाख थी और आज 14 करोड़ है. सबसे बड़ी प्राथमिकता सड़क की स्थिति और अच्छी सड़कों की संख्या को बढ़ाना है. हमारे पास एक मानक है जिससे सड़क बनाने की तकनीक और सामग्री का स्तर तय होता है.

सड़क निर्माण का आपका लक्ष्य कितना बड़ा है?

हमारे पास राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत 70000 किलोमीटर सड़कें हैं, इनमें से 30000 राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी के पास हैं. इनमें से 6000 तो 4 से 6 लेन की बनाई जाएंगी.

राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी यह भी है कि वह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत सभी राज्यों की राजधानियों को जोड़े . यह 12000 किलोमीटर है और कई महत्वपूर्ण पर्यटन और धार्मिक जगहें इन पर स्थित हैं.

feedback@chauthiduniya.com

भारत में व्यावसायिक न्यायालयों की स्थापना, क्यों और कैसे

वैश्वीकरण और विदेशी निवेश

निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण ने हमारी अर्थव्यवस्था को मज़बूती दी है. वाणिज्य और व्यापार के तेज़ी से बढ़ने से व्यावसायिक विवादों के मामलों में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है. जब तक इनसे तेज़ और असरदार तरीक़े से निपटने के लिए एक नए और प्रभावी तंत्र की व्यवस्था नहीं होती, तब तक यह हमारे विकास में रोड़ा बनता रहेगा. भारत में आनेवाले विदेशी निवेशकों को यह भरोसा होना चाहिए कि भारतीय अदालतें उतनी ही तेज़ हैं, जितनी कि विश्व के विभिन्न विकसित देशों की अदालतें. और, अब यहां भी न्यायिक प्रक्रिया में लंबा समय नहीं लगता. कई देशों ने अपने यहां न्यायिक फ़ैसलों की प्रक्रिया में व्यावसायिक मामलों के लिए एक अलग शाखा बनाने का विचार अपनाया है. हालांकि उनमें थोड़ा–बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात व्यावसायिक शाखा को अलग करने का विचार ही है. व्यावसायिक अदालतें वर्तमान न्यायिक व्यवस्था से अलग नहीं हैं, बल्कि उसी की एक नई शाखा हैं. ये वे न्यायालय हैं जहां आर्थिक महत्व वाले मामलों का निपटारा होगा और जहां उन अदालतों से बड़े पैमाने पर कार्रवाई करेंगे, जहां आम तौर पर ये मामले दर्ज़ होते हैं. विभिन्न देशों में इस तरह के न्यायालयों में आर्थिक मामलों के जानकार जज नियुक्त होते हैं. इन न्यायालयों में मामले का निपटारा काफी तेज़ी से होता है. साथ ही इन न्यायालयों में सबसे ऊंचे स्तर की सुविधाएं मौजूद होती हैं.

अमेरिका और इंग्लैंड के न्यायालयों की अवधारणा

अमेरिका और इंग्लैंड के न्यायालयों में भारत में न्यायिक मामलों के निपटारे में देरी की धारणा है. इस वजह से इस व्यासायिक शाखा का गठन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि यह व्यवसायिक शाखा उच्चस्तरीय आर्थिक मामलों का निपटारा फास्ट ट्रैक अदालतों की तर्ज़ पर सभी आधुनिक और ज़रूरी सुविधाओं के साथ करे. अगर एक बार ऐसा हो गया तो विदेशी अदालतों की भारतीय अदालतों में फ़ैसले में होने वाली देरी की धारणा नहीं रहेगी.

भटनागर बनाम सुरेंद्र ओवरसीज लिमिटेड (1995)(52 एफ.2.डी. 1220) (थर्ड सर्किट), का मामला अपीलों के तीसरे सर्किट कोर्ट का है (इस मामले का उल्लेख अब अमेरिका में मामलों की सुनवाई के दौरान अक्सर किया जाता है). जज लेविस ने प्रो. मार्क गैलेंटर और शार्दूल श्रॉफ (एक भारतीय वकील) के शपथपत्र का हवाला दिया, जिसमें दोनों ने खेदपूर्वक यह बात कही थी कि भारतीय न्यायालयों की व्यवस्था ढहने के कगार पर है. जज लेविस ने उनके शपथपत्रों को स्वीकार किया और जिला कोर्ट के अमेरिका में ही सुनवाई के फ़ैसले को सही ठहराया. उन्होंने कहा कि जिला कोर्ट ने यह पाया कि भारतीय न्याय व्यवस्था में काफी मामले लंबित पड़े हैं. अगर यह मुकदमा भारत में दर्ज होगा तो इससे निपटने में 25 वर्ष भी लग सकते हैं. भटनागर केस के संदर्भ में पाइपर एयरक्राफ्ट (1981 454 यूएस 235) का हवाला देते हुए कहा गया कि मामले के निपटारे में इस तरह की देरी अमेरिकी अदालतों में भी होती है और दो या ढाई वर्ष की देरी को समझा जा सकता है. जज लेविस ने कहा कि अगर उपचार इतनी देर से मिले कि वह किसी काम का न रहे तो वह उपचार नहीं है. भटनागर मामले में, अमेरिका में भारतीय प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन (स्टे के लिए आवेदन दिया गया था) को ज़िला कोर्ट ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि अगर इस मामले को कोलकाता हाईकोर्ट स्थानांतरित कर दिया जाए तो इस मामले के निपटाने में 15 से 20 वर्ष लग सकते हैं और उसके बाद पांच वर्ष से अधिक अपील करने में लगेगा. थर्ड सर्किट कोर्ट ने भी इस राय की पुष्टि की. यूनाइटेड किंगडम (यूके)की अदालतों में हाल में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण फ़ैसले, अमेरिकी कोर्ट द्वारा दिए गए फ़ैसलों के जैसे ही हैं. इनमें भी भारतीय अदालतों की देरी के बारे में कहा गया है. यूरोपियन एशियन बैंक बनाम पंजाब एंड सिंध बैंक (1982) लायड्स रिप 356(सीए) के मामले में, कहा गया था कि साफ है कि इंग्लैंड की तुलना में न तो भारत और न ही सिंगापुर सुनवाई की कार्यवाही के लिए ठीक हैं. इस मामले में, वादी वेस्ट जर्मन बैंक ने इंग्लैंड में भारतीय बैंक के ब्रांच ऑफिस के खिलाफ एक क्रेडिट लेटर पर भुगतान के मामले में रिट याचिका भेजकर कार्रवाई की. प्रतिवादी द्वारा इस मामले में दायर स्टे आवेदन को खारिज़ कर दिया गया था और यह केस इस आधार पर यूके में चलता रहा था कि भारतीय अदालत में फ़ैसले में देर लगती है. कुछ इसी तरह की राय विष्णु आभा (1990)(2)(लायड्स रिप. 312) के मामले में भी अपनाया गया था. विश्वास अजय (1986) (लायड्स रिप. 558) के मामले में भी यह मान लिया गया था कि भारत में मामले की सुनवाई शुरू होने में 10 साल का समय लग जाता है और यह न्याय नहीं है. प्रतिवादी के आवेदन को खारिज़ करते हुए यह मामला इंग्लैंड के न्यायालय में ही चला.

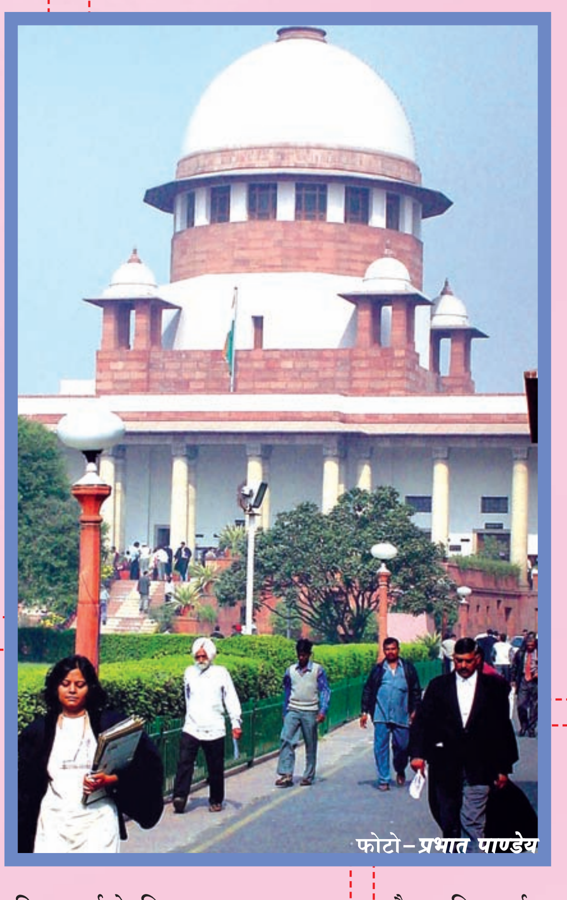

फोटो–प्रभात पाण्डेय

संविधान में प्रावधान

सूची तीन के 11–ए में प्रविष्टि–3 में दिए गए न्याय की व्यवस्था और सूची एक की प्रविष्टि–78 में दी गई हाईकोर्ट के संविधान और उसके संगठन की व्याख्या के संदर्भ में हाई कोर्ट में व्यावसायिक मामलों (जो एक करोड़ से अधिक के हों) की सुनवाई के लिए एक अलग शाखा की व्यवस्था संसद के द्वारा की जा सकती है या अलग से एक फास्ट ट्रैक व्यवस्था भी की जा सकती है. साथ ही जहां तक हाई कोर्ट एकल और बहुसदस्यीय खंडपीठ के सामने लंबित मामलों की बात है तो संसद यह व्यवस्था कर सकती है कि इन मामलों को व्यावसायिक शाखा द्वारा एक फास्ट ट्रैक अपील प्रक्रिया द्वारा निपटाया जाए. इसे हाई कोर्ट के नियमों के द्वारा या पूर्णन्यायालय के प्रस्ताव के द्वारा ही करना जरूरी नहीं है. अनुच्छेद 225 में दिए गए उपयुक्त विधेयन के मुताबिक क़ानून के विषयानुसार यह संसद के द्वारा किया जा सकता है. इसी तरह मुख्य न्यायाधीश की जजों को काम सौंपने की शक्ति को भी संसद के द्वारा बनाए गए क़ानून में वर्णित किया जा सकता है. कई बिंदुओं पर विचार के बाद, हमारे विचार से इसमें कोई शक़ नहीं है कि संसद उच्च न्यायालयों में अलग से एक व्यावसायिक शाखा के लिए प्रावधान कर सकती है.

व्यावसायिक अदालतों की स्थापना के तरीक़े

भारत में, हाईकोर्ट में विभाजनों का वर्गीकरण हाईकोर्ट के द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर ही होता है या फिर पूर्ण अदालतों के प्रस्तावों द्वारा होता है. हाईकोर्ट के विभिन्न जजों को न्यायिक कार्य सौंपने का अधिकार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का है. मुख्य न्यायाधीश द्वारा तैयार की गई सूची के अनुसार विभिन्न तरह के मामलों को निपटाने और उसकी सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में जज या तो एकल पीठ या दो या उससे अधिक की संख्या में पैनल में बैठते हैं. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बंटवारे के हिसाब से कुछ जज रिट क्षेत्राधिकार, कुछ दीवानी क्षेत्राधिकार में, अन्य की आपराधिक क्षेत्राधिकार में और इसी तरह अलग–अलग क्षेत्रों के मामलों की सुनवाई करते हैं. हालांकि भारत में ब्रिटेन , अमेरिका और दूसरे देशों की तरह अलग से व्यावसायिक विभाजन नहीं होने के बाद भी, दिल्ली उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार अपील और फ़ैसले के लिए इस तरह के मामलों का वर्गीकरण व्यावसायिक मामलों के तौर पर ही होता है. इस तरह का वर्गीकरण सभी उच्च न्यायालयों में नहीं है. इस तरह के व्यावसायिक मामलों का निपटारा अलग से करने की व्यवस्था सभी उच्च न्यायालयों में लागू होनी चाहिए.

हालांकि अहम सवाल यह है कि क्या इस तरह के वैधानिक प्रावधानों के द्वारा हाईकोर्ट की व्यावसायिक शाखा का गठन कर हाईकोर्ट में ही एक करोड़ से अधिक महत्व वाले व्यावसायिक मामलों का निपटारा करने की व्यवस्था करने या इसी स्तर की अपीलों से क्या हम इस तरह की शाखा के गठन की या जजों को अलग तरह के न्यायिक कार्य सौंपने की हाईकोर्ट की या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों में निहित शक्ति में हस्तक्षेप तो नहीं कर रहे.

नितिन जैन
सॉलिसिटर (इंग्लैंड एंड वेल्स, क्लैपम लॉ चैंबर्स)

feedback@chauthiduniya.com

बारिश न होने का असर

साल	बारिश (% में)	जीडीपी विकास	महंगाई दर	महंगाई(खाद्य पदार्थों में)
2003	102	8.5	5.5	1.3
2004	87	7.4	6.5	2.6
2005	99	9.3	4.4	4.8
2006	99	9.9	5.4	7.7
2007	105	9.0	4.8	5.6
2008	98	6.7	8.3	7.9

कम होती बारिश, कराह रही फ़सलें

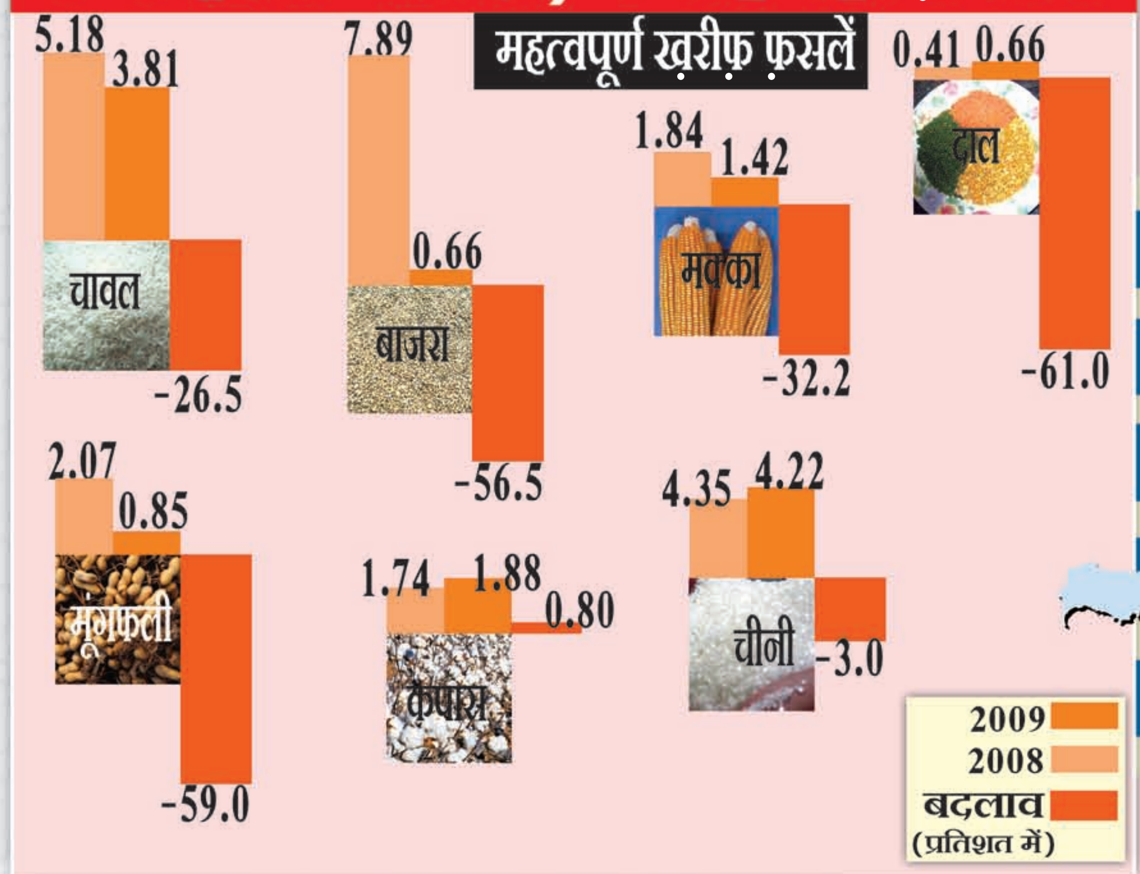

सूखे से सूख रही हैं उम्मीदें

फोटो–पीटीआई

सूखे से न केवल खेती प्रभावित होती है, बल्कि सभी चीज़ों–जैसे ईंधन से लेकर साबुन तक– की क़ीमतें बढ़ जाती हैं. इस साल भी बारिश की कमी ने हमें झकझोर कर रख दिया है.

ज़रूरी फ़सलों के उत्पादन में कमी आई है और राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार काफी दबाव में आ गई है. सबसे बुरा असर ख़रीफ़ फ़सलों पर हुआ है. इस साल धान के रकबे में 25 प्रतिशत की कमी आएगी और उत्पादन में 15 फ़ीसदी की गिरावट आने की संभावना है. इस सूखे की समस्या की गंभीरता को समझें इन आंकड़ों के आईने में.

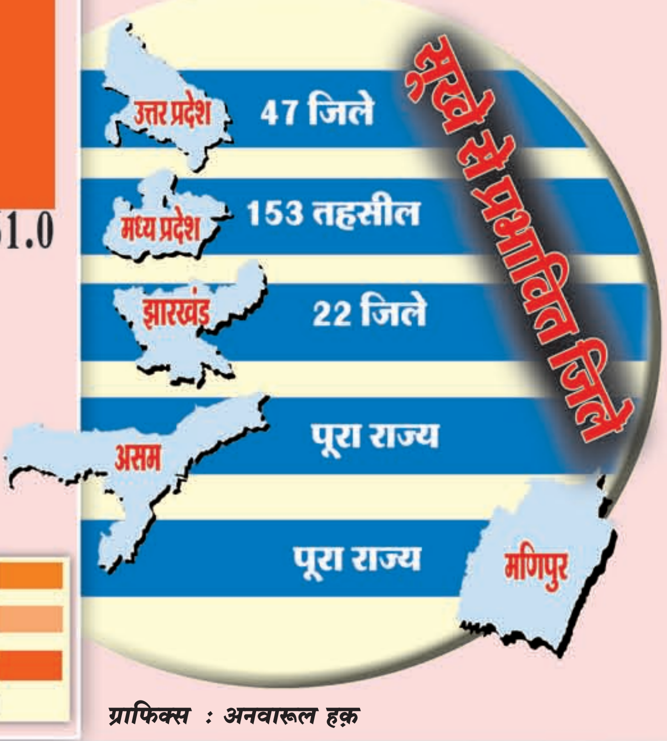

ग्राफ़िक्स : अनवारूल हक़

शरद पवार उवाच

बारिश पर

सरकार के पास 13 महीने का खाद्यान्न भंडार मौजूद है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. मानसून में देरी के कारण देश में स्थिति गंभीर है लेकिन स्थिति में सुधार हो रहा है. जून में मानसून के एक हफ्ता पहले आने की बात की गई थी और ऐसा हुआ भी लेकिन बाद में स्थिति बदल गई और बारिश नहीं हुई. जून में बारिश में 62 प्रतिशत कमी रही, अभी तक बारिश में 17 प्रतिशत कमी है.

बढ़ती क़ीमतों पर

सरकार की स्थिति नज़र है और दालों की बढ़ती क़ीमतों के मद्देनज़र इसे आम लोगों को मुनासिब क़ीमत पर मुहैया कराने के लिए जनवितरण प्रणाली की मदद ली जाएगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ममता जी, आम आदमी की परेशानी भी सुनिए

आदरणीया ममता जी,

आपने अपनी रेल में हर तबके को जगह देने की कोशिश की है. रेल बजट में कई घोषणाएं भी की हैं. *तुरंतो* ट्रेन चलाने की बात की है तो ग़रीबों को इज़्ज़त नवाजी है. युवाओं से लेकर महिलाओं, छात्रों, बुज़ुर्गों का ख्याल रखा है, लेकिन आसमानी घोषणाओं के बीच आम जनता की परेशानी कहीं पीछे छूट गई है. रेल में आम जनता को यात्रा करते वक़्त आम तौर कुछ परेशानियों से हमेशा रूबरू होना पड़ता है. ये परेशानियां हर ट्रेन में हर यात्रा में होती हैं. उन्हीं परेशानियों का ज़िक्र है. यह परेशानी आम यात्री की है, जो स्लीपर क्लास में सफ़र करता है. उम्मीद है आप ज़रा ध्यान देंगी.

किसी की यात्रा में पहली परेशानी होती है टिकट की. ख़ास तौर पर त्यौहारों और गर्मियों में. ममता जी आपने तत्काल बुकिंग की सीमा पांच दिन से घटाकर दो दिन कर दी है, लेकिन इससे टिकट की समस्या का माकूल हल निकलता नहीं दिखता. जब से ई–टिकटिंग की व्यवस्था शुरू हुई है, तब से इंटरनेट के ज़रिए बुकिंग कराने वाली रेलवे आरक्षण की दुकानें गली–मोहल्लों में खुल गई हैं. ये रेलवे आरक्षण वाले मुसाफिरों से मनमाने पैसे लेकर उनके टिकट कंफर्म कराती हैं. कंफर्म्ड टिकट दिलाने के लिए इन लोगों ने अपनी सांठगांठ रेलवे के भीतर कर रखी है. ये अलग–अलग कोटों के ज़रिए यात्रियों के टिकट कंफर्म कराते हैं. अकेले रायपुर में ऐसी दर्जनों दुकानें हैं. जहां यात्रा से एक दिन पहले ली गई टिकट गारंटी के साथ कंफर्म की जाती है, वहीं सीधे रास्ते से दस या बारह वेटिंग नंबर वालों का टिकट कंफर्म नहीं होता. यह समस्या दिखने में छोटी हो सकती है, लेकिन रोज़ाना सैकड़ों लोग इसे झेलते और लुटते हैं. जो टिकट विशेष लोगों और विशेष परिस्थितियों के लिए होते हैं, उनका इस्तेमाल रेलवे में बैठे लोग दो नंबर के पैसे बनाने के लिए कर रहे हैं. टिकट न मिलने की दूसरी वजह है एजेंट और दलालों का फैला जाल. आप नई दिल्ली स्टेशन चले जाइए. आरक्षण केंद्र के अंदर और बाहर आपको कई दलाल मिल जाएंगे जो स्लीपर के लिए दो सौ से तीन सौ और एसी के लिए पांच सौ से सात सौ रुपये ज़्यादा लेकर कंफर्म टिकट देते हैं. हां, हो सकता है कि यह यात्रा आपको किसी दूसरे के नाम से करनी पड़े. ये दलाल इस बात से अच्छी तरह वाक़िफ़ होते हैं कि कौन सी ट्रेन में टिकट का टोटा होता है. इन टिकटों की बुकिंग ये अलग–अलग नामों से पहले ही करा लेते हैं. इसके लिए इनके कारिंदे रोज़ाना रिज़र्वेशन की लाइन में लगे होते हैं. अलग–अलग ट्रेनों में अलग–अलग नाम से ये टिकट लेते हैं और फिर मुसाफिरों को ये टिकट बेच देते हैं. कुछ तो अपनी पैठ इतनी अच्छी बना लेते हैं कि वे काउंटर के अंदर बैठकर फ़र्ज़ी नामों से टिकट बनवाते हैं.

यात्रियों को अगली दिक़्क़त झेलनी पड़ती है ट्रेन में यात्रा करते वक़्त. दिक़्कत होती है टीटीई की मनमानी से. अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं है और अगर आपकी वेटिंग एक से दस के बीच में हो तो आप आश्वस्त मत होइए कि आपको सीट मिल जाएगी. टीटीई टिकट उसी को देगा जो उसे हरे–हरे नोट देगा. दरअसल ये टीटीई भ्रष्टाचार को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और कोई उनके अधिकार पर हमला बोले, ये किसी भी सूरत में उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते.

मैं आपको हाल की घटना बताता हूं. मैं 16 जून को छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में दिल्ली से बिलासपुर जा रहा था. टिकट तत्काल की थी. वेटिंग 6 और 7. मुझे लगा सीट होगी तो मिल ही जाएगी. थोड़ी दूर के बाद देखा कई यात्री जिनकी वेटिंग पचास –साठ है, वे टीटीई के पास से सीट लेकर ख़ुशी–ख़ुशी लौट रहे हैं. मैं भी टीटीई के पास पहुंचा. मैंने कहा– साहब मेरी वेटिंग 6 और 7 है, मेरी सीट कंफर्म नहीं हुई है और आपने उन लोगों को भी सीट दे दी, जिनके पास जनरल की टिकट है. टीटीई साहब ने मुझे ऊपर से नीचे देखा. फिर बोले, आप कहां बैठे हैं? मैंने कहा फलां बोगी में. इस पर बोले–वहीं बैठिए, मैं आ रहा हूं. मैं चुपचाप उनकी बातों पर यक़ीन करके चला गया, लेकिन मेरे बाद कई लोग गए और अपना टिकट कंफर्म करा आए. इस बीच बगल में बैठे शख्स ने मुझे बताया कि कटनी से कोई बारात बुक है. उन्होंने क़रीब पचास सीटें बुक कराई हैं. वे सीटें टीटीई डेढ़ सौ रुपये में बांट रहा है.

फोटो–प्रभात पाण्डेय

इस बीच टीटीई साहब पास आए. मैंने उनसे दो सीट मांगी. उन्होंने छूटते ही कहा–300 रुपये. मैंने एक परिचित टीटीई का हवाला दिया, उनसे बात कराई तो उन्होंने इतनी रियायत दी कि बिना पैसे के मुझे एक सीट देने को राज़ी हुए. लोगों की जेब पर डाका डालने वाला वह टीटीई मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैंने उसके पैसे चुरा लिए हों. जब मैंने उसे कहा कि मेरी वेटिंग 6 और 7 नंबर की है, तो वह कह रहा था कि सीट मैं एक ही दूंगा, मुझे बाक़ी लोगों को भी देखना है...ऐसे बोला जैसे वह ट्रेन का टीटीई न हो, ट्रेन उसके बाप की हो, और इसका सारा सिस्टम उसकी रखैल हो. जिसे जैसे चाहे वह नचा सकता हो. बहरहाल, मैंने सीट लेने से मना कर दिया. मैंने उसका नाम पूछा तो उसने नाम नहीं बताया. उसने नेमप्लेट भी नहीं लगाया था. जब मैंने उससे शिकायत करने को कहा तो उसने उलटा मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हें चाहूं तो अभी अंदर करा सकता हूं. मैं उसकी गुंडागर्दी देखकर दंग रह गया. यह हाल सिर्फ़ उस टीटीई का नहीं है या इस घटना का भुक्तभोगी सिर्फ़ मैं ही नहीं हूं. आप सब भी कभी न कभी इस तरह के वाकये से दो चार होते होंगे. कोई टीटीई से लड़ता होगा और ज़्यादातर लोग नोट दे देते होंगे, लेकिन लोगों के विरोध के बाद इन टीटीइयों का यह गोरखधंधा बदस्तूर चलता रहता है. ममता जी, इस पर लगाम लगाने की व्यवस्था आप बजट में तो नहीं कर सकतीं, लेकिन बजट से बाहर इन बेईमान टीटीइयों पर लगाम कसिए.

तीसरी समस्या है खान–पान की. ममता जी, आपने एलान कर दिया है कि खाने में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय व्यंजनों को जगह मिलेगी और खाने की गुणवत्ता जांची जाएगी. लेकिन असल समस्या पैंट्री कार में मिलने वाला ऊंची क़ीमत पर घटिया खाना है. पहले 10 रुपये में दो समोसे मिलते थे, लेकिन अब 15 रुपये के मिलने लगे हैं और समोसे के भीतर क्या होता है...सिर्फ़ आलू. साथ में लाल सॉस जैसा कुछ, जो दिखता तो लाल है लेकिन न मीठा होता है न खट्टा. आप अंबिकापुर में पुलिस लाइन वाले राजेश स्वीट्स के समोसे खाइये या हल्दीराम के (एक जगह दो तरह की बेहतरीन चटनी मिलती है तो दूसरी जगह काजू किशमिश भरा हुआ समोसा), लेकिन फिर भी दोनों जगहों पर दो समोसे 10 रुपये में मिल जाएंगे.

दोनों जगहों का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूं कि यहां के समोसे ही सबसे बेहतर होते हैं. इसी तरह सुबह नाश्ते में दो सूखे ब्रेड और कटलेट मिलता है–25 रुपये में. ब्रेड को ब्रेड बटर कहते हैं, लेकिन प्रयोगशाला में रिसर्च करा लीजिए तब भी आपको बटर नहीं मिलेगा. अब खाने की बात करते हैं. रेलवे का खाना माशाअल्लाह. पैसे आपसे लेंगे 35 और 60 रुपये, लेकिन खाना इतना घटिया कि भूख थोड़ी कम लगी हो तो गले से नहीं उतर सकता. चलिए अब आपको बताते हैं कि 35 रुपये वाला खाना कैसे 60 रुपये वाला खाना बन जाता है. 35 रुपये वाले खाने का 60 रुपया इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसकी सब्ज़ी में तीन चार टुकड़े पनीर के डाले होते हैं. परांठे की जगह लंबी पतली रोटी होती है, जिसे ये लोग रूमाली रोटी कहते हैं. चावल में दो चार दाने जीरे के डाल कर जीरा फ्राई कहते हैं और इस तरह हो जाती है स्पेशल थाली तैयार. हालांकि क़ीमत आईआरसीटीसी की तय क़ीमत के मुताबिक है, लेकिन अव्वल तो ये रेट ज़्यादा हैं और दूसरे निर्धारित गुणवत्ता का पालन नहीं होता. ममता जी, पीने के पानी की समस्या भी बड़ी ज़्यादा है. गर्मी के दिनों में पानी कहीं ठंडा नहीं मिलता. नागपुर और झांसी में तीन रुपये में ठंडा मिनरल वाटर एक पाउच मिलता है. बाक़ी स्टेशनों पर ऐसे स्टॉल खोलने की ज़रूरत है.

इसके अलावा सफाई रेलवे की सदाबहार समस्या है. अगर बोगी पुरानी हुई तो उससे बदबू आती है. फिर कई डिब्बों में टॉयलेट काफी गंदा होता है और पानी की दिक़्क़त भी होती है. कभी पानी ख़त्म हो जाता है कभी टॉयलेट का पानी बोगी में बहने लगता है. हालांकि ये समस्याएं रोज़मर्रा की नहीं हैं, पर ऐसी समस्याएं खड़ी हों तो इससे निपटने के इंतज़ाम होने चाहिए. जैसे एसी बोगी में साफ–सफाई का ज़िम्मा एटेंडेंट के पास होता है. वैसा ही एक अटेंडेंट स्लीपर में भी होना चाहिए. इससे स्लीपर में साफ –सफाई रहेगी और यात्रियों की सुरक्षा भी बेहतर हो जाएगी. इसके बदले आप प्रति यात्री पांच रुपये ज़्यादा ले लें, तो न कोई यात्री नाराज़ होगा, न ही आपका वोटबैंक नाराज़ होगा. ममता जी, बजट में हमने तो आपकी बातें सुन लीं. अब आपकी बारी है तनिक हमारी भी सुन लें.

एक आम आदमी

रूपेश
feedback@chauthiduniya.com

नक्सलवाद : रमन की राह का रोड़ा

प्रदीप गांधी

सत्ता व्यवस्था परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है. यह एक हथियार है जिसे यदि ठीक तरह से चलाया गया तो समाज में सुख, शांति और प्रगति का वातावरण निर्मित किया जा सकता है. यदि हथियार की दिशा बदल दी जाए तो यह दुख, अशांति और हिंसा का वातावरण तैयार कर देगा. यह वातावरण विकासशील देशों के तथा नवोदित प्रदेशों के सेहत के लिए ठीक नहीं होगा. चूंकि पूर्व में विकास की किरणें अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने भारत के मानचित्र पर तीन नए प्रदेशों का निर्माण किया. इस निर्माण के पीछे भाव यही था कि विकास की किरणें समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और विकास की प्रक्रिया में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो. सामाजिक न्याय का सिद्धांत समाज के अंतिम व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने पर पूरी होती है और इस चुनौतीपूर्ण कार्य को प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अपने दिमाग़ से नहीं बल्कि दिल से योजना बनाकर इसे कार्यरूप में परिणित कर उन चुनौतियों का मुक़ाबला किया है जो कल तक नारे थे वे आज हक़ीक़त में बदल गए हैं. सत्य-सत्य होता है, उसमें हज़ार हाथियों का बल होता है और वही ताक़त राजा की शक्ति होती है. उसके सहारे ही वह जनकल्याण के बड़े से बड़ा निर्णय लेता है. जब कोई निर्णय होगा तो असंतोष भी होगा लेकिन यदि निर्णय से अंतिम व्यक्ति को ख़ुशी मिलती है तो यह लोगों का दुखः उतना महत्व नहीं रखता है. चूंकि निर्णय बहुतायत लोगों की प्रगति के लिए हुआ है और फिर उस निर्णय के प्रकाश से समाज प्रकाशित होता है और वही प्रकाश हमें पुनः नया जनादेश प्रदान करता है.

कांग्रेस का गढ़ कहलाने वाला छत्तीसगढ़ गठन के समय से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण था. नए राज्य की पहली सरकार यूं तो अजीत जोगी के नेतृत्व में कांग्रेस की बनी, लेकिन नेतृत्व की लड़ाई ने कांग्रेस का नुक़सान कर दिया. नेतृत्व विवाद ने कांग्रेस के आधार को समाप्त कर अगली सरकार भाजपा की बन जाने दी. लेकिन डॉ. रमन सिंह के सामने सरकार बनाने के साथ ही कई नई चुनौतियां आ गईं. छत्तीसगढ़ नवोदित राज्य था. इस नाते वहां सब कुछ नए सिरे से शुरू होना था. लेकिन राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की कार्यपद्धति जिस मार्ग का अनुसरण कर रहीं थी. वह मार्ग ठीक नहीं था. पार्टी के अंदर तानाशाही स्थापित हो गई थी, जिससे नेतृत्व का अपमान हुआ. भ्रष्टाचार, भय और आतंक की रणनीति के अलावा ताक़त और पैसे के बल पर दल-बदल की नई राजनैतिक संस्कृति पैदा की गई. जातिवाद का ज़हर तो कालांतर में स्वयं उनके ही अपयश का कारण बना और धीरे-धीरे कांग्रेस कमज़ोर होती गई.

उधर भारतीय जनता पार्टी में डॉ. रमन सिंह राज्य में पहले चुनाव के समय केंद्र की तत्कालीन एनडीए सरकार में मंत्री थे. परिवर्तन को अनुशासन मानकर स्वीकार करना उनका हमेशा से स्वभाव रहा है और उसी स्वभाव का प्रतिफल है कि उन्हें पार्टी ने मुख्यमंत्री का दायित्व दिया. पार्टी अनुशासन से चलती है और अनुशासन के लिए स्वयं पर शासन ज़रूरी होता है. जब व्यक्ति स्वयं पर शासन कर लेता है तो सारा समाज व प्रदेश तथा वहां निवास करने वाली जनता उनके अनुशासन को स्वीकार कर लेती है.

विरासत में उन्हें जैसा प्रदेश मिला था, वह भय से मुक्ति के लिए तड़प रहा था. स्वयं कांग्रेस के लोगों ने अपनी सरकार को सत्ता से हटाने में अहम भूमिका अदा की थी और डॉ. रमन सिंह जैसे संवेदनशील व्यक्ति के सबल कंधों पर यह चुनौती भरा कार्य डाला गया था. अपने स्वभाव के अनुरूप डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश का इलाज प्रारंभ किया. मरीज़ कितनी ही गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, वही डॉक्टर सफल है जो उसका आत्मबल और मनोबल बढ़ा कर उसका इलाज करे. इससे मरीज़ भी जल्द स्वास्थ्य होता है. यह कार्य एक कुशल डॉक्टर के रूप में रमन सिंह ने किया और उसी का प्रतिफल है कि चुनौतियों को स्वीकार करते हुए वह निरंतर आगे बढ़ते रहे और अनेक प्रतिमान स्थापित करते रहे. व्यवस्था परिवर्तन का सशक्त माध्यम है-सत्ता. इसे उन्होंने स्थापित ही नहीं किया, अपितु राज्य में एक नया मॉडल स्थापित करके दिखा भी दिया.

कांग्रेस का हाथ ग़रीबों के साथ, यह कांग्रेस का नारा था. नारे जब आचरण में नहीं उतरते तो जनता दलों को सत्ता से बाहर कर देती है और नारे पर आत्मचिंतन का अवसर देती है. पुनः खड़े होने के लिए समय देती है. डॉ रमन सिंह और पूरी पार्टी ने परिवर्तन यात्राओं के माध्यम से सत्ता परिवर्तन की भूमिका बनाई और एक विजन छत्तीसगढ़ प्रस्तुत किया. यह दस्तावेज दरअसल वर्तमान चुनौतियों से जूझते हुए बेहतर और प्रगतिशील छत्तीसगढ़ के निर्माण का था. सामाजिक रूप से अति पिछड़े ग़रीब, आदिवासियों और हरिजनों के मन में उत्साह पैदा करना और उन्हें प्रगति की मुख्यधारा में जोड़ना वास्तव में कठिन था, लेकिन असंभव नहीं. यह कार्य डॉ रमन सिंह ने बख़ूबी किया. सामाजिक न्याय का सिद्धांत यह कहता है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर समाज की कड़ी को न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की नैतिक ज़िम्मेदारी है. यदि सरकार अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी का ईमानदारी से पालन करे, तो जनता को अपनी समझदारी का परिचय देते हुए बहादुरी के साथ सत्ता को सदैव नैतिक समर्थन देते रहना चाहिए तथा उपलब्ध वातावरण का लाभ उठा कर अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए. यह दुनिया मांग और आपूर्ति के फ़ामूर्ले पर चलती है.

शोषण करना मानवीय दुर्बलता है. शोषण का स्वरूप भिन्न-भिन्न होता है. छत्तीसगढ़ प्रदेश में आदिवासियों का बाहुल्य है. उनकी आजीविका का मुख्य साधन वनोपज हैं. वनोपज छत्तीसगढ़ में आर्थिक मज़बूती का बहुत बड़ा साधन हैं. घोर जंगलों में बसे छोटे छोटे गांव और वहां के लोग नमक के बदले अपने बहुमूल्य वनोपज को बेच दिया करते थे. सरकार ने 25 पैसे किलो नमक देकर उन्हें अपने बहुमूल्य वनोपज का पूरा आर्थिक मूल्य उपलब्ध कराकर अपने एक निर्णय से करोड़ों आदिवासियों को नई दिशा प्रदान की. 34 लाख परिवारों को तीन रुपये किलो चावल मुहैया कराया. इस तरह प्रति माह 35 किलो चावल देकर उन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा के घेरे में लाया गया. उनकी इस क्रांतिकारी योजना का अनुसरण केंद्र की वर्तमान कांग्रेस सरकार तक ने किया और अब यह पूरे देश में लागू कर दी गई है.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर सभी सरकारें कठघरे में खड़ी की जाती रही हैं और इस योजना में पर्याप्त भ्रष्टाचार की गुंजाइश रहती ही थी. सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक मुख्यमंत्री ने क्रांतिकारी निर्णय करके एक नई व्यवस्था का निर्माण किया. व्यक्तिगत मनुष्य का आचरण यदि ठीक नहीं है, तो वह व्यवस्था को अपने आचरण से प्रभावित करेगा. परिणामस्वरूप यदि आचरण गंदा है तो सत्ता बदनाम होगी और बड़ी सत्ता कभी भी व्यक्तिगत आचरण पर तीखी नज़र नहीं रख पाती है. कालांतर में व्यक्ति के दोष का प्रभाव सत्ता और संगठन पर पड़ता है और सत्ता बदलनी होती है. इसलिए समूह को ज़िम्मेदारी दी जाती है, ताकि परस्पर एक-दूसरे पर नज़र रखी जा सके तथा दबाव बना रहे. छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम को देश का एक मॉडल माना जाता है. जहां 10 हज़ार 400 दुकानें निजी हाथों से वापस लेकर पंचायतें, सहकारी संस्थाओं, वनसुरक्षा समितियों तथा महिला स्वसहायता समूहों के हाथों दे दिया गया है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए का रिवालविंग फंड भी उपलब्ध कराया गया है, ताकि ठीक कार्य हो. सारी व्यवस्था को हाईटेक करने की पूरी जानकारी पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत कर दी गई है.

विजन ग्लोबली एक्सन लोकली को आधार बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में जिस तरह से विदेशी पूंजी का निवेश देश में हो रहा है, उससे औद्योगिक क्रांति तो आ रही है लेकिन परंपरागत खेती और लघु उद्योग प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पा रहे हैं. ऐसे अघोषित संकट के समय रमन सिंह ने कृषि पर ख़ास ध्यान दिया. उन्होंने 13 से 14 प्रतिशत की दर पर मिलने वाले कृषि ऋण को तीन प्रतिशत की ब्याज दर पर लाकर किसानों को खेती के लिए अभूतपूर्व सुविधा उपलब्ध कराई है. अपने इस क़दम से उन्होंने साबित किया है कि राज्य में उनके नेतृत्व में इस समय किसान हितैषी सरकार काम कर रही है. प्रदेश में पहले कृषि ऋण की राशि 250 करोड़ थी, जिसे बढ़ा कर 600 करोड़ कर दी गई, यह भी बड़ी क्रांति है.

हमारा देश ऊर्जा संकट के दौर से गुज़र रहा है. जैसे-जैसे प्रगति के साधन बढ़ेंगे ऊर्जा की मांग भी बढ़ेगी और उसके लिए नीतिगत फ़ैसले लेने होंगे. छत्तीसगढ़ भारत का पहला प्रदेश है जिसे नो पावर कट स्टेट का दर्जा प्राप्त हो गया है. यहां ग्रामीण आबादी, किसानों, उद्योगों को पर्याप्त बिजली मिल रही है तथा भविष्य में यह देश का पावरहब बनने जा रहा है. यहां पर 42 हज़ार मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए एमओयू हो चुका है तथा 1.68 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है.

हमारा देश गांव का देश है. यहां कृषि मुख्य व्यवसाय है. इसलिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना एक कठिन चुनौती रहती है. लेकिन राज्य सरकार ने उस चुनौती को स्वीकार किया और पूर्व सरकार द्वारा 1.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल के स्थान पर तीन लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में नई सिंचाई क्षमता निर्मित कराई. इसलिए कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी मिल सके. किसानों के विकास के गर्भ में ही पलायन रूपी समस्या का समाधान छुपा हुआ है. छत्तीसगढ़ के पानी और जवानी दोनों को रोक कर रोज़गार के नए अवसर सृजित करने का कार्य डॉ. रमन सिंह ने किया है.

डॉ. रमन सिंह के सामने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सभी क्षेत्रों में चुनौतियां थीं. पर राजनैतिक सूझबूझ से उन्होंने हर समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया है. बावजूद इसके, चुनौतियां अब भी बाक़ी हैं. यूं तो समस्याएं अनेक हैं, पर सबसे बड़ी समस्या है-नक्सलवाद की. जब हम विकास करते हैं और विकास के लिए पैसे देते हैं तो जिन महकमों से पैसे जाते हैं, वहां बैठे हुए लोगों की नीयत को नापने का कोई पैमाना नहीं होता है. आज भी ग़लत तरीक़े से करोड़ों कमाने वाले कमा ही रहे हैं. आज भी कारपोरेट हाउस संसाधनों का दोहन कर अकूत संपदा जमा कर रहे हैं. महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बताया था. दीनदयाल जी ने एकात्मक मानववाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था. नक्सलवाद की जड़ में जाकर रमन सिंह को भी नए सिद्धांत का प्रतिपादन करना होगा. सिद्धांत क्या होगा, कैसा होगा, रास्ता कैसे बनेगा यह गंभीर आत्ममंथन मांगता है. यदि नक्सली दिशाहीन होकर केवल नरसंहार करना चाहते हैं तो सरकार को उनसे कठोरता से निपटना होगा. लेकिन यदि समस्या के मूल में आर्थिक शोषण है तो शोषण से मुक्ति की दिशा में कुछ क्रांतिकारी क़दम उठाने होंगे. ऐसे क़दम जो उद्यमिता को बढ़ावा दे तथा सत्ता का विकेंद्रीकरण कर समस्याओं का समाधान करे. निर्णय की प्रक्रिया में समाज के अंतिम व्यक्ति की भागीदारी जोड़ कर ही हम सलवा-जुडुम जैसे कार्यक्रम को एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान कर सकते हैं. इससे विकास के साथ विश्वास का नाता जुड़ेगा और भटके हुए लोग यदि इस दर्शन को समझ कर साथ आए, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ शांति के एक नए टापू के रूप में शीघ्र विकसित होगा.

(लेखक लोकसभा के पूर्व सदस्य हैं)

feedback@chauthiduniya.com

मुख्यमंत्री रमन सिंह की चुनौतियां और उपलब्धियां

1. मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना

छत्तीसगढ़ में भुखमरी और ग़रीबी की बड़ी समस्या थी. सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ के लगभग 34 लाख ग़रीब परिवारों को तीन रुपये प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल प्रति माह देने की योजना शुरू की गई है, जिस पर राज्य 837 करोड़ रुपये ख़र्च कर रहा है. इससे हालात बहुत सुधरे हैं लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना है.

2.पहुंच-विहीन ग्रामों में ग्रेन बैंक

राज्य के कई गांव अभी भी पूरी तरह से आधुनिक विकास से कटे हुए थे. राज्य के 2000 से अधिक ऐसे पहुंच-विहीन ग्रामों में ग्रेन बैंक बनाए गए हैं. ताकि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति को भुखमरी का सामना न करना पड़े. इसी तरह सभी पंचायतों में हर वक़्त पर्याप्त चावल रखने की व्यवस्था की गई है.

3.छत्तीसगढ़ अमृत नमक

राज्य के ग़रीब परिवारों को 25 पैसे प्रति किलो में आयोडीनयुक्त नमक देने की व्यवस्था की गई है. इससे दूरस्थ आदिवासी अंचलों में लोगों को अपनी 50 रुपये किलो मूल्य तक की वन से होने वाली उपज को बिचौलियों को मात्र 4-5 रुपये किलो के नमक के बदले में बेचने की मजबूरी एवं शोषण से छुटकारा मिलेगा.

4.सार्वजनिक वितरण प्रणाली

जन वितरण प्रणाली में बिचैलियों और जमाखोरों को ख़त्म करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी 10 हज़ार 400 दुकानें निजी हाथों से वापस लेकर सहकारी संस्थाओं, पंचायतों, लैंप्स और वन सुरक्षा समितियों को सौंपी गई. राशन दुकानों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है. हाईटेक मॉनीटरिंग के लिए एसएमएस से राशन की अद्यतन स्थिति की जानकारी देने की व्यवस्था की गई है. ग्रामीण अंचल में केरोसिन वितरण को सुगम बनाने के लिए हाट बाज़ारों में बिना राशन कार्ड के दो लीटर केरोसिन देने के लिए उजियारा योजना प्रारंभ की गई है. हालांकि अभी भी इस पूरी प्रक्रिया में कुछ समस्याएं हैं, जिनका निपटारा ज़रूरी है.

5.दीनदयाल आवास योजना

राज्य में भूमिहीनता की समस्या भी बहुत बड़ी है. दीनदयाल आवास योजना के तहत 88 हज़ार भूमिहीन ग्रामीणों को 900 वर्ग फीट भूमि का पट्टा प्रदान करने की योजना लागू की गई है. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के अंतर्गत प्रदेश के वन क्षेत्र में रहने वाले वनवासियों को भूमि का स्वामित्व प्रदान करने हेतु आवश्यक सर्वेक्षण तथा पट्टा वितरण के लिए वर्ष 2008-09 के बजट में 10.30 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है.

6. वन अपराध मुक्ति

पिछले 51 वर्षों से छोटे-छोटे वन संबंधी अपराधों के न्यायालयों में लंबित मामलों से पीड़ित अनुसूचित जाति, जनजाति तथा ग़रीब परिवारों के दो लाख 20 हज़ार 613 मामलों को ख़त्म किया. हालांकि अभी भी जंगल के लोगों को उनका वाज़िब हक़ मिलना बाक़ी है.

7. 6.5 प्रतिशत ब्याज दर पर क़र्ज़

महिला स्व-सहायता समूहों को छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से न्यूनतम 6.5 प्रतिशत ब्याज दर पर क़र्ज़ देने की योजना लागू की गई है.

8. औद्योगिक निवेश प्रस्ताव

भारत सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2006 एवं 2007 में छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव मिले. वर्ष 2006 में एक लाख सात हज़ार करोड़ रुपये के निवेश प्राप्त हुए थे, जबकि 2007 में नवंबर तक की जानकारी के अनुसार एक लाख 60 हज़ार करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके थे. दूसरे स्थान पर गुजरात को 90 हज़ार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे.

9. क़र्ज़ माफी

वर्ष 2004 में साढ़े पांच लाख लघु और सीमांत किसानों के 106 करोड़ रुपये के क़र्ज़ माफ किए गए. फिर भी राज्य में क़र्ज़ में डूबे किसानों की संख्या कम नहीं है.

10. तीन प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण

पहले प्रदेश में किसानों को 13-14 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देने की व्यवस्था थी. छत्तीसगढ़ देश में पहला राज्य बना जिसने छह प्रतिशत पर कृषि ऋण देना प्रारंभ किया. साथ ही ऋण राशि भी पूर्व के 250 करोड़ रुपये की तुलना में 600 करोड़ रुपये से अधिक उपलब्ध कराई गई है. 15 अगस्त 2008 को कृषि ऋण की ब्याज दर तीन प्रतिशत करने की घोषणा की गई है.

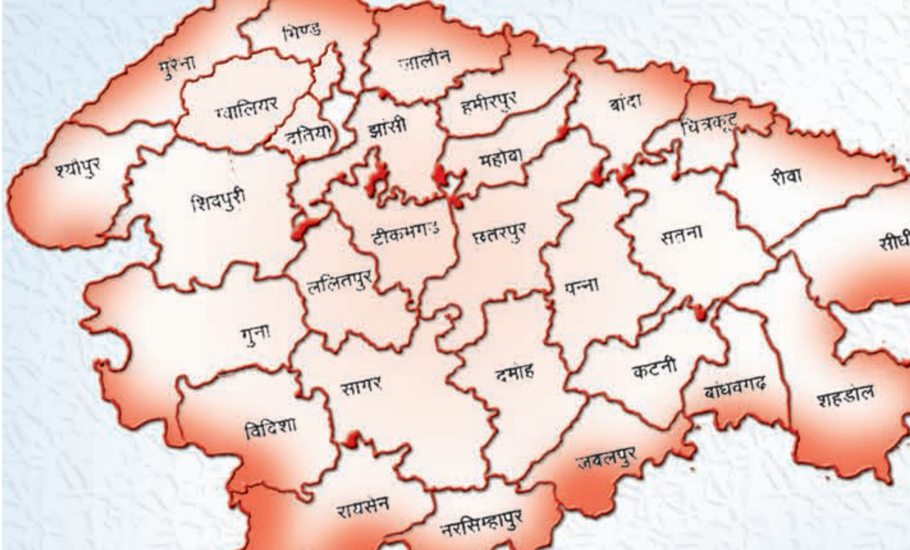

बुंदेलखंड राज्य के लिए भड़कने लगी आग

सुरेंद्र अग्निहोत्री

आज़ादी के बाद से ही उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के बीच बांट कर बुंदेलखंड के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है. जिस तरह इतिहासकारों ने महान राजा छत्रसाल की उपेक्षा की है, उतनी ही उपेक्षा बुंदेलखंड की लोक संस्कृति, कला, पुरातत्व तथा बुंदेली भाषा की आज हो रही है. पिछले दिनों प्रदेश की राजधानी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश के तीन राज्यों में बंटवारा- बुंदेलखंड, पूर्वांचल और हरितप्रदेश- किए जाने की वकालत करके उत्तर प्रदेश के विभाजन का जिन्न बोतल से बाहर निकाल दिया है. बुंदेलखंड राज्य के लिए 1947 से ही लड़ रहे बुंदेलखंड वासियों को मानो मुंहमांगी मुराद सी मिल गई है. अब उन्हें लगने लगा है कि इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं. 1947 में देश आज़ाद होने के बाद सुप्रसिद्ध साहित्यकार पं. बनारसी दास चतुर्वेदी के संपादन में कुंडेश्वर (टीकमगढ़) से निकलने वाली पत्रिका *मधुकर* ने बुंदेलखंड राज्य की मांग को पहली बार उठाया था. 1968 में सागर (मध्यप्रदेश) में बुंदेलखंड राज्य के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक सम्मेलन तत्कालीन मंत्री नरेंद्र सिंह जूदेव, साहित्यकार डॉक्टर बृंदावनलाल वर्मा, विधायक डाल चन्द जैन और मध्यप्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बृजकिशोर पटैरिया के नेतृत्व में हुआ था. हालांकि भोपाल के राजधानी बनते ही बुंदेलखंड राज्य आंदोलन को उतनी गति नहीं मिल पाई, जितनी की ज़रूरत थी. लेकिन बुंदेलखंड राज्य के लिए झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना और सागर में कभी तेज़ तो कभी धीमी गति से आंदोलन चलता रहा है. बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के लिए पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण नायक, तत्कालीन विधायक देव कुमार यादव, कामता प्रसाद विश्वकर्मा की बुंदेलखंड प्रांत निर्माण समिति, वर्तमान मंत्री बादशाह सिंह की इंसाफ़ सेना और बुंदेलखंड विकास सेना समय-समय पर राज्य आंदोलन की मुहिम चलाती रही है. 1989 में शंकर लाल मल्होत्रा के नेतृत्व में नौगांव छावनी में बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के गठन के साथ ही पिछले 17 सालों से बुंदेलखंड राज्य के लिए मुहिम तेज़ हो गई है. फिल्म अभिनेता और कांग्रेस के नेता राजा बुंदेला के नेतृत्व में बुंदेलखंड राज्य के लिए बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा चित्रकूट से खजुराहो तक जनजागरण यात्रा 15 अगस्त से शुरू की जा रही है. तिंदवारी (बांदा) के विधायक विशंभर प्रसाद निषाद जोश खरोश के साथ बुंदेलखंड राज्य का समर्थन विधानसभा के अंदर और बाहर करते है. वहीं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में सूपड़ा साफ करा चुकी भाजपा न हां कह पा रही है और न ही न कर पा रही है.

खनिज संपदा के लिए मशहूर बुंदेलखंड के पन्ना जनपद से ही 700 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को और मध्यप्रदेश सरकार को 1400 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में प्राप्त होते हैं. राजा बुंदेला कहते हैं कि बुंदेलखंड का आमजन बदहाली और बेबसी का शिकार है. संपन्न एवं मध्यम वर्ग का किसान क़र्ज़, ट्रैक्टर की किश्त, नमक-रोटी न जुटा पाने के कारण आत्महत्या कर रहा है. कांग्रेस के झांसी जिलाध्यक्ष सुधांशु त्रिपाठी कहते है बुंदेलखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह ध्वस्त है. 10-10 वर्षों से अंत्योदय, बीपीएल कार्ड धारकों को राशन नहीं मिल रहा है. बुंदेलखंड में भुखमरी की घटनाएं अब आम हो चली हैं. ग़रीब एवं वंचित वर्ग के लगभग 40 प्रतिशत लोगों का काम की तलाश में पलायन इसका प्रमाण है. बुंदेलखंड साहित्य एवं संस्कृति परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश मड़वैया कहते हैं कि अफसोस है कि आज़ादी के बाद हमारे अपने ही हमें एक नहीं होने दे रहे हैं.

बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के भानु सहाय कहते हैं कि बुंदेलखंड में प्रति व्यक्ति आमदनी राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है. बुंदेलखंड के जिले देश के चुनिंदा ग़रीब और संकटग्रस्त जिलों में शुमार हैं. यहां के हालत पर ग़ौर किए बिना तमाम योजनाएं लागू कर दी जाती हैं. परिणाम भी घातक होते हैं, लेकिन न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार ज़मीनी हक़ीक़त पर ग़ौर करने को तैयार हैं. न सरकारी मदद, न रोज़गार और अन्नदाता (किसान) लाचार की यह कहानी पिछले छह सालों से लगातार सूखे से सूखते बुंदेलखंड के लोगों की है. इन हालात से तंग आकर 12 सौ से भी अधिक किसानों ने ख़ुदकुशी कर ली. बुंदेलखंड की हर गांव की एक ही कहानी है. हर महीने कोई न कोई विपदा आती है. यूं तो बुंदेलखंड क्षेत्र दो राज्यों में विभाजित है-उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश. हालांकि भू-सांस्कृतिक दृष्टि से यह क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न रूप से जुड़ा हुआ है. रीति रिवाजों, भाषा और विवाह संबंधों ने इस एकता को और भी पक्की नींव पर खड़ा कर दिया है. उत्तर प्रदेश के झांसी, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर और जालौन के अलावा इस क्षेत्र में ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, अशोकनगर, पन्ना, दमोह, सतना और गुना जैसे जिले भी शामिल हैं. वैसे बुंदेलखंड के अनेक बुद्धिजीवियों का तो मानना है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सात जिले और मध्य प्रदेश के 21 जिले आते हैं.

इसी आधार पर कुछ लोगों ने बुंदेलखंड राज्य की स्थापना का आंदोलन भी प्रारंभ किया है. बुंदेलखंड में नरेगा के नाम पर हुई लूट से ग्रामीणों में व्याप्त आक्रोश लालगढ़ की तरह न फूट पड़े, यह ध्यान रखना होगा. राहुल गांधी ने बुंदेलखंड के लोगों को आश्वासनों की चूसनी से जो सपना दिखाया है वह खंड-खंड बुंदेलखंड के रहते पूरा नहीं हो सकता है. इसी बात को लेकर संघर्ष की राहों पर उतरी बुंदेलखंड विकास सेना यहां के ग्रामीण अंचलों में जितनी तेज़ी के साथ अपना सदस्यता अभियान चला रही है, उससे तो यही लगता है कि बुंदेलखंड में राज्य का आंदोलन एक नए रंग के साथ शुरू होने वाला है.

feedback@chauthiduniya.com

राजा बुंदेला, दद्दू प्रसाद, प्रदीप जैन और गोपाल बार्गव (बाएं से दाएं)

बुंदेलखंड

कब-कब उठी मांग

- बुंदेलखंड राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई. इसके प्रथम संस्थापक पंचम सिंह (गढ़ कुंढ़ार) थे. वर्ष 1128 में हेमकरण ने इसकी राजधानी ओरछा बनाई. अकबर के समय वीर सिंह बुंदेला ने इस राज्य का विस्तार किया.
- महाराजा छत्रसाल ने अपने बाहुबल के आधार पर बुंदेलखंड राज्य की स्थापना की और इसकी सीमाएं चंबल, नर्मदा, यमुना और टोंस नदी की परिधि में थी.
- द्वापर युग में भी बुंदेलखंड का अलग अस्तित्व रहा. तब यह चेदि प्रदेश राजा शिशुपाल तथा दंतवक्र के अधीन था, दोनों ही श्रीकृष्ण की बुआ के पुत्र थे.
- 1955 में गठित प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग ने बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए इसे अलग राज्य बनाने की सिफ़ारिश की थी.
- मध्यप्रदेश के विधानसभा में बुंदेलखंड राज्य के लिए मांग पहली बार विधायक ब्रजकिशोर पटैरिया ने की थी.
- बुंदेलखंड राज्य के लिए 1968 में तत्कालीन मंत्री नरेंद्र सिंह जूदेव की अध्यक्षता एवं साहित्यकार डॉ. वृंदावन लाल वर्मा की पहल पर सागर में पूर्व मंत्री बृजकिशोर पटैरिया के संयोजन में सागर मध्यप्रदेश में सम्मेलन हुआ.
- 1989 में शंकरलाल मल्होत्रा ने नौगांव छावनी में बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की. वह सर्वसम्मति से इसके अध्यक्ष चुने गए. तभी से बुंदेलखंड राज्य के लिए आंदोलन शुरू हो गया.

प्रस्तावित जिले

- **उत्तर प्रदेश :** बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन, ललितपुर.
- **मध्यप्रदेश :** छतरपुर, पन्ना, सतना, दतिया, टीकमगढ़, दमोह, सागर.
- **क्षेत्रफल :** 1.60 लाख वर्ग किलोमीटर (यूपी में 30 हजार वर्ग किलोमीटर).
- **आबादी :** लगभग 3 करोड़ 5 लाख 75 हजार.

समस्याएं

- उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाने के लिए 300 से 450 किलोमीटर दूर का रास्ता तय करना पड़ता है. हाई कोर्ट के लिए इलाहाबाद जाना होता है. अविकसित होने से जनप्रतिनिधि और सरकारें विकास की सुध नहीं लेतीं.
- केंद्र और राज्य सरकारों को बुंदेलखंड से हर वर्ष लगभग 500 अरब रुपए राजस्व के रूप में मिलते हैं. लेकिन यहां विकास के लिए मिलने वाला बजट इसका चौथाई भी नहीं होता. उत्तराखंड के आठ जिलों को 425 करोड़ रुपये और छत्तीसगढ़ को 350 करोड़ रुपये मिलते है. जबकि बुंदेलखंड के सात जिलों को मात्र 12 करोड़ और मध्य प्रदेश में आने वाले बुंदेलखंड के छह जिलों को मात्र 20 करोड़ रुपये का बजट आवंटित होता है.

राजनीतिज्ञों का रुख़

श्रीमती इंदिरा गांधी
बुंदेलखंड के पिछड़ेपन पर चिंतित हूं. यहां के विकास को प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकार प्रस्ताव भेजे तो पूर्ण सहयोग करूंगी. मैं योजना आयोग से कहूंगी कि वह पता करे कि क्या किया जा सकता है. (सांसद रामनाथ दुबे के पत्र के जवाब में छह फरवरी 1980 को जवाब)

सोनिया गांधी
बुंदेलखंड के विकास के लिए विकास परिषद का गठन कराया जाएगा. मैं यहां की रिपोर्ट मंगा रही हूं.
(2003 में एक कार्यक्रम के दौरान)

मायावती
यदि केंद्र तैयार हो, तो हम विधानसभा में बुंदेलखंड, पूर्वांचल, हरितप्रदेश के निर्माण का प्रस्ताव पारित करा सकते हैं.
(9 सितंबर 2007 को लखनऊ में रैली को संबोधित करते हुए)

सलमान ख़ुर्शीद
कांग्रेस के सत्ता में आने पर बुंदेलखंड विकास परिषद का गठन किया जाएगा. इसका उल्लेख आगामी चुनाव घोषणा पत्र में भी होगा.
(11 सितंबर 2000 को बांदा में पत्रकार वार्ता के दौरान)

रणदीप सिंह सुरजेवाला
बुंदेलखंड के लिए विकास परिषद का गठन कांग्रेस की सत्ता होने पर.
(दस सितंबर 2000 को बांदा में युवक कांग्रेस की मंडलीय क्रांति रैली में)

राहुल गांधी
बुंदेलखंड के विकास को लेकर कांग्रेस प्रतिबद्ध है. यहां के पिछड़ेपन और विकास के उपायों का अध्ययन किया जा रहा है.
(जनवरी 2005 में चित्रकूट में पार्टी अधिवेशन के दौरान)

राजनाथ सिंह
बुंदेलखंड के विकास के लिए बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण बना देना चाहिए. *(12 नवंबर 2006 को मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में निवाड़ी के गढ़ कुंढ़ार में एक कार्यक्रम के दौरान)*

अजीत सिंह
उत्तर प्रदेश के चार टुकड़े किए बिना विकास संभव नहीं. बुंदेलखंड, हरितप्रदेश तथा पूर्वांचल राज्य के लिए हम विधानसभा में आने वाले प्रस्ताव का समर्थन करेंगे.
(22 अक्टूबर 2007को लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान)

रामविलास पासवान
विकास के वटवृक्ष तले सूखते बुंदेलखंड को राज्य का दर्जा तुरंत मिलना ज़रूरी है.
(बुंदेलखंडी संसद झांसी में संबोधन के दौरान)

सभी फोटो- **प्रभात पाण्डेय**

सरकार ही चाहती है सब कुछ दिखाना

गंगेश मिश्र

कहते हैं कि कोई एक जगह खड़ा नहीं रह सकता. वह अगर आगे नहीं बढ़ सकता तो पीछे लौटता है. अगर अच्छाई की आशा नहीं कर सकता, तो बुराई को अपनाता है. कभी बुद्धू बक्सा के नाम से कुख्यात हुआ अपना टेलीविजन आज ऐसे ही दोराहे पर खड़ा है. भारत सरकार की प्रसारण नीति के भी दोराहे पर खड़े होने से नीम चढ़े करैला वाली स्थिति है, जिसके कारण टीवी को परिवर्तन के नाम पर पतन की राह दिखा दी गई है. विदेशी चैनलों की बात पुरानी हुई, अब तो खांटी देसी चैनलों पर भी अश्लीलता का कारोबार बेधड़क चालू है.

पिछले दिनों राज्य सभा में सच का सामना समेत कई रियलिटी शो का मामला उठा. मामला अदालत में भी चला गया. सरकार की ओर से भी इन रियलिटी शो के एडल्ट विषयों पर चिंता जताई गई. सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी का कहना था कि हम सभी के लिए एक दायरे बने हैं और हमें उसके अंदर ही रहना चाहिए. तमाम नैतिकताओं और मान-मर्यादाओं को ताक पर रख देने वाले रियलिटी शो-सच का सामना-को लेकर सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने उसे दिखाने वाले चैनल यानी स्टार प्लस को नोटिस भी जारी कर दिया है. थोड़े में कहें तो सरकार की ओर से छोटे पर्दे पर बढ़ती हिंसा और अश्लीलता पर चिंता जताते हुए उस पर लगाम कसने के वादे किए गए हैं. लेकिन तय मानिए कहीं कुछ होगा नहीं. इसलिए कि सरकार ही ऐसा नहीं चाहती. उसकी नीयत में ही खोट है. चौतरफा महंगाई, विकास दर में गिरावट और ऊपर से लगभग पूरे देश में सूखे जैसी स्थिति पर नियंत्रण पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है. इसलिए वह कभी समलैंगिकता पर दो टूक निर्णय न कर, तो कभी टीवी पर चल रहे रियलिटी शो में उलझा कर लोगों को असल विषयों पर सोचने और बोलने का समय नहीं देना चाहती. सरकार किसी बड़ी समस्या के हल के लिए किस तरह के फ़ार्मूले पर काम करती है, इसे स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद के बयान से समझा जा सकता है. उनका मानना है कि लोगों को देर रात तक टीवी दिखाने से देश की आबादी कम हो सकती है. यानी देर रात तक टीवी पर परोसी जा रही अश्लीलताओं को देख-देख कर लोग इतने कुंठित हो जाएंगे, कि पति-पत्नी के सहज और सुंदर रिश्ते को निभाने के लायक रह ही नहीं जाएंगे. यानी ऐसा कहते हुए वह यह मान रहे हैं कि परिवार नियोजन के नाम पर कई दशकों से चल रहे सरकारी कार्यक्रम नाकाम रहे हैं. यही हाल प्रसारण नीति की भी है. केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी एक तरफ़ तो सच का सामना बनाने वालों और उसे दिखाने वाले चैनल को नोटिस जारी करती हैं, लेकिन लगे हाथ यह भी कहती हैं कि वह कोई नियामक बनाने के पक्ष में नहीं हैं. अधिक से अधिक वह यह तय कर देंगी कि क्या दिखाया जाए और क्या न दिखाया जाए. अब उन्हें यह कौन बताए कि यह तो पहले से तय है. क्या सूचना और प्रसारण मंत्री को यह नहीं मालूम कि टीवी चैनलों के लिए इस देश में आवश्यक दिशा-निर्देश बने हुए हैं. ये दिशा-निर्देश काफी व्यापक हैं. इसमें सेक्स, अश्लीलता से लेकर भाषा और हिंसा तक पर काफी कुछ कहा गया है. लेकिन न तो चैनल वाले इस पर अमल कर रहे हैं और न ही सरकार को ही इसकी चिंता है. दरअसल, सच का सामना या अश्लीलता से भरे अन्य कार्यक्रमों की भरमार का संबंध व्यवस्था के दोहरेपन से है. इस दोहरेपन की सड़ांध को फिल्म और टेलीविजन की दुनिया में सर्वत्र आसानी से पहचाना जा सकता है. जहां तक प्रसारण नीति में दोहरेपन का सवाल है तो आश्चर्यजनक रूप से यह सच है कि इसकी परंपरा कांग्रेसी शासन से ही शुरू हुई. वह भी सरकारी मीडिया यानी दूरदर्शन से. तब प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव हुआ करते थे. राव शासन में सूचना व प्रसारण मंत्री होते थे हरकिशन लाल भगत. उन दोनों ने 1986 में दूरदर्शन पर देर रात की वयस्क फिल्में दिखाने की अनुमति देकर उसे कामुक चैनल ही बना दिया. इस देश में महिलाओं को सामने से नग्न दिखाने का पाप अब तक सिर्फ़ और सिर्फ़ दूरदर्शन के नाम ही है. लगभग 23 साल पहले दूरदर्शन पर दिखाई गई वह फिल्म थी-शी विल बी वेयरिंग पिंक पायजामा. उन दो बुज़ुर्ग नेताओं की मेहरबानी ही थी कि देश में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के ज़रिए अनिवासी भारतीयों द्वारा कामुक फिल्मों का आगमन हुआ. अनिवासी भारतीयों ने एनएफडीसी द्वारा तब जो फिल्में आयात कराईं, उनमें नायिकाओं को पांच साल की बच्ची की मानसिकता और जवान बिल्ली की कामेच्छा की धनी बताने वाली फिल्में-सिरोको, लोनली लेडी और नोबल लेडी जैसी अनगिनत फिल्में थीं. स्कर्ट और टाप्स के बाद बिकनी तक उतर आए नीतिगत खुलेपन से टीवी का छोटा पर्दा भी अछूता नहीं रह सका. बुद्धू बक्से की छवि से मुक्ति की चाहत में टीवी अचानक वयस्कता की होड़ में शामिल हो गया.

क्या सूचना व प्रसारण मंत्री को यह नहीं मालूम कि टीवी चैनलों के लिए इस देश में आवश्यक दिशा-निर्देश बने हुए हैं. इनमें अश्लीलता, सेक्स से लेकर भाषा और हिंसा तक काफी कुछ कहा गया है.

झंडाबरदार बन कर सामने आया-एमटीवी. लेकिन खुलेपन की होड़ हमारे नेताओं में भी हमेशा रही है. जैसे 1998 में जब एमटीवी के *ग्राइंड* जैसे कार्यक्रमों के ख़िलाफ़ आज की तरह ही जब संसद में हल्ला मचा, तो तब भी सूचना व प्रसारण मंत्री महिला ही थीं. वह थीं-सुषमा स्वराज. आज बाल विवाह को महिमा मंडित करते सीरियल-बालिका वधू-के विरोध पर जिस तरह का जवाब सूचना व प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी दे रही हैं, कुछ वैसा ही तत्कालीन मंत्री सुषमा स्वराज का भी हुआ करता था. उन्होंने तो एक क़दम आगे बढ़ते हुए यहां तक कह दिया था कि जब मैं अपनी बेटी को ही एमटीवी देखने से नहीं रोक पाती हूं तो दूसरों को कैसे देखने न दूं. ज़ाहिर है, एमटीवी उसके बाद नंगई की हर सीमा को समय के साथ और अधिक से अधिक लांघता चला गया. *रोडीज़* और *स्पिट्सविला* जैसे रियलिटी शो में गाली बकने वाली लड़कियां आज आदर्शों में गिनी जाने लगी हैं. गवाह है सोनी पर प्रसारित हो रहे शो-मुझे इस जंगल से बचाओ-में *रोडीज़* की कुख्यात लड़की पलक को शामिल किया जाना. *बिग बॉस-2* में संभावना सेठ, पायल रोहतगी, राजा और राहुल महाजन ने क्या किया था, यह सब जानते हैं. बावजूद इसके, उनमें से अधिकतर कई चैनलों पर हस्ती बने बैठे हैं. इसलिए यह कहना ही होगा कि सेल्फ रेगुलेशन पर्याप्त नहीं है और इससे काम नहीं चल सकता. इसलिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को कोई कठोर क़दम उठाना ही चाहिए. लेकिन यह सच है कि कोई भी क़दम उठाने से पहले उसके स्वरूप और अन्य पक्षों पर आवश्यक विचार-विमर्श अवश्य हो जाना चाहिए. ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सचमुच बची रहे और उसके नाम पर चल रहा गोरखधंधा भी बंद हो जाए.

feedback@chauthiduniya.com

पहले से मौजूद हैं दिशा-निर्देश

दिशा-निर्देशों के मुताबिक कोई चैनल ऐसे कार्यक्रम नहीं दिखा सकते, जो दर्शकों में अश्लीलता को बढ़ावा देते हों. इसलिए फिल्मों की तरह ही हर शो को एक प्रमाणपत्र दिया जाता है. उसमें यह साफ-साफ लिखा होता है कि-

1 यू यानी यूनिवर्सल. ऐसे प्रमाणपत्र वाले शो का मतलब होता है कि यह हर उम्र के दर्शकों के लिए देखने लायक है. ऐसे कार्यक्रमों की श्रेणी में आम तौर पर शिक्षाप्रद और पारिवारिक कार्यक्रम आते हैं.

2 यू/ए यानी यूनिवर्सल/एडल्ट. ऐसे प्रमाणपत्र वाले शो 12 साल से बड़ी उम्र के किशोर माता-पिता से इजाज़त लेकर देख सकते हैं. लेकिन ऐसे कार्यक्रम रात आठ बजे से देर रात के दो बजे तक ही दिखाए जा सकते हैं.

3 ए यानी एडल्ट. फिल्मों की तरह ही ए-सर्टिफिकेट वाले शो 18 साल से अधिक उम्र वाले ही देख सकते हैं. इतना ही नहीं, ये कार्यक्रम रात 11 बजे से पहले शुरू नहीं हो सकते.

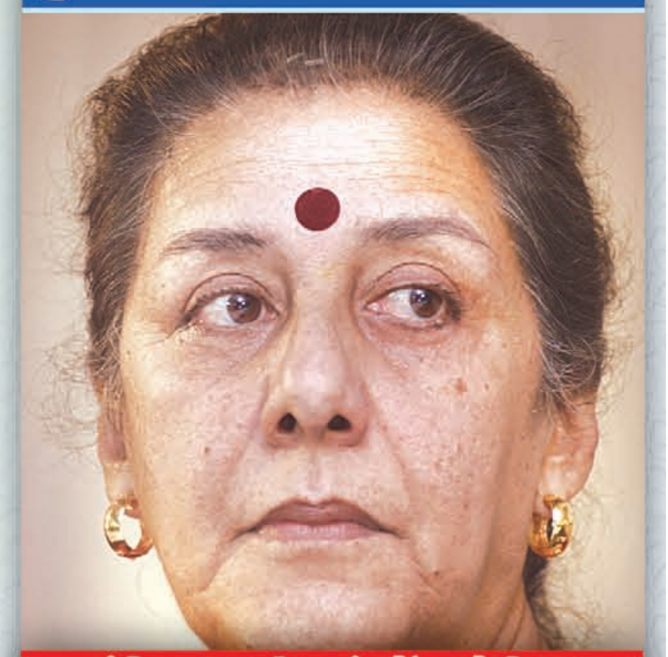

अंबिका जी आंखें खोलिए

- वयस्क विषयों पर होते हुए भी स्टार प्लस पर दिखाया जा रहा *सच का सामना* रात में साढ़े दस बजे ही शुरू हो जाता है. दूसरे, इसके निर्माता और प्रसारणकर्ता दर्शकों के प्रति कितने गंभीर हैं, यह इस शो के दौरान स्क्रीन पर चल रहे टिकर से समझा जा सकता है. इसमें लिखा होता है-इस शो के विषय परिपक्व (यानी वयस्क नहीं, समझदार) हो सकते हैं, इसलिए अभिभावक की निगरानी आवश्यक है.
- कहना न होगा कि गाली-गलौज से भरी भाषा, अश्लील दृश्य और विवादास्पद विषय उठाने वाले तमाम रियलिटी शो सरकारी दिशा-निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए प्रसारित हो रहे हैं. हद तो यह कि ये सारे शो देर शाम सात बजे से रात ग्यारह बजे तक प्रसारित होते हैं. एमटीवी का *रोडीज़* हो या *स्पिट्सविला* या कोई और, सभी शाम सात बजे के आसपास ही प्रसारित होते रहे हैं.

टीआरपी के नाम पर धड़ल्ले से चल रही है नंगई

समलैंगिकता पर दिल्ली हाई कोर्ट के फ़ैसले पर उठा विवाद अभी थमा भी नहीं था कि दर्शकों को शारीरिक संबंधों से लेकर अविवाहिता मां बनने और अवैध संबंध की इच्छा रखने जैसे अजीबोग़रीब सच का सामना करना पड़ रहा है. कल तक अश्लीलता बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाई पड़ती थी लेकिन वहां बिकनी में अभिनेत्रियों का आना और चुंबन वाले दृश्य सेंसर की कैंची चलने के बाद ही पर्दे पर आते थे, लेकिन चैनलों की टीआरपी दौड़ में अब यह सब छोटे पर्दे पर खुलेआम हो रहा है. वयस्क सवालों पर आधारित सच का सामना का लाभ स्टार प्लस को पूरा मिल रहा है. पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 15 फ़ीसदी कम कमाई होने से परेशान इस चैनल को तारणहार मिल गया है. बीती 15 जुलाई से शुरू हुए इस शो ने अपने पहले ही हफ़्ते में तीन करोड़ दर्शकों को जोड़ लिया. पहले ही शो की टीआरपी 4.6 रही, जो एक रिकॉर्ड है. अपने पहले तीन एपीसोड उसने औसतन 4.3 टेलीविजन रैंकिंग हासिल की, जो इसी समय शुरू हुए दूसरे रियलिटी शो से कहीं अधिक है. जैसे राखी सावंत के स्वयंवर की शुरुआती टेलीविजन रैंकिंग 0.1 थी, वहीं सोनी पर प्रसारित हो रहे मुझे इस जंगल से बचाओ की 1.6 तो स्टार प्लस के एक अन्य शो-गोदरेज खेलो जीतो जियो-की 0.8 ही थी.

स्टार प्लस वालों के मुताबिक सच का सामना को सबसे अधिक टीआरपी गुजरात में मिल रही है. उनका दावा है कि यह रियलिटी शो लोगों की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव ला रहा है. अगर वे सही कह रहे हैं, तो आने वाले दिनों में छोटे पर्दे पर रियलिटी शो के नाम पर कैबरे और स्ट्रिपटीज़ शो देखने के लिए तैयार रहिए.

रियलिटी शो वालों ने एक-एक क़दम नाप-तौल कर उठाए हैं. पहले उसने नैतिकता के पुराने सारे मानक ध्वस्त किए. फिर नई परिभाषा गढ़ते हुए लोकप्रियता को जीवन का महान उद्देश्य बना दिया. किसी भी तरह से चर्चा में रहना आज की नई नैतिकता है. चर्चा में रहने के लिए देह और ज़ुबान सनसनीख़ेज होनी चाहिए. जिसकी देह जितनी दिखेगी और ज़ुबान जितनी भ्रष्ट होगी, उसकी सफलता की गारंटी उतनी ही अधिक होगी.

जिन्हें-फाड़ दूंगा-जैसी घटिया सड़क छाप भाषा पर आपत्ति होती थी, देखते ही देखते ही उनके ड्राइंग रूम में टीवी पर-मेरी तो फट गई-बोलती रियलिटी शो वालियां प्रकट हो गईं हैं. इन्हें देख-देख कर सयाने बनते बच्चे घर में खुलेआम चुनौती देते हैं-आप कुछ नहीं जानते.

दुर्भाग्य से दुनिया को देखने-समझने का सबसे बड़ा ज़रिया आज टीवी हो गया है. राखी सावंत, संभावना, पायल रोहतगी और पलक जैसी मुंहफट लड़कियां और शो के दौरान आपस में लड़ने-झगड़ने से लेकर मारपीट तक करते लड़के उनके आदर्श हैं. गाली बोलतीं मुंहफट लड़कियां आधुनिकता की पर्याय हो गई हैं. इसी तरह गठीले बदन वाले लड़के नायकत्व को प्राप्त हो गए हैं.

रियलिटी शो में महिलाओं का यौन शोषण सिर्फ़ इसलिए नहीं होता कि वहां पुरुषों का वर्चस्व है. यह जानते हुए भी कि उनके व्यवहार से चैनल की टीआरपी बढ़ रही है या उसे दूसरी तरह के कमर्शियल लाभ मिल रहे हैं, महिलाएं कतई विरोध नहीं करतीं. उनके लिए जीवन से भी अधिक क़ीमती हो जाता है शो में बने रहना. इस तरह के शो में जितने एपीसोड वह टिकी रहेगी, समाज में उतना ही उनका नाम होगा. गुमनामी ऐसे लोगों के लिए मौत से कम नहीं लगती. यानी चर्चा है तो मज़ा है, बाक़ी सब बकवास.

चर्चा का लाभ देखिए कि एमटीवी के रियलिटी शो-रोडीज़-में खुलेआम गाली बकती और लात मारती पलक को एक और शो-मुझे इस जंगल से बचाओ-मिल गया. *बिग बॉस-2* में बदतमीज़ियों की सारी सीमाएं लांघने वाली संभावना और मर्यादाओं को भंग कर चर्चित हुए राहुल महाजन आज विभिन्न चैनलों पर जज और दूसरे रूप में छाते जा रहे हैं. यानी जो अपनी करनी से कहीं के नहीं रह गए थे, वे ग़लत वजहों से पहले चर्चा में आए और आज दूसरों से कहीं सफल हैं. इस तरह सफलता और सफल होने के रास्ते के मायने बदल गए हैं.

रियलिटी शो के जज भी बड़े अजीबोग़रीब होते हैं. एक बार *नच बलिए* में एक प्रतियोगी को फराह ख़ान महज़ इसलिए पूरी दुनिया के सामने बुरी तरह दुत्कार रही थीं कि उसने पैर में चोट लगने के कारण हील वाली जूती नहीं पहनी थी. *एमटीवी रोडीज़* में तो और हद कर दी जाती थी. वहां तो शो में भाग लेने से पहले ऑडिशन में ही लड़कियों को सरेआम भद्दी से भद्दी गालियां दी जाती थीं. एक बार कोलकाता में जब ऑडिशन हुआ, तो वहां मुख्य जज की भूमिका में टीवी की दुनिया का सबसे बदतमीज़ रघु राम बैठा था. लगता है, उसके मां-बाप ने उसे बातचीत का मतलब या तो गाली-गलौज ही सिखाया है, या फिर घर से लेकर बाहर तक सबने उसे ज़िंदगी भर गाली ही दी है. या फिर इसका सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि एमटीवी वालों की नज़र में भारतीय समाज की ही ऐसी तस्वीर बनी हो. बहरहाल, हर शहर में घूम-घूम कर लिए जा रहे ऑडिशन के दौरान वह लड़कियों को *स्टुपिड* और *एरोगेंट* ही कहता रहा. हद तो उसने दिल्ली में कर दी. वहां ऑडिशन देने आई एक लड़की के लिए उसने *बिची* जैसे शब्दों के धड़ल्ले से इस्तेमाल किए. क़ानून की घटिया से घटिया समझ रखने वाला भी बता सकता है कि लड़की के साथ हुआ इस तरह का अभद्र व्यवहार सीधे-सीधे यौन शोषण में आता है. फिर भी संसद, सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की चुप्पी हैरान करती है.

अब स्टार प्लस पर आया नया रियलिटी शो-सच का सामना- तो मर्यादा को ही शब्दकोश से हटा देने पर आमादा लगता है. इसके एक एपीसोड में अभिनेत्री उर्वशी ढोलकिया से पूछा गया-क्या आपने कभी मज़े लेने के लिए उस स्ट्रिपटीज शो में गई हैं जहां मर्द नंगे होते हैं. उर्वशी का जवाब-हां, में था. लेकिन बात यहीं ख़त्म होने के बजाय मां तक पहुंचीं, जो बेटी के इस जवाब पर मज़े से हंस रही थी. यानी संदेश साफ है-मां को बेटी को जवान बिल्ली जैसी कामुकता वाली साबित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है. उर्वशी सिंगल मदर हैं और वह एक बार तब गर्भवती हो गई थीं, जब वह नाबालिग थीं. हमारा क़ानून कहता है-नाबालिग उम्र में सेक्स अपराध होता है, चाहे वह मर्ज़ी से ही क्यों न किया गया हो. लेकिन इसे इस तरह पेश किया गया मानो कोई गर्व की बात हो.

इस तरह, एक लंबे संघर्ष के बाद महिलाओं ने इस देश में जो कुछ भी हासिल किया था, वह सब वैश्वीकरण के इस अंधायुग में मटियामेट हो रहा है. पुरुष प्रधान समाज में बराबरी के दर्जे के लिए उनका सारा संघर्ष साज़िशन फिर से देह के दायरे में सिमटा कर रख दिया जा रहा है. इस पूरे खेल का मज़ा ले रहे मीडिया का दोमुंहापन देखिए कि वह महिला सशक्तीकरण का नारा लगाता हुआ बड़ी होशियारी से स्त्री को स्त्री के ही ख़िलाफ़ खड़ा करने में लगा है. इसमें सबसे कारगर हथियार बन कर आया है-रियलिटी शो.

गंगेश मिश्र

feedback@chauthiduniya.com

संस्कृति के ख़िलाफ़ है समलैंगिकता

इसमें कोई शक़ नहीं है कि फ़िलहाल देश में सबसे बड़ा मुद्दा समलैंगिकता है. समलैंगिक संबंधों को वैध-अवैध करार देने की इस बहस के मायने बहुत बड़े हैं. यह मुद्दा केवल हमारे देश के क़ानून का नहीं है, इसका असर देश की संस्कृति और तौर-तरीक़ों पर पड़ने वाला है. इस मुद्दे को केवल क़ानूनी दांव-पेंचों में उलझाकर देखना बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है. यह हमारी संस्कृति और धर्म से भी जुड़ा है. इसलिए सिर्फ़ क़ानूनी ही नहीं सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोणों की भी अनदेखी नहीं होनी चाहिए. इन्हीं दृष्टिकोणों से जनता और मीडिया को वाक़िफ़ कराने के लिए विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलिजंस के बैनर तले इकट्ठा हुए. भारत के बड़े धर्मों के धर्मगुरुओं ने इस मौके पर उपस्थित होकर मीडिया के माध्यम से अपना मत स्पष्ट रखा है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को और इसके परिणामों को समझे बिना इसका समर्थन सही नहीं होगा. इस मुद्दे को व्यक्तिगत आज़ादी से जोड़ना ग़लत है. जो बिना समझे इसके साथ हैं, उन्हें इसके पहलुओं से पहले यह समझना ज़रूरी है कि आख़िर ट्रांस-सैक्सुअल्स और होमो-सैक्सुअल्स के बीच का अंतर क्या है. ट्रांस-सैक्सुअल्स वे लोग हैं जो अलग शारीरिक प्रवृत्ति और दोहरी सैक्सुअलटी वाले होते हैं, जबकि होमोसैक्सुअल वैसे लोग हैं, जो पुरुष या महिला के तौर पर पैदा होते हैं. साथ ही सेक्सुअलिटी की पवित्रता बनाई रखनी चाहिए, क्योंकि इसका संबंध ब्रह्म से है, यह ऐसी प्रक्रिया है जिससे जीवन की उत्पत्ति होती है, और इस पावन प्रक्रिया को महज़ मनोरंजन और ख़ुद की इच्छा पूरा करने का एक साधन मात्र बना देना इसके महत्व को घटाना होगा. इस मौके पर हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन धर्मों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे और यह साफ किया कि वे क्यों समलैंगिकता को वैध ठहराने के फ़ैसले का विरोध कर रहे हैं. इस अवसर पर पुरुषोत्तम मुलोली (समन्वयक, जैक इंडिया), डॉ. के के अग्रवाल (अध्यक्ष, हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया) और एन के नौटियाल (प्रमुख, महाराष्ट्र हिंदू अकादमी) भी उपस्थित थे. इन धर्मगुरुओं को अन्य धर्मों जैसे इस्लाम, यहूदी, पारसी, सिख आदि धर्मों के प्रतिनिधियों का भी समर्थन मिला है.

पिछले कुछ दिनों में इस मामले से जुड़ी जो ख़बरें आ रही हैं, उनमें दो बातें मुख्य रूप से कही गई हैं. पहली बात जो कही जा रही है वह यह है कि धारा 377 का क़ानून 150 साल पहले का एक ब्रिटिश क़ानून है. यह बात पूरी तरह से सही नहीं है. हर क़ानून की तरह इस क़ानून की भी समीक्षा की गई है और कई आयोगों ने इसकी ज़रूरत को परखा है. इसे बचाए रखने की ज़रूरत भी महसूस की गई है. इस बात को मीडिया ने नज़रअंदाज़ किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि वे इस बात को सही तरीक़े से सामने रखेंगे. दूसरी बात हो रही है- ग़ैर-अपराधीकरण की. मुझे यह समझ में नहीं आता है कि आख़िर इसका मतलब क्या है, क्योंकि जब अपराधीकरण ही नहीं हो रहा तो ग़ैर-अपराधीकरण कैसा? अजीब बात है कि इस पूरे मामले में अपराधीकरण का एक भी उदाहरण वादी की ओर से नहीं मिल पाया. धारा 377 में कहीं भी समलैंगिकता या एमएसएम की बात नहीं है. क़ानून में साफ-साफ कहा गया है - पुरुष, महिला या जानवर के साथ अप्राकृतिक संबंध. यह क़ानून कहीं भी किसी के ख़िलाफ़ नहीं है. मैं इस मामले पर लंबे समय से लड़ता रहा हूं, 2004 में इसी दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले को ख़ारिज़ किया था और जब अपील सर्वोच्च न्यायालय में गई तो जैक इंडिया को उसमें रेस्पांडेंट बनाने का आदेश न्यायालय ने दिया. मुझे दुख के साथ यह भी कहना पड़ता है कि मीडिया ने भी इस मामले में अधूरा काम किया है. 2004 में जब यह मामला ख़ारिज़ हुआ था तो किसी ने भी इस बात को नहीं दिखाया था. लेकिन आज इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया जा रहा है. हालांकि किसी रेस्पांडेंट को मीडिया ने अपनी बहसों में नहीं बुलाया है. मेरी अपील है कि आप सभी पहलुओं को देख कर रिपोर्टिंग करें.

किसी भी सभ्यता में जब संकट आता है तो कुछ चीज़ें ज़रूर सामने आती हैं. समलैंगिकता, नशाखोरी, गैंगवार जैसे ट्रेंड उभर कर आते हैं. भारत में ये बातें विदेशी रास्ते से आ रही हैं. मेरा मानना है कि इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा बाज़ार शामिल है, जो इसे चला रहा है. न्यायालय में चल रही लड़ाई तो बस एक पहलू है, पूरा मामला बहुत बड़ा है. मेरी अपील है कि अगर आप भारतीय परिवार व्यवस्था में यक़ीन रखते हैं तो आप इस पूरे मामले को समझें और सोच-समझकर सही फ़ैसला लें.

पुरुषोत्तम मुलोली
प्रतिनिधि, समन्वयक (जैक इंडिया)

जैन धर्म में संयम पर ख़ास ज़ोर दिया गया है और संयम खोने की स्थिति में होने वाले दुष्परिणामों का भी वर्णन किया गया है. अप्राकृतिक संबंध उसी तरह की स्थिति है. समलैंगिकता के पैरोकार हमें इतिहास के उदाहरण देते हैं, लेकिन आप ही बताएं क्या अपवादों के आधार पर पूरे समाज के लिए नियम बनाए जाएंगे. आप ये बताएं कि जिस समलैंगिकता का समर्थन किया जा रहा है उसे आप के बच्चे या परिवार के लोग अपनाने लगें तो क्या आप उन्हें स्वीकार करेंगे. अगर आप इसके परिणामों पर ग़ौर करेंगे तो आप देखेंगे कि समलैंगिकता को वैधता देने का जो प्रयास हो रहा है, वह कितना ग़लत है. पारिवारिक व्यवस्था को मानने वाले लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह हमारी संस्कृति को खोखला कर देगी.

डॉ. साध्वी साधना जी महाराज
अध्यक्ष, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलिजंस और प्रतिनिधि (जैन धर्म)

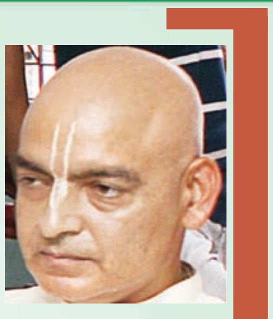

समलैंगिकता की पूरी बात ही सृष्टि के नियमों के ख़िलाफ़ है. नर और मादा का जो पूरा सिद्धांत है, वह इस पूरी सृष्टि का आधार है. अब समलैंगिकता की बात इस पूरे सिद्धांत को ही नकार रही है, इसे कैसे माना जा सकता है? संविधान निर्माताओं ने धारा 377 इसलिए रखा क्योंकि उनके हिसाब से यह अमानवीय कृत्यों को रोकती है. अब इसे हटाने का यह नया खेल समझ से परे है. इसमें कोई शक़ नहीं कि ऐसे संबंध अभी भी बनते हैं तो फिर इसे खुलेआम बाहर लाने का क्या अर्थ है? मेरी तो मीडिया, न्यायपालिका, सरकार और आम जनता से अपील है कि इस पूरे मामले को समझें. समलैंगिकता के इस पूरे शोर में असल मुद्दा दबाया जा रहा है. इस पर ध्यान दें, वरना यह हमारी संस्कृति को बहुत नुक़सान पहुंचाएगा.

महा मंत्र दास
प्रतिनिधि (हरे कृष्ण समाज)

इस क़ानूनी मुद्दे को धार्मिक और सामाजिक सदाचार से जोड़ कर देखना ग़लत है. हम लोग जो इसका कोई विरोध कर रहे हैं, यह हमारी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है. हम लोग वही बातें रख रहे हैं जो हमारे शास्त्रों और परंपराओं में कही गई हैं. हम एक बहुत बड़े समुदाय की सोच को सामने रख रहे हैं. कई ऐसे लोग हैं, जो इस घटनाक्रम से बहुत चिंतित हैं. दुख की बात है कि उनकी बात मीडिया नहीं उठा रहा है. मैं बहुत से चैनलों में गया हूं. वहां धार्मिक विचारों को किनारे कर दिया जा रहा है, लेकिन हमारी संस्कृति में धर्म को किनारे नहीं किया जा सकता.

फादर डोमनी, *प्रतिनिधि (क्रिश्चियन धर्म)*

अमेरिका, यूरोप और कनाडा जैसे देशों में पुरुष-पुरुष संबंध (एमएसएम) बनाने वाले लोगों को जीवन भर ख़ून देने की अनुमति नहीं है. वहीं स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में आख़िरी बार संबंध बनाने के एक साल तक उन्हें रक्तदान करने की मनाही है. एमएसएम को गंभीर ख़तरे वाले व्यवहारों की श्रेणी में रखा जाता है, और ख़ून पाने वाले हर व्यक्ति को यह जानने का पूरा हक़ है कि उसे ख़ून देने वाला व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो या महिला, किसी तरह के गंभीर ख़तरे वाले व्यवहार में लिप्त तो नहीं है.

डॉ. के के अग्रवाल
हृदयरोग विशेषज्ञ. अध्यक्ष, हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया

यह समय देश में संक्रमण काल का है. किसी भी देश का आधार तीन चीज़ों पर टिका होता है-साहित्य, संस्कृति और धर्म. इस समय जो हालात हैं उसमें इस आधार पर ही प्रहार हो रहा है. धर्म को आउटडेटेड करार देने का फ़ैशन-सा चला हुआ है और लगता है कि ये सब एक सुनियोजित और प्रायोजित तरीक़े से हो रहा है. किसी भी तरह से समलैंगिकता को सही नहीं ठहराया जा सकता. अगर ऐसा होता है तो इसका असर हमारी संस्कृति, हमारे भविष्य पर ग़लत तरीक़े से पड़ेगा.

महामंडलेश्वर स्वामी रघुआनंद जी
प्रतिनिधि (हिंदू धर्म)

बीमारियों को आमंत्रण देने का दूसरा नाम है समलैंगिकता

वयस्कों में सहमति से समलैंगिक यौन संबंधों को वैध ठहराए जाने संबंधी दिल्ली हाईकोर्ट के फ़ैसले पर ग़ौर करना ज़रूरी है. इस वजह से कि इस फ़ैसले को सरकार से अगर हरी झंडी मिल जाती है तो देश की जनता के स्वास्थ्य पर इसका क्या असर हो सकता है. वैसे कहा तो यह जा रहा है कि यह फ़ैसला देश में फैल रहे एचआईवी/एड्स पर लगाम लगाने की कोशिश में एक क़दम है. यहां, यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि उन देशों में जहां एड्स ने महामारी का रूप ले लिया है. इसके ज़्यादातर मरीज़ समलैंगिक संबंध बनाने वाले लोग हैं. समलैंगिक जोड़ों को साथ रहने देने की क़ानूनी सहमति देने के बहाने जिस बीमारी को रोकने की बात हो रही है, कहीं ऐसा न हो कि वही रोग भारत में भी अपना शिकंजा पूरी तरह जमा ले. ग़ौरतलब है कि अमेरिका में एचआईवी संक्रमण के पहले मामले सैन फ्रांसिस्को और दूसरे शहरों के समलैंगिकों में ही पाए गए थे. सितंबर 2006 में अमरीका की एडवोकेट होमोसेक्सुअल पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार समलैंगिक लोगों ने ख़ुद माना है कि बीस प्रतिशत समलैंगिक व्यक्ति 51-300 अलग-अलग सेक्स पार्टनरों के साथ संबंध बनाते हैं, आठ प्रतिशत समलैंगिकों के 300 से भी अधिक सेक्स संबंध होते हैं. ज़ाहिर है, ऐसे में सेक्स जनित रोगों (एसटीडी) की संभावना अधिक होती है.
दिल्ली के महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एएमएस डॉ. ममता जैन के मुताबिक गुदा के ज़रिए संभोग से रेक्टम यानी मलाशय के नाजुक तंतुओं (टिश्यूज) को काफी क्षति पहुंचती है. इससे गे बॉवल सिंड्रोम होने की आशंकाएं रहती हैं. ये उन बीमारियों के लक्षण हैं जो पुरुष-पुरुष सेक्स संबंधों में देखे जाते हैं. जैसे सिफलिस, एचआईवी इंफेक्शन, एड्स, प्रोकटाइटीस, एमीबियोसिस, वाइरल हेपेटाइटिस, लिंफोग्रेनुलोमा वेनेरम, वार्ट, गोनोरिया, इंटेस्टाइनल पारासिटिज़्म जैसी बीमारियां आदि.

सिफलिस

यह सेक्स जनित रोग (एसटीडी), ट्रेपोनेमा पैलीडम नाम के बैक्टीरिया से होता है. इसमें शरीर में बैक्टीरिया का प्रवेश दूसरे शरीर की कटी-फटी त्वचा और म्यूकस मेम्ब्रेन के रास्ते से होती है. यह सबसे ज़्यादा संभोग से फैलता है, क्योंकि इस दौरान त्वचा संपर्क में रहती है. रिसर्च में पाया गया है कि अमेरिका में सिफलिस इंफेक्शन प्रतिवर्ष 20,000 से 30,000 लोगों में होता है. इनमें सभी 20 से 29 साल के वयस्क होते हैं. 2007 के साइबरकास्ट न्यूज़ सर्विस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के फेडरल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का आंकड़ा है कि 12000 सिफलिस संक्रमित पुरुषों में तक़रीबन 65 प्रतिशत व्यक्ति समलैंगिक थे और आगे भी इसके वाहक बन रहे हैं. यह गे बाउल सिंड्रोम की एक बीमारी है और इसके बाद एचआईवी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं.

लक्षण

इस रोग के लक्षण बीमारी के स्तर पर निर्भर है. कई लोगों में इस रोग के लक्षण नज़र ही नहीं आते हैं. वैसे इसमें शरीर के कुछ हिस्से-ख़ास कर लिंफ-सूज जाते हैं और चकत्ते उभर आते हैं. ये आमतौर पर दर्दरहित होते हैं. इंफेक्शन के 2-3 हफ़्ते के बाद सोर रतिज घाव बनने शुरू हो जाते हैं. रेक्टम मलाशय या सर्विक्स गर्भाशय में होने से ये सोर नज़र नहीं आते हैं. इस स्तर को प्राइमरी सिफलिस कहते है. सोर बनने के 2-8 हफ़्ते बाद उपचार नहीं कराने पर सेकेंडरी सिफलिस हो जाते हैं. टरसियरी सिफलिस इस रोग का आख़िरी स्तर है. आख़िरी स्तर पर संक्रमण दिमाग़, नर्वस सिस्टम, हृदय, त्वचा और हड्डियों में फैल जाता है. इस बीमारी का पता लगाने के लिए ख़ून की जांच कराने की ज़रूरत होती है. इस रोग की कुछ जटिलताएं भी हैं, जैसे न्यूरोसिफलिस जिसमें हृदय और ख़ून की नलियों में परेशानियां होती है.

एड्स

अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिसिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स एक जानलेवा बीमारी है जो ह्यूमन इम्यूनो डिफीसिएंसी वायरस (एचआईवी) से होता है. शरीर में इस वायरस के आक्रमण से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र यानी बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधी क्षमता ख़त्म हो जाती है. इससे कई प्रकार के कैंसर, ट्यूमर, गैस्ट्रोइंटेस्टीनल, न्यूरोलॉजिकल, सायकोलॉजिकल और कई प्रकार के इंफेक्शन हो सकते हैं. एड्स म्यूकस मेंम्ब्रेन, स्तन के दूध, वजाइनल फ्लुईड, प्रिसेमिनल फ्लुईड से भी होता है. इसके उपचार का पता अब तक नहीं लग पाया है. सुरक्षा ही इसका बचाव है. यह ज़्यादातर असुरक्षित सेक्स से ही फैलता है. एड्स का वायरस ज़्यादातर स्पर्म में पाया जाता है. इस वजह से एनल इंटरकोर्स से भी एड्स का वायरस फैलता है. आयरलैंड के गे मेंस हेल्थ प्रोजेक्ट के सर्वे के मुताबिक आधे से ज़्यादा होमोसेक्सुअल लोग असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं. इसके अलावा वे अपने पार्टनर धड़ल्ले से बदलते रहते हैं. वर्ष 2004 के बापिस्ट प्रेस के अनुसार शिकागो विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से यह पता चल पाया है कि पुरुष होमोसेक्सुअल व्यक्ति अस्वस्थ व्यवहार और स्वच्छंद संभोग करते हैं. शिकागो के शोरलैंड में 42.9 प्रतिशत पुरुष होमोसेक्सुअल के 60 से भी ज़्यादा पार्टनर रहते हैं, जबकि बाक़ी में 18.4 प्रतिशत के 31 से 60 पार्टनर होते हैं.

वार्ट

यह भी सेक्स संक्रामक रोग है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से फैलता है. इसमें यौनांग की बाहरी त्वचा के अंदर एक गांठ सी बन जाती है, जो आमतौर पर दर्द रहित होती है. यह पुरुष होमोसेक्सुअल लोगों में ज़्यादातर होता है, जो एनल सेक्स करते हैं. इसका कोई उपचार नहीं है, बचाव के लिए इस वायरस से आक्रमण के पहले गार्डासिल वैक्सीन दिया जाए तब ही यह परेशान नहीं करता, वरना एक बार ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के शरीर में प्रवेश करने के बाद बचाव या उपाय संभव नहीं है.

अन्य आम बीमारियां

अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिपोर्ट के अनुसार गे बॉउल सिंड्रोम के तहत गोनोरिया और प्रोक्टाईटिस जैसी बीमारियां पुरुष समलैंगिकों में ज़्यादा होती है, जो एचआईवी के होने की संभावनाओं को भी बढ़ाती हैं. वर्ष 2007 के जर्नल ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार पुरुष का पुरुष से सेक्स संबंध में ये बीमारियां आम हो रही हैं. होमोसेक्सुअल लोगों में होने वाली बीमारियों में एक लिंफोग्रेनुलोमा वेनेरम है, जो ऐसे ही अप्राकृतिक सेक्स के ज़रिए फैलने वाला रोग है. वर्ष 2006 के मेडिकल जर्नल ऑफ ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में समलैंगिक संबंध रखने वाले पुरुषों में इंटेस्टाइनल पारासाइटिज़्म सबसे ज़्यादा पाया है, जिसमें बैक्टीरिया इंटेस्टाइन- जो पेट से मलद्वार तक जाती है, पर आक्रमण करता है और इसे कमज़ोर कर देता है. इसकी वजह से कई प्रकार की बीमारियां होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं. जैसे पेटदर्द, एनीमिया, विटामिन की कमी, रेक्टल क्षतिग्रस्त होना, अंधापन, सीने में दर्द, मोटापा, स्कीन अल्सर, घुटन, जोड़ों का दर्द, सिरदर्द इत्यादि. इसके अलावा एनल कैंसर की भी प्रबल आशंका होती है. एनल कार्सिनोमा भी ऐसे लोगों में आम है, जिनमें मलाशय के आस-पास गांठें बन जाती हैं. इससे ह्यूमन पैपिलोमा बीमारी भी हो जाती है जो सेक्स जनित रोग है और एचआईवी के वायरस का संचार शरीर में करने में मदद करता है.

दिमाग़ी हालत

अब तक के शोधों के मुताबिक होमोसेक्सुअल लोगों को हेट्रोसेक्सुअल लोगों के मुक़ाबले मनोरोग संबंधी परेशानियां ज़्यादा होती हैं. ऐसे लोग सुसाइड, डिप्रेशन, बुलीमिया, एंटी-सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और सबस्टांस एब्यूज के ज़्यादा शिकार होते हैं. पूर्व शोधों के मुताबिक होमोसेक्सुअल स्वभाव से ज़्यादा हिंसात्मक होते हैं. जून 2004 के जर्नल क्लिनिक्स ऑफ नार्थ अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार गे कम्युनिटी यानी समलैंगिक बिरादरी के एचआईवी पॉजीटिव लोगों में घरेलू हिंसा, पालतू जानवरों के प्रति हिंसा ज़्यादातर देखी जा सकती है.

मोटापा/स्थूलता

अमेरिका में वर्ष 2007 के परिवार उत्थान के राष्ट्रीय सर्वे में बताया गया है कि अमेरिकन लेस्बियन यानी स्त्री-स्त्री सेक्स संबंध रखने वाली महिलाओं के मोटे होने की संभावना आम महिलाओं की तुलना में ज़्यादा थीं. साथ ही इनमें अस्वस्थता और मृत्यु दर भी अधिक दर्ज़ की गई है.

रीतिका सोनाली
ritika@chauthiduniya.com

दुनिया

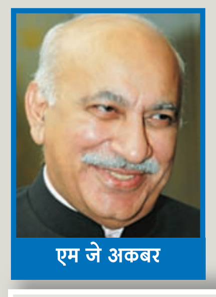

एम जे अकबर

शांति के लिए पाकिस्तान के प्रयास नाकाफी

अगर दो परमाणु ताक़तों के बीच युद्ध के बारे में सोचा नहीं जा सकता तो फिर किसके बारे में सोचा जा सकता है? आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले राज्यों ने अपना सोच-विचार कर लिया और छद्म युद्ध शुरू किया, जिसका दोष उन पर नहीं डाला जा सकता. यह भारत के लिए एक मुश्किल भरी बात है. हम एक ऐसी ताक़त हैं जो वर्तमान परिस्थिति को बनाए रखने में यक़ीन करती हैं, जिसकी उसके पड़ोसियों की ज़मीन पर नज़र लगाने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है और जिसकी सुरक्षा सेनाएं, सुरक्षा सेनाएं ही हैं कुछ और नहीं. उनका काम भारत की ज़मीन और शांति की सुरक्षा करना है. उनका आक्रमण का तरीक़ा जवाबी हमले का है, किसी पर सीधे हमले का नहीं है. जब हमने विशेष परिस्थितियों में बांग्लादेश पर हमला किया भी तो हम अपना उद्देश्य पूरा करने के चार महीने के अंदर ही वापस आ गए. हमें ज़मीन क़ब्ज़ाने की कोई इच्छा नहीं थी. दूसरी तरफ़ पाकिस्तान की सेना आज भी ऐसे युद्ध-खेल रच रही है, जिनका आख़िरी लक्ष्य कश्मीर ही है.

1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद में यह सोचा था कि थोड़ा देकर बदले में बहुत पाया जा सकता है. 1972 में इंदिरा गांधी ने भुट्टो की यह बात मान ली कि उनके समर्थन के बिना बचा-खुचा पाकिस्तान भी टूट जाएगा. इंदिरा गांधी ने एलओसी को आधार बना कर कश्मीर मुद्दे के लिखित समाधान पर ज़ोर नहीं दिया. अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान से हाथ मिलाने लाहौर पहुंचे और बदले में कारगिल पाया.

नई दिल्ली की रणनीतिक दुविधा यही है. अगर युद्ध विकल्प नहीं है तो फिर हमारे पास कौन से दूसरे विकल्प बचते हैं. हमारा दुश्मन तो इस बात को लेकर निश्चिंतता में रह सकता है कि जब तक युद्ध से ही उकसाया न जाए, तब तक भारत जवाब नहीं देगा.

हालांकि सैद्धांतिक तौर पर कोई मनमोहन सिंह के पाक के साथ शांति के प्रयास को ग़लत नहीं ठहरा सकता. भारत धीरे-धीरे उस सामुदायिक हिंसा के दौर से बाहर निकल रहा है जिसने उनके 1991 में वित्तमंत्री बनने से पहले के तीन दशकों को जकड़े रखा था. वह इस उपमहाद्वीप को कमज़ोर करने वाली, स्वनाशी से मुक्त करना चाहते हैं.

दुर्भाग्य से, शांति बहुत लचीला शब्द है. जब मनमोहन सिंह शांति के लिए प्रयास कर रहे हों तो उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि भारत और पाक दोनों एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं. क्या पाकिस्तान 60 साल पुरानी समस्या ख़त्म करने के लिए शांति चाहता है या फिर इसलिए क्योंकि उसकी सेनाएं अफ़-पाक के अमेरिकी युद्ध में व्यस्त हैं?

1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद में यह सोचा था कि थोड़ा देकर बदले में बहुत पाया जा सकता है. 1972 में इंदिरा गांधी ने भुट्टो की यह बात मान ली कि उनके समर्थन के बिना बचा-खुचा पाकिस्तान भी टूट जाएगा. इंदिरा गांधी ने एलओसी को आधार बना कर कश्मीर मुद्दे के लिखित समाधान पर ज़ोर नहीं दिया. अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान से हाथ मिलाने लाहौर पहुंचे और बदले में कारगिल पाया.

1972 में पाकिस्तान ने शांति की बात मान ली, क्योंकि उसकी सेना लड़ाई के काबिल नहीं थी. हमने उन्हें आराम और स्वास्थ्य लाभ का पूरा दशक दिया. जैसे ही 1980 में अमेरिकी मदद से (1979 में अफ़ग़ानिस्तान में सोवियत हमला हुआ था) पाकिस्तानी सेना फिर से थोड़ी ताक़तवर हुई और अपने पूर्वी मोर्चे पर उसने फिर गतिविधि शुरू कर दी. उसने पंजाब में हिंसा को हवा और आतंक को हथियार दिए. यह ऐसा इलाक़ा था जिस पर उसका भारत से कोई विवाद नहीं था. इसकी क़ीमत बहुत ज़्यादा रही- स्वर्ण मंदिर को क्षति, इंदिरा गांधी की हत्या, सिख-विरोधी दंगे. भरोसे की क़ीमत असहनीय भी हो सकती है.

डॉ. सिंह के लिए खेल शुरू हो चुका है. उन्होंने शरम-अल-शेख़ में कूटनीति की अहम चीज़ें दांव पर लगाई हैं. अब वह खेल से पीछे नहीं हट सकते. डॉ. सिंह अपने संयुक्त बयान को एक अंतरिम दांव के तौर पर समझा सकते हैं, खेल के आख़िरी पत्तों के तौर पर नहीं. ख़राब मसौदा एक बहाना है, सफाई नहीं. इस खेल में बातों की कोई अहमियत नहीं है, लिखित शब्द ही मायने रखते हैं. डॉ. सिंह या तो बड़ी बाज़ी जीतेंगे या सब कुछ खो देंगे. सच्चाई का वह समय जल्द ही आएगा. अगर वह इस्लामाबाद से 1972 में हुए एक अस्पष्ट समझौते पर कोई स्पष्ट भरोसा पाते हैं तो वह एक विजेता के तौर पर उभरेंगे. अगर ऐसा नहीं होता है तो आप इसके मायने ख़ुद समझ सकते हैं.

उन्होंने पहले ही युसूफ रज़ा गिलानी को बड़ा फ़ायदा पहुंचाया है. गिलानी की विश्वसनीयता इस कदर बढ़ी है कि वह अब ख़ुद को आसिफ अली ज़रदारी को चुनौती देने लायत समझ रहे हैं. आईएसआई- जो कम-से-कम अपने नर्म रवैए के लिए तो मशहूर नहीं है- ने एक डॉजियर तैयार कर लिया है. इसमें उसने भारत पर न सिर्फ़ बलूचिस्तान में दंगे भड़काने का, बल्कि श्रीलंकाई क्रिकेटरों पर हमले का भी आरोप मढ़ दिया है. गिलानी को अपनी राजनैतिक हैसियत बचाए रखने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा. वैसे भी अगर वह कुछ नहीं करते तो भारत क्या कर लेगा? युद्ध छेड़ देगा?

यह भूलना ग़लती होगी कि मुंबई कांड और उसके बाद आतंकवादी आकाओं के ख़िलाफ़ क़ानूनी दांव-पेंच का दिखावा, ज़रदारी-गिलानी सरकार के समय में ही हुआ है. अजमल कसाब के जुर्म क़बूलने पर रक्षा मंत्री चौधरी मुख़्तार की ओर से इस्लामाबाद की जो प्रतिक्रिया आई वह जमती नहीं- एक व्यक्ति ने भारतीय पुलिस की हिरासत में जुर्म क़बूला है. यह सबूत नहीं है. क्या मुख़्तार कसाब से तब एक बयान चाहेंगे जब उसे आईएसआई की हिरासत में बहादुरी का पदक मिल गया हो. पाकिस्तान की कोशिश अभी भी कम-से-कम करने की है, न कि ज़्यादा से ज़्यादा करने की. वह हाफिज़ सईद को गिरफ़्तार कर कोई मदद नहीं कर रहा, वह अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत मजबूरी में अपना काम कर रहा है.

भारत के साथ यह संघर्ष पाकिस्तान ने आज़ादी के महज़ छह हफ्ते के भीतर शुरू कर दिया था, क्योंकि वह कश्मीर घाटी को भारत से छीनना चाहता था. इसे ख़त्म करने का एक ही रास्ता है- एक ऐसा समझौता जिसमें पाकिस्तान कश्मीर, जो कि अब भारत का हिस्सा है, पर दावा छोड़ दे.

सूफ़ियों के बीच एक बात मशहूर है-जब आप किसी मुश्किल घेरे में फंसे हों तो उसके बाहर उससे बड़ा घेरा बना लें. यह छोटा घेरा सिकुड़ता जाएगा और सरकार का दम उसमें घुट जाएगा. इससे तभी बचा जा सकता है, अगर प्रधानमंत्री कश्मीर के हल का एक बड़ा घेरा खींच लें.

feedback@chauthiduniya.com

रवि किशोर

भारतीय समाज के अंतर्द्वंद्व

पिछले सप्ताह कई घटनाएं हुईं, जिनमें कुछ शुभ लेकिन ज़्यादातर अशुभ थीं. इनमें से अधिकतर किसी न किसी रूप में कमज़ोर समुदाय या औरतों से संबंधित हैं. इन गतिविधियों से भारतीय समाज की दिशा और समाज में व्याप्त भेदों के बारे में बहुत से सवाल उठे हैं. सबसे स्वागत योग्य फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जहां एक अहम फ़ैसले में 20 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त अनाथ लड़की- जो यौन उत्पीड़न से गर्भवती हो गई थी- को संतान पैदा करने की अनुमति दी और पंजाब और हाई कोर्ट के आदेश को उलट दिया.

दूसरे फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट दिल्ली के फ़ैसले का अनुमोदन किया, जो भारतीय दंड संहिता 377 से संबंधित है. यह सामान्य रूप से बहुसंख्यक लोगों और प्राय: सभी धर्मों के धार्मिक नेताओं के पक्ष में नहीं गया, जिनकी राय यह थी कि सुप्रीम कोर्ट को इसे ख़ारिज़ कर देना चाहिए था. इसके अलावा जो घटनाएं काफी दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक हैं, उसमें हरियाणा की पंचायत का समान गोत्र विवाह को लेकर लिया गया कड़ा फ़ैसला है. एक मामले में पति ने ज़हर खा लिया और दूसरे में लड़की के रिश्तेदारों ने उसके पति को मार दिया. एक घटना पटना की है जहां दिन-दहाड़े भीड़-भाड़ वाली गली में एक लड़की को नंगा कर दिया था और किसी ने उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की. भले ही इसके बाद बिहार सरकार ने मामले से निपटने की तमाम कोशिशें कीं.

ये सभी गंभीर मसले हैं. जहां एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट जीवन के हित में फ़ैसले लिए, वहीं दूसरे फ़ैसले में समाज के ठेकेदारों ने समान गोत्र के विवाह के संबंध में पंचायत में जो फ़ैसला लिया, वह तालिबानी और काफी कठोर था. एक तरफ़ तो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के संबंध में कोर्ट ने उदार रवैया अपनाया है, जिसने होमोसेक्सुअलिटी को वैध करार दिया (मतलब यह कि दो समान लिंग वाले वयस्कों के आपसी सहमति से हुए सेक्स) तो दूसरी तरफ़ पंचायत औरत और पुरुष के वैधानिक विवाह का विरोध करती है. सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं के मातृत्व अधिकार के बारे में कहा कि उसकी और उसके बच्चों की सहायता राज्य और समाज का अधिकार है. तीन जजों के एक बेंच- जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन ने की-का यह फ़ैसला ऐतिहासिक ही कहा जाएगा. उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 17 जुलाई के उस आदेश को ख़त्म कर दिया, जिसमें 19 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के गर्भ को गिराने को कहा गया था. सरिता (नाम बदला हुआ) नारी निकेतन में रहती थी और वहीं के सुरक्षाकर्मियों ने उसके साथ बलात्कार किया था, जिसकी वजह से उसे गर्भ रह गया था. यह घटना मार्च की है. वह अनाथ और मानसिक रूप से विक्षिप्त है. गर्भावस्था के वह 19 सप्ताह पार कर चुकी थी. मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट, 1971 के मुताबिक गर्भधारण के 20 सप्ताह बाद भ्रूण को नहीं गिराया जा सकता है. इसी वजह से कोर्ट ने सरिता के मामले में जल्द ही अहम फ़ैसला लिया. मुख्य न्यायाधीश ने चंडीगढ़ प्रशासन के वकील की यह दलील ख़ारिज़ कर दी कि सरिता बच्चे को जन्म देने का मानसिक दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकती. यह फ़ैसला देते हुए जज ने कहा कि प्रकृति के पास अपनी ताक़त होती है. चंडीगढ़ प्रशासन को सरिता को हरेक संभव मेडिकल और मनोवैज्ञानिक सहायता मुहैया कराए. बेंच में जस्टिस सदाशिवन और बी एस चौहान भी शामिल थे, जिन्होंने कहा कि एक विस्तृत फ़ैसला बाद में दिया जाएगा. कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन के वकील से पूछा कि सरिता का बलात्कार चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे नारी-निकेतन में हुआ. तो क्या यह प्रशासन का दायित्व नहीं कि वह आनेवाले बच्चे की देखभाल करे.

माननीय सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला दरअसल हरेक तरह से सराहनीय है. नागरिकों के तौर पर हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी न्यायिक व्यवस्था ने न केवल उच्चतम मूल्यों को बरक़रार रखा है, बल्कि बारहां इसका मानवीय पहलू भी उजागर किया है.

सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फ़ैसला हालांकि निराश करने वाला है जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट की धारा 377 संबंधी फ़ैसले पर रोक नहीं लगाई गई. हालांकि इस मसले पर अधिक विचार और गंभीर चिंतन की ज़रूरत है. ख़ासकर भारतीय समाज और इसकी नैतिकता के संदर्भ में. इस मुद्दे पर इस कॉलम में पहले भी चर्चा की गई है और *चौथी दुनिया* ने अपने पहले के अंकों में इस मसले पर विस्तार से चर्चा की है. मेरे नज़रिए से तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली हाईकोर्ट के फ़ैसले पर रोक लगा देनी चाहिए. साथ ही केंद्र सरकार को विस्तृत जवाब या हलफ़नामे के लिए समय देना चाहिए. इससे सभी संबंधित एजेंसियों को इस विषय पर गहराई से और विस्तार से सोचने का मौका मिल जाता.

एक ही गोत्र में विवाह के मसले पर अगर बात करें, तो यह सचमुच निराशाजनक है कि कोई पंचायत सगोत्रीय विवाह पर तालिबानी फ़रमान जारी कर दे और उसकी वजह से हत्या और आत्मघात की नौबत आ जाए. यह सचमुच ही द्वंद्वात्मक हालत है कि एक तरफ़ तो समाज समलैंगिकता को वैध करने पर बहस करे और हम गे-परेड और समलैंगिक विवाहों पर उत्सव मनाएं, जबकि दूसरी ओर पंचायती फ़रमान का विरोध भी न किया जाए. इस विवाद की जड़ दरअसल हिंदू समाज की गोत्र-व्यवस्था में है, जहां माना जाता है कि एक ही गोत्र के लोग समान गुरु के वंशज होते हैं और सगोत्रीय विवाह नहीं होने चाहिए. हालांकि यह हिंदू समाज की आंतरिक सोच है और हिंदू मैरिज एक्ट में इसकी कोई मनाही नहीं है.

हिंदू मैरिज एक्ट में जिसकी मनाही है, वह सपिंद संबंधों की है. हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3 (एफ) (एक) में सपिंदा संबंधों की व्याख्या कुछ ऐसे की गई है:-

ये संबंध किसी भी वैसे व्यक्ति के संदर्भ में हैं, जो माता की तरफ़ से तीसरी पीढ़ी तक और पिता की तरफ़ से पांचवीं पीढ़ी तक जाता है. हरेक मामले में यह पीढ़ीगत रेखा संबंधित व्यक्ति से तय होती है, जिसे पहली पीढ़ी का माना जाता है.

इसके अलावा विरासत के मामले में किसी तरह के संबंधों की मनाही नहीं है. इसी बात को दिल्ली की एक कोर्ट में भी दुहराया गया, जिससे एक नवविवाहित युगल को राहत मिली. उस विवाह का विरोध भी एक ही गोत्र के होने के आधार पर किया गया था.

दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने हिंदू मैरिज एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि सगोत्रीय विवाहों पर किसी तरह की रोक नहीं है. फ़ैसले में कहा गया कि इसकी कोई वजह नहीं दिखती कि दो लोग अगर प्यार में हैं और सपिंदा नहीं हैं, तो उनको शादी की इजाज़त क्यों नहीं दी जाए. कोर्ट ने व्यवस्था दी कि गोत्र का आधार ही किसी की विरासत को तय करने में है और ऐसी व्यवस्थाओं का उद्देश्य किसी एक को फ़ायदा पहुंचाना है, न कि उनकी ख़ुशी की राह में बाधा पैदा करना है. दो व्यक्तियों के बीच शादी बिल्कुल व्यक्तिगत पसंद पर आधारित है, जिसका समाज को सम्मान करना चाहिए. अगर इसमें कोई क़ानूनी बाधा नहीं है, तो उसके बाद यह सुनिश्चित करना न्यायलय का काम है कि युगल को उनके फ़ैसले के आधार पर परेशान नहीं किया जाए. कोर्ट ने यह भी कहा कि इसमें क़ानून की बेहद तकनीकी व्याख्या कर कोर्ट को एक पक्ष नहीं बनना चाहिए. इसीलिए राज्य को अपने प्रशासन के तहत यह सुनिश्चित करना चाहिए की पंचायत के अंधे फ़रमान क़ानूनी नहीं और उनको हमारे क़ानून के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा होना चाहिए. हालांकि, दुर्भाग्य से राज्य सरकार ने इस हद तक काम नहीं किया और पंचायत के डर से उचित कार्रवाई नहीं की. राज्य अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करने में विफल रहा.

इसी तरह, पटना में दिनदहाड़े कुछ गुंडों ने एक औरत को नंगा करने की कोशिश की. वहां वह राज्य अपने नागरिकों की रक्षा करने में असफल रहा. हालांकि, नीतीश कुमार की वर्तमान सरकार ने राज्य की क़ानून-व्यवस्था में काफी हद तक सुधार किया है, लेकिन इस ख़ास घटना में राज्य सरकार विफल रही. इससे भी आश्चर्यजनक तो ऐसी घटनाओं के प्रति सार्वजनिक उदासीनता है. यह घटना सैकड़ों लोगों के सामने हुई और कोई भी उस बेचारी लड़की को बचाने के लिए आगे नहीं आया. तो क्या हम दूसरों के प्रति पूरी तरह असंवेदनशील और असहिष्णु हो गए हैं?

ऊपर की दोनों घटनाएं अलग राज्यों की हैं, जहां की राज्य सरकारें असफल रही हैं. इसके साथ ही यह आमतौर पर सामान्य सामाजिक व्यवस्था के असफल होने को भी रेखांकित करता है. यह सचमुच ही हमारे समाज और राजनीति की दुखद हालत को दिखाता है.

(लेखक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं)

feedback@chauthiduniya.com

प्रिय संपादक जी,

आपका साप्ताहिक अख़बार ***चौथी दुनिया*** के बारे में केवल सुनता था, मगर आज देखने का मौका मिल गया. मैंने 2 अगस्त वाला अंक देखा. बहुत बढ़िया लगा. आवरण कथा बहुत अच्छी लगी. कोई भी जगह हो या देश, आतंकवाद से ग्रसित है और आतंकवाद के कारण किसी देश का विकसित होना संभव नहीं है. आतंकवाद कैसे पनपता है और कैसे फैलता है, इसके बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया. आतंकवाद को ख़त्म करने में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी उजागर की गई, जिसके बारे में मैं अभी तक अनजान था. साथ ही यह भी जानकारी मिली कि दुनिया भर में कितने देशों के पास कितने परमाणु बम हैं. सभी कारण अपने आप में पूर्ण थे, क्योंकि आतंकवाद को बढ़ावा देने में यही कारण होते हैं जो आपके अख़बार में छपे हैं. ***अपराध दुनिया*** में सिस्टर अभया हत्याकांड से उठाया गया पर्दा चकित करने वाला रहा. कितनी अजीब बात है कि 17 साल तक सिस्टर अभया के हत्यारे, जिसकी हत्या के मामले को दबा दिया गया था, छिपे बैठे थे वे कोई और नहीं बल्कि उसी चर्च के फादर थे. इसने मुझे पूरी तरह झकझोर दिया. साथ ही सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं भी इंसानियत नाम की चीज़ नहीं बची है. यह बहुत ही खोजपरक और रोचक स्टोरी लगी. आशा है कि आप इस तरह की सामाजिक बुराइयों और भ्रष्टाचारों के मामले को उजागर करते रहेंगे. आपका साहित्य और खेल पन्ना भी विशिष्ट है.

आपका

उदय

दिल्ली

दुनिया

जब तोप मुक़ाबिल हो

सरकार के साथ विपक्ष भी बने ज़िम्मेदार

यहां सवाल उठता है कि क्या भाजपा एक मज़बूत विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है? इसका जवाब तलाशने के लिए अधिक दूर जाने की ज़रूरत नहीं है. हम अगर नई सरकार के बनने के बाद से संसद में भाजपा की भूमिका देखें, तो बड़े आराम से इस सवाल का जवाब मिल सकता है-वह भी न में.

एक स्वस्थ और बेहतर लोकतंत्र के लिए ज़रूरी क्या है? अगर हम लोकशाही को सफल बनाना चाहते हैं, तो एक बेहतर सरकार तो ज़रूरी है ही. इसके अलावा, एक मज़बूत और ज़िम्मेदार विपक्ष भी बहुत आवश्यक है. आख़िर लोकशाही के और मायने भी क्या हैं? अगर हमारे विपक्षी दल कमज़ोर रहेंगे, तो सरकार को जगाएगा कौन? विपक्ष का काम सदन चलाने में सहयोग देने से लेकर सरकारी नीतियों पर सवाल पूछने और आम जन के हित के लिए सरकार को नीतियां बनाने पर मजबूर करना भी है. लोकतंत्र आख़िर पक्ष-विपक्ष के बेहतर समन्वय और संयोजन से ही तो चलता है. अगर विपक्ष ज़िम्मेदार नहीं हुआ, तो सत्तापक्ष के तानाशाह हो जाने का ख़तरा है. सत्ताधारी दल निरंकुश हो सकता है और अपनी मर्जी से तमाम फ़ैसले ले सकता है. इसी तरह अगर विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध करता है, तब भी लोकशाही की मूल भावना आहत होती है. अगर जनता के हित के लिए सरकार कोई फ़ैसला लेती है, तो विपक्ष को उसका साथ भी देना चाहिए. सरकार के पास अगर कम सांसद हैं, तो विपक्षी दल के समर्थन से ही तो आवश्यक कोरम पूरा होगा. बात बस इतनी सी है कि लोकशाही के सफल होने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों को ही अपने कर्तव्य और ज़िम्मेदारी का अहसास होना चाहिए. अब यहां सवाल उठता है कि क्या भाजपा एक मज़बूत विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है? इसका जवाब तलाशने के लिए अधिक दूर जाने की ज़रूरत नहीं है. हम अगर नई सरकार के बनने के बाद से संसद में भाजपा की भूमिका देखें, तो बड़े आराम से इस सवाल का जवाब मिल सकता है-वह भी न में.

भाजपा ने इस सत्र में संसद में एक बार बहिष्कार किया, वह भी भारत-पाक साझा घोषणापत्र और बलूचिस्तान के मसले पर. भाजपा नेतृत्व को यह समझ ही नहीं आया कि हमारी आंतरिक राजनीति अलग है, अंतरराष्ट्रीय मसलों पर व्यापक सहमति एक दूसरी बात है. जिस तरह प्रधानमंत्री को इस मसले पर घेरने की कोशिश की गई, उससे कहीं न कहीं यह संदेश जाता है कि अंतरराष्ट्रीय मसलों पर भी हमारे यहीं व्यापक सहमति नहीं है. प्रधानमंत्री को कमज़ोर बताना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाता है. महाभारत की कथा है कि गंधर्वों के राजा ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था, तो युधिष्ठिर ने पांडवों को उसकी रक्षा का आदेश दिया था. भीम और अर्जुन के सवाल पूछने पर उनका यही जवाब था कि हमारी लड़ाई और मतभेद हमारे हैं, लेकिन बाहर वालों के लिए तो हम 105 भाई ही हैं-वयं पंचाधिकम शतम्.

यह नीति हमारी संसद के लिए भी सही है. हमारे आपस में चाहे जो भी मतभेद हों, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो व्यापक सहमति और एकता दिखनी ही चाहिए. भाजपा दरअसल अब

जल, ज़मीन और जंगल ख़तरे में हैं. देश के दो सौ से अधिक ज़िले अशांत हैं और नक्सल-प्रभावित हैं. रोज़मर्रा की ज़रूरतों की क़ीमतें आसमान छू रही हैं और मानसून की देरी से आम आदमी के और भी प्रभावित होने की आशंका है. भाजपा के पास ज़ाहिर तौर पर मुद्दों की कमी नहीं थी, राजनीतिक इच्छाशक्ति होने पर वह सरकार को आसानी से घेर सकती थी.

तक अपनी हार पचा ही नहीं पाई है. जो पार्टी ख़ुद ही मतभेदों में उलझी हो, वह सरकार को भला किस मुद्दे पर और कैसे घेरेगी. इस बार तो यही काम ममता बनर्जी कर रही हैं. जब भूमि-अधिग्रहण के मसले पर उन्होंने बहिष्कार किया, तो लगा कि वही विपक्षी दल की भूमिका में हैं.

इसी तरह, अगर पिछली बार की सरकार का दौर याद करें, तो वाम-दलों ने ही विपक्ष की भूमिका निभाई थी. कई मसलों पर सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे वाम मोर्चे ने ही घेरा था, जबकि भाजपा के सांसद अपनी ही दुनिया में मग्न थे. इस बार वाम दल भी अपनी हार के सदमे में हैं. भाजपा तो ख़ैर अपने ग़म से उबर ही नहीं पाई है. हार के बाद पार्टी के अंदर ही जिस तरह घमासान चल रहा है, उसमें विपक्ष की भूमिका शायद उसे याद ही नहीं रही है. भाजपा के पास ऐसे कई मसले थे, जिन पर वह सरकार को चेता सकती थी, उसे संसद में घेर सकती थी और सवाल उठा सकती थी. भाजपा ने ये सब कुछ भी नहीं किया, जब सरकार को घेरा भी तो शरम-अल-शेख के मसले पर. भाजपा की करनी से तो यही लगा कि देश में और आम जनता के हित के मसले ही ख़त्म हो गए हैं. तभी तो सरकार को घेरने के लिए उसे अंतरराष्ट्रीय मसलों की ज़रूरत है. इस बात से कोई इंकार नहीं कि विपक्ष को कई मसलों पर सरकार को घेरने का अधिकार है, लेकिन सबसे ज़रूरी तो यह है कि आम आदमी से जुड़े मसलों और उनकी भलाई के मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही तय करे.

जल, ज़मीन और जंगल ख़तरे में हैं. देश के दो सौ से अधिक ज़िले अशांत हैं और नक्सल-प्रभावित हैं. रोज़मर्रा की ज़रूरतों की क़ीमतें आसमान छू रही हैं और मानसून की देरी से आम आदमी के और भी प्रभावित होने की आशंका है. भाजपा के पास ज़ाहिर तौर पर मुद्दों की कमी नहीं थी, राजनीतिक इच्छाशक्ति होने पर वह सरकार को आसानी से घेर सकती थी. आम आदमी से सरोकार रखने वाले मसलों को अगर वह उठाती, तो उसे समर्थन भी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन भाजपा का प्रदर्शन बताता है कि वह ख़ुद ही आम आदमी के सरोकार भूल चुकी है और इसी वजह से उसके मसले उठाना भी उसे याद नहीं रहा है. रेल बजट के साथ ही आम बजट भी पेश हुआ. भाजपा के पास ये दोनों मौके थे, जब वह कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकती थी. उसने यही काम नहीं किया.

भाजपा दरअसल इनर्शिया में चली गई है. अपनी हार उसे हज़म ही नहीं हुई. वह आपसी लड़ाई और रंज़िश का शिकार हो गई है. वह सरकार को घेर नहीं पा रही. यह हालत हमारे लोकतंत्र के लिए सुखद नहीं कही जा सकती. लोकशाही की सफलता के लिए ज़रूरी है कि विपक्ष अपने कर्तव्य को समझे और उसी तरह आचरण करे.

संपादक

editor.chauthiduniya.com

काराकोरम दे सकता है आतंकवाद से निजात

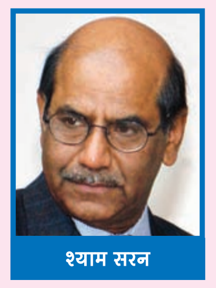

श्याम सरन

आप अगर इस विशाल और दुष्कर पर्वत शृंखला को देखिए- जिसकी गोद में काराकोरम के पहाड़ अपनी पूरी आभा के साथ मौजूद है- तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ऐसे भौगोलिक दृश्य को आप दुनिया में कहीं नहीं देख सकते. यहां छह प्रमुख पर्वत शृंखलाएं एक-दूसरे से मिलती हैं. अफ़ग़ानिस्तान के उत्तर में विशाल हिंदुकुश पर्वत है. इसे उत्तर में काटते हुए ऑक्सस घाटी बनाते हुई ऊंची मीनारों की तरह पामीर का पहाड़ मानो अपनी बाहें फैलाए सबको बुलाता है. मुज़तगाता की चोटी उसे वाकई में हिमशिखरों के पिता की उपाधि देता है. अरब के लोग पामीर को बम-ए-दुनिया या दुनिया की छत की उपाधि से नवाजते हैं. कुनलुन पर्वत शृंखला पश्चिम से आकर पामीर से मिलती है, जिससे दक्षिणी चीन का हिस्सा निकला है, इन तीनों पर्वत शृंखलाओं- हिंदुकुश, पामीर और कुनलुन के बीच बना कोण ही हमारा काराकोरम है, जिसे भूगोलशास्त्री सर्वोच्च मानते हैं. वास्तव में काराकोरम, हिमालय पर्वत शृंखला के पश्चिमी फैलाव से जुड़ा है और पीर पंजाल से जुड़ा है, जिसके बीच में कश्मीर घाटी है.

हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम इस इलाक़े की ताक़त को समझें, ऐतिहासिक भूमिका को याद करें, आपसी व्यापार को बढ़ाएं और साझा संस्कृति को समझें. हमें उन कॉरीडोर को बनाने की ज़रूरत है, जो सदियों से काराकोरम को आपसी आदान-प्रदान का ज़रिया बनाए हुए था. हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई बार कहा है कि हम शायद अपनी राजनीतिक दूरी और रेखांकन को न मिटा सकें, लेकिन हम अपने पड़ोसियों तक नए तरीक़े से ज़रूर पहुंच सकते हैं.

पर्वतों के ये बंधन दुनिया के सिरे पर मौजूद हैं. यहीं इसका गुरुत्व केंद्र है या फिर वह धुरी कह सकते हैं, जिसके इर्द-गिर्द यह चक्कर काटता है. छह सौ मील लंबा और तीन सौ मील चौड़ा यह भू-भाग अपने फैलाव में जर्मनी या फिर फ्रांस जितना है.

काराकोरम की सबसे ख़ास बात यह है कि दुर्गम घाटियों और कठोर वातावरण के बावजूद इस पर्वत शृंखला ने अपनी गोद में कई समृद्ध संस्कृतियों को जन्म दिया. वे संस्कृतियां सदियों से यहां की उपजाऊ घाटियों और मरुद्यानों पर बसी हैं. बेहद कठोर पहाड़ियों के बावजूद प्राचीन व्यापार और धर्मयात्राएं इन पहाड़ियों के बीच से होकर गुज़रती थीं. अलग-अलग संस्कृतियां जो इस ज़मीन को अपना मानती हैं, एक लंबे अर्से से बग़ैर किसी लड़ाई-झगड़े के एक साथ रहती हैं. साम्राज्यों और शक्तिशाली देशों ने भले ही इस पूरे इलाक़े में निशानदेही कर रखी हो, लेकिन यहां की संस्कृतियां कभी भी किसी एक राजनीतिक शक्ति के अधीन नहीं रहीं, क्योंकि वे राष्ट्र-राज्य की सबसे प्रमुख सरहद और सीमा को हमेशा लांघती रही हैं.

यह क्षेत्र भले ही सामुदायिक स्तर पर एक पहेली की तरह है, लेकिन यहां की सांस्कृतिक धरोहर बहुत ही धनी है. यह धरोहर दुनिया भर के प्रमुख धर्म- हिंदू, बौद्ध, इस्लाम और यहां तक की जरथुष्ट्र के उतार-चढ़ाव के बीच सृजित हुई है. सभी धर्मों को यहां की प्राचीन जीवनशैली को अपनाना पड़ा. व्यापार के प्राचीन रास्ते से गुज़रने वाले कारवां के चलते यहां कई छोटी संस्कृतियां उपजीं लेकिन इन धर्मों के प्रभावों के बीच उपजी यहां की प्रमुख संस्कृति को उखाड़ना इतना आसान नहीं है.

यह वही धरोहर है, जिस पर आज इतना ज़्यादा दबाव है कि वह अपनी पहचान खोने के कगार पर है. यह ख़तरा ख़ास तौर पर यहां की समृद्ध संस्कृति पर है, जिसकी अपनी विविधता पर प्रहार हो रहा है. जबकि यहां के समुदाय अपनी सांस्कृतिक और भाषाई धरोहर पर गर्व महसूस करते हैं.

यह पूरा इलाक़ा बेहद तेज़ी से जलवायु परिवर्तन का शिकार हो रहा है और यह इस पूरे क्षेत्र में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तनाव को ही बढ़ाएगा, जो पहले ही यहां अशांति का सबब बने हुए हैं. हम अभी इस इलाक़े में जो कुछ भी देख रहे हैं, वह मूल तौर पर कई तरह के तनावों- राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण से जुड़े तनाव- का ही असर हैं. बात चाहे हम स्वात या बुनेर की करें, वजीरिस्तान या हेलमंड की करें, बलूचिस्तान या जिनजियांग की करें. हम इन्हीं दबावों का असर भारत के अपने सीमांत इलाक़ों जैसे जम्मू और कश्मीर में भी देख सकते हैं.

आख़िर भारत के लिए काराकोरम के विविध समुदायों का भाग्य क्यों मायने रखता है? एक तो, इस अस्थिर इलाक़े को लेकर बेहद साफ शंकाएं भारत पर असर डालती हैं. दूजे इन इलाक़ों और लोगों को लेकर बेहद साफ और भारतीय हितों के मद्देनज़र अहम चिंताएं हैं. साथ ही उन इलाक़ों की भी चिंताएं हैं, जो हैं तो भारत का हिस्सा पर अवैध तौर पर किसी और ने उन पर क़ब्ज़ा किया हुआ है. हालांकि, इन सबसे अहम एक और चिंता है- भारत के दरवाज़े पर कट्टरतावाद, असहिष्णुता और अलगाववाद के ज्वार का मतलब क्या है? हमारे बहुलतावादी लोकतंत्र पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसीलिए काराकोरम के समुदायों के भाग्य और भारत के एक बहुलतावादी देश के होने में क्या आपसी संबंध है? हमें इस इलाक़े में ज़ाहिर तौर पर केवल सांकेतिक तौर पर ही नहीं, बल्कि काफी सक्रिय तौर पर काम करने की ज़रूरत है. साथ ही, मैं तो यह भी कहूंगा कि चुनौती झेल रहे इन समुदायों की मदद करने की ज़रूरत है.

क्या हम यह कह सकते हैं कि वापस हम उसी काल्पनिक या वास्तविक भूतकाल की तरफ लौटें, जिसमें शांति, भाईचारे और समृद्धि की बात की गई है? हमारे ख़याल से यह काम नहीं करेगा. हमें तो सामयिक संदर्भों में बात करने की, इलाक़े की ताक़त को समझने और व्यापार व आपसी समझौते को जानने की ज़रूरत है.

हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम इस इलाक़े की ताक़त को समझें, ऐतिहासिक भूमिका को याद करें, आपसी व्यापार को बढ़ाएं और साझा संस्कृति को समझें. हमें उन कॉरीडोर को बनाने की ज़रूरत है, जो सदियों से काराकोरम को आपसी आदान-प्रदान का ज़रिया बनाए हुए था. हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई बार कहा है कि हम शायद अपनी राजनीतिक दूरी और रेखांकन को न मिटा सकें, लेकिन हम अपने पड़ोसियों तक नए तरीक़े से ज़रूर पहुंच सकते हैं. हम लोगों का आना-जाना आसान बना सकते हैं और विचारों के आदान-प्रदान के साथ व्यापार को भी बढ़ा सकते हैं. अगर हम पुराने व्यापारिक रास्तों को खोल दें, तो कंधार के अनार एक बार फिर उत्तर भारत के बाज़ारों की शोभा बढ़ा सकते हैं. इसी तरह इलाक़े में समृद्धि आ सकती है. ज़रा सोच कर देखिए, इससे इस इलाक़े के लोगों की ग़रीबी कैसे दूर हो सकती है, जो अभी ड्रग्स माफ़िया का शिकार बनने को मजबूर हैं, क्योंकि उनको रोज़गार का कोई न कोई ज़रिया तो चाहिए ही.

भारत ने इस मामले में बढ़त बना ली है. नियंत्रण रेखा के इधर-उधर व्यापार, श्रीनगर और मुज़फ्फराबाद के बीच बस सेवा, पुंछ और रावलकोट के बीच परिवहन और इस तरह की कई शुरुआतों के ज़रिए भारत ने लोगों को फिर से जोड़ने की दिशा में सकारात्मक पहलक़दमी कर दी है. हम तो कारगिल-स्कार्दु के बीच भी यातायात खोलने की मांग कर रहे हैं, ताकि आख़िरकार पूरी तरह से संचार और यातायात व्यवस्था जारी हो सके. यह न केवल एक मानवीय लक्ष्य पूरा करेगा, बल्कि अतिवाद और आतंकवाद के विषाणु को भी रोक सकता है.

इस संदर्भ में मैं ज़ोर देकर कहना चाहूंगा कि जम्मू और कश्मीर के मसले पर भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी बातचीत में हमेशा यह कहा है कि नियंत्रण रेखा के पार सारे यातायात को खोल दिया जाए. ख़ास इलाक़ों में सहयोग को बढ़ाया जाए और पूरे जम्मू-कश्मीर में आवागमन आसान हो. इसमें गिलगित और बाल्टिस्तान भी शामिल हैं. नियंत्रण रेखा के पार किसी भी तरह का राजनैतिक संबंध स्वशासित और प्रतिनिधि लोगों के ज़रिए हो सकता है और ज़ाहिर है कि इसमें भी गिलगित और बाल्टिस्तान शामिल हैं.

अंत में, एक बार फिर यही दोहराना चाहूंगा कि कोई भी समाधान बातचीत के ज़रिए ही हो सकता है और हरेक समस्या का मानवीय पहलू निकाले जाने पर ज़ोर दिया जाना चाहिए. आख़िरकार, युद्ध भी किसी समस्या का समाधान नहीं है.

(लेखक प्रधानमंत्री के विशेष दूत हैं)

feedback@chauthiduniya.com

ख़ुफ़िया एजेंसियों के सीक्रेट

एफबीआई बनाम अमेरिकी जनता का दुश्मन नंबर एक

एफबीआई भले ही आज अमेरिका की सबसे ताक़तवर जांच एजेंसी है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था. अपनी स्थापना के बाद एफबीआई ने अपराधियों के ख़िलाफ़ अपनी सफलताओं से अपनी जगह बनाई. इस दौरान उसका सामना कई बार अपराध की दुनिया के सबसे शातिर खिलाड़ियों से भी हुआ. एफबीआई की कहानी की इस कड़ी में बात एक ऐसे ही पब्लिक एनिमी की.

पावस नीर

एक जुलाई 2009 को अमेरिकी सिनेमाघरों में एक फिल्म रिलीज हुई. फिल्म का नाम है-पब्लिक एनिमीज. जॉनी डेप और क्रिश्चियन बेल जैसे बड़े अमेरिकी सितारों वाली यह फिल्म 1930 के दशक के अमेरिकी अपराध जगत की कहानी पर आधारित है. यह एक ऐसा दौर था, जब अमेरिका में अपराध सबसे ऊंचाई पर था. यही वह दौर था, जब अमेरिका में एफबीआई नाम की एक नई संघीय जांच एजेंसी का गठन हुआ था. इसके मुखिया एडगर जे हूवर इस एजेंसी को मज़बूत करने की कोशिश में जुटे थे. हालांकि उनकी राह में कई रोड़े थे. उनका राज्यों में चल रही आपराधिक गतिविधियों पर कोई ज़ोर नहीं चलता था. कहने को तो पूरे देश में छानबीन का अधिकार उसके पास था लेकिन कुछ ही क़ानून ऐसे थे, जिनके तहत एफबीआई उसके लोगों को गिरफ़्तार कर सकती थी. अपराधी एक राज्य में अपराध कर दूसरे में छुप जाते थे और एफबीआई देखती रह जाती थी.

1930 का दशक अमेरिकी अपराध के इतिहास में सबसे ख़तरनाक दशक था. इसी दशक में आर्थिक मंदी ने अमेरिकियों की कमर तोड़ दी थी. लाखों लोग बेरोज़गार हो गए थे और इनमें से कई अपराध की ओर मुड़ चुके थे. दूसरी ओर रंगभेदी अपराध भी तेज़ हो चुके थे. कु-क्लक्स-क्लान अश्वेतों को निशाना बना रहा था. एफबीआई इन अपराधों के ख़िलाफ़ मूकदर्शक बनी बैठी थी क्योंकि उसके पास इन अपराधियों को पकड़ने की ताक़त ही नहीं थी.

इसी समय अमेरिकी अपराध जगत के सबसे कुख्यात मुजरिम भी उभरे. बैंक लुटेरों, हत्यारों और क़ानून तोड़ने वालों की इस फेरहिस्त में प्रेटी बॉय फ्लॉयड, बेबी फेस नेल्सन और वैन मीटर जैसे नाम शामिल थे. इन अपराधियों को पुलिस ने नाम दिया था-पब्लिक एनिमीज. इन पब्लिक एनिमीज की फेरहिस्त में जो नाम सबसे ऊपर था, वह एक बैंक लुटेरे का था. नाम था- जॉन डिलिंगर. मध्य-पश्चिम अमेरिका की पुलिस फोर्सेज के बीच आतंक का पर्याय बन चुका जॉन डिलिंगर उस समय कई राज्यों में पब्लिक एनिमी नंबर वन था.

डिलिंगर उस ज़माने के दूसरे अपराधियों की तरह ही एक बैंक लुटेरा था, लेकिन इसके दौरान उसने कई हत्याएं भी की थीं. हालांकि इसके बावजूद जनता उसे पसंद करती थी. दरअसल डिलिंगर अमेरिकी जनता के लिए 20वीं सदी के रॉबिन हुड की तरह था. वह बैंकों को लूटता था. बैंक उस समय मंदी की मार झेल रहे जनता के लिए उस आर्थिक व्यवस्था का प्रतीक थे, जिसने उन्हें बर्बाद किया था. डिलिंगर का बैंक लूटना जनता को एक बदले जैसा लगता था. डिलिंगर का बैंक लूटने का तरीक़ा किसी फिल्मी लूट जैसा था. बिना किसी हड़बड़ाहट के बैंक लूटने की इस आदत के कारण लोगों ने उसे जैकरैबिट (बहुत तेज़ और बिना हड़बड़ाहट के भागने वाला जानवर) का नाम दिया था.

पब्लिक एनिमी नंबर एक- जॉन डिलिंगर, एफबीआई द्वारा डिलिंगर को पकड़ने के लिए लगाया गया इनामी पोस्टर(दाएं)

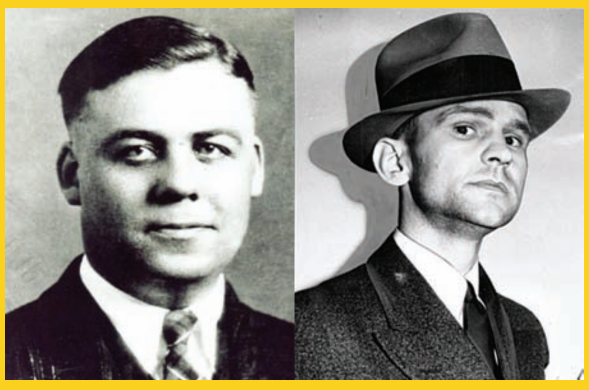
एफबीआई के ख़ास एजेंट काउली (बाएं) और पर्विस

डिलिंगर का पूरा व्यक्तित्व ही एक मिथक सरीखा था. अपनी पहली ही चोरी में पकड़े जाने के बाद उसने सुधरने की सोची और अपना अपराध क़बूल लिया. उसे 12 साल की सज़ा मिली. वहीं उसके जिन साथियों ने अपराध नहीं कबूला था, उन्हें बस दो साल की सज़ा हुई. इस बात ने उसे गुस्से से भर दिया. जब साढ़े आठ साल बाद 1933 में वह रिहा हुआ तो उसने सिलसिलेवार ढंग से बैंक लूटने शुरु कर दिए. वह फिर से पकड़ा गया. उसके पास एक नक़्शा बरामद हुआ जिसमें किसी जेल से भागने का रास्ता था. चार दिन बाद उसी योजना से आठ लोग इंडियाना राज्य की जेल से भाग निकले.

अगला काम था जॉन डिलिंगर को बाहर निकालने का -12 अक्टूबर 1933- ओहायो राज्य के लीमा में जेल के अधिकारी के पास चार लोग पहुंचे. उन्होंने अधिकारी को बताया कि वे वहीं बंद डिलिंगर को इंडियाना जेल ले जाने के लिए लेने आए हैं- वहां के अधिकारी ने उनसे पहचान पत्र मांगा-उनमें से एक ने अपनी बंदूक निकाली-उसने कहा *ये रहा मेरा आई डी*-अधिकारी को गोली मारकर वे जॉन डिलिंगर को लेकर भाग गए. उसके बाद इस गैंग ने कई बैंकों को लूटा और कई लोगों की हत्या भी की. राज्य सरकारें उन्हें पकड़ नहीं पा रही थीं. एफबीआई कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि बैंक लूट राज्यों के मामले थे. हूवर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी.

इस बीच जनवरी 1934 में डिलिंगर फिर से पुलिस की गिरफ़्त में आ गया. इस बार उसे ऐसी सुरक्षा में रखा गया, जिसे पुलिस के मुकाबिक तोड़ा नहीं जा सकता था. एक महीने बाद डिलिंगर इस जेल से भाग निकला. उसने एक सिपाही को रिवॉल्वर भिड़ाई और उसके हथियार लेकर भाग गया. बाद में उस सिपाही ने देखा कि वह रिवॉल्वर दरअसल लकड़ी का एक टुकड़ा भर थी. हालांकि इस बार डिलिंगर ने ऐसी ग़लती कर दी जो आगे चलकर उसके लिए भारी साबित होने वाली थी. उसने एक पुलिस कार चुराकर राज्य की सीमा पार की. यह राष्ट्रीय मोटर सुरक्षा क़ानून के ख़िलाफ़ था. यह क़ानून एफबीआई के अधिकार क्षेत्र में था.

आख़िरकार एफबीआई को वह मौका मिल गया जिसकी उसे तलाश थी. अब एफबीआई डिलिंगर के पीछे थी. हालांकि कई बार डिलिंगर उसे चकमा देने में सफल रहा, लेकिन उसकी प्रेमिका और कई साथी पकड़े गए. अब डिलिंगर उस ज़माने के कुख्यात अपराधियों बेबी फेस नेल्सन और वैन मीटर के साथ काम कर रहा था. हूवर ने स्पेशल एजेंट काउली और मेल्विन पर्विस को डिलिंगर को पकड़ने का ज़िम्मा सौंपा. इससे पहले कुख्यात अपराधियों *बोनी और क्लाइड* को मारने वालों में से एक चार्ल्स बी वेंस्टेड को भी बुलाया गया.

21 जुलाई 1934 को एक वेश्यालय की मालकिन एन सेज ने एफबीआई से संपर्क साधा. उसके मुताबिक डिलिंगर उसकी एक लड़की पॉली हेमिल्टन के साथ था. अगले दिन वे दोनों फिल्म देखने जाने वाले थे. काउली और पर्विस ने सेज के साथ एक संकेत तय किया. अगले दिन डिलिंगर और पॉली फिल्म देखने बायोग्राफ थिएटर पहुंचे. पॉली ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, जो एन सेज ने उसे इस मौके के लिए ख़ास उपहार दिए थे. लाल रंग डिलिंगर को पहचानने का संकेत था. जब फिल्म देखकर डिलिंगर बाहर निकला तब बाहर खड़े पर्विस ने अपना सिगार जलाया. डिलिंगर तुरंत यह समझ गया कि यह इशारा है. उसने अपनी बंदूक निकाली लेकिन उससे पहले ही एफबीआई के लोगों की बंदूकें गरज उठीं. जॉन डिलिंगर को तीन गोलियां लगीं. उनमें से एक चार्ल्स वेस्टेंड ने चलाई थी. अस्पताल लाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया. इस तरह अमेरिका का पब्लिक एनिमी नंबर वन ढेर हो गया.

इसके बाद एफबीआई ने अपना वार अगेंस्ट क्राइम अभियान शुरू किया. एक के बाद एक अपराधी एफबीआई का निशाना बनते गए. वैन मीटर मारा गया. बेबी फेस नेल्सन को स्पेशल एजेंट काउली ने मार गिराया, हालांकि इसी मुठभेड़ में वह ख़ुद भी शहीद हो गए. संगठित अपराध की दुनिया को एफबीआई की इस आंधी ने तबाह कर दिया. इस पूरे अभियान ने एफबीआई की ताक़त में ज़ोरदार इजाफ़ा किया. अब एफबीआई अमेरिका की सबसे ताक़तवर जांच एजेंसी बन चुकी थी. अब उसे और अधिकार मिल गए. एफबीआई अमेरिका के पब्लिक एनिमीज के ख़िलाफ़ लड़ने को पूरी तरह से तैयार हो गई.

pawas@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

बड़ी चोट लगी है गुरु को

बृहस्पति यानी जूपिटर को बड़ी चोट लगी है. चोट भी कोई छोटी-मोटी नहीं है. चोट इतनी बड़ी है कि जूपिटर की शक्ल पर पृथ्वी के आकार का गड्ढा हो गया है. जूपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह है, तो सवाल यह उठता है कि उसे इतनी बड़ी चोट किसने पहुंचा दी. वैज्ञानिकों का मानना है कि उससे कोई भटका हुआ धूमकेतु या बर्फ का बड़ा टुकड़ा टकरा गया है, जिसने इसके गैसीय पर्यावरण पर पृथ्वी के जितना बड़ा धब्बा छोड़ा है.

नासा के वैज्ञानिकों ने अपनी कैलिफोर्निया लैब में आई बृहस्पति की नई तस्वीरों को देख कर यह निष्कर्ष निकाला है. कैलिफोर्निया लैब में काम करने वाले ग्लेन ऑरटन ने कहा कि जूपिटर की किसी अनजानी खगोलीय वस्तु से हुई, यह टक्कर अब तक वहां देखे गए किसी भी परिवर्तन से अलग है.

इस टक्कर की असली जगह का पता आस्ट्रेलिया के एक शौक़िया वैज्ञानिक एंथनी वीजली ने लगाया. जब उसने जूपिटर पर काफी बड़ा काला धब्बा देखा तो उसने अपनी इस खोज की रिपोर्ट कैलिफोर्निया के पासाडेना स्थित नासा के जेट प्रोपेल्सन लैबोरेटरी में दी. लैबोरेटरी ने इस घटना को कोई मौसम संबंधी परिवर्तन न मानते हुए इसकी गहरी जांच की. टेलिस्कोपों की मदद से ली गई

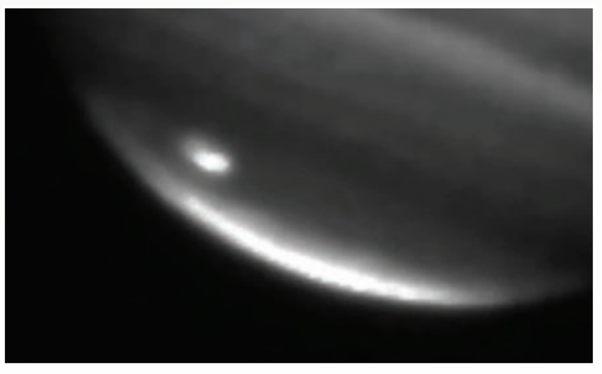

तस्वीरों को ध्यान से देखने पर दिखाई दिया कि धब्बे के बनने से ठीक पहले वहां एक तेज़ चमक दिखाई दी थी. इससे यह साफ हो गया कि कोई खगोलीय पिंड जूपिटर की सतह से टकराया था. वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी प्राकृतिक घटना से इतनी चमक और इतना बड़ा काला धब्बा नहीं बन सकता.

सन 1994 के बाद से यह पहला मौका है, जब जूपिटर पर कोई टक्कर की घटना देखने को मिली है. इससे पहले 1994 में शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु के 21 टुकड़े जूपिटर से टकराए थे.

अब चीन में भी हम दो हमारे दो

एक से भले दो. दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन अब अपने नागरिकों को यही सलाह दे रहा है. चीन के सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहर शंघाई में अधिकारी जोड़ों को दूसरे बच्चे के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं.

ग़ौरतलब है कि चीन ने तेज़ी से बढ़ रही जनसंख्या और संसाधनों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए 1978 में ही एक बच्चे की नीति अपना ली थी. इसके हिसाब से लोगों को केवल एक बच्चा पैदा करने की अनुमति है. केवल कुछ ग्रामीण इलाक़ों में ऐसे माता-पिता को दूसरा बच्चे की इजाज़त है, जिनकी पहली संतान लड़की हो. साथ ही वहां के अल्पसंख्यकों को भी इस मामले में छूट दी गई है. इसके अलावा उन जोड़ों को भी दूसरे बच्चे की इजाज़त मिल सकती है जो ख़ुद अपने माता-पिता की इकलौती संतान हों. चीनी सरकार का मानना है कि इस नियम से चीन की जनसंख्या में क़रीब चालीस करोड़ का इजाफ़ा होने से रोका गया है. अब कई दशकों के बाद पहली बार सरकार दो संतानों की बात को बढ़ावा दे रही है. शंघाई में दो बच्चों को इजाज़त देने के पीछे

सरकार की एक बड़ी चिंता है. दुनिया के सबसे अहम व्यापार केंद्रों में एक शंघाई जैसे-जैसे अमीर होता जा रहा है वैसे-वैसे ही बूढ़ा भी, दरअसल शंघाई में युवा लोगों की संख्या, बुज़ुर्गों के अनुपात में बहुत कम होती जा रही है. शहर की कुल जनसंख्या का क़रीब 21 प्रतिशत साठ साल के ऊपर के लोग हैं, और आने वाले कुछ सालों में यह आंकड़ा और तेज़ी से बढ़ने वाला है.

ऐसे में शंघाई में काम करने योग्य लोगों की संख्या घटती जा रही है. इस समस्या से निपटने वाले के लिए ही सरकार लोगों को दूसरे बच्चे के लिए प्रोत्साहित कर रही है. अमेरिका स्थित सेंटर फॉर स्ट्रैटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के शोध के मुताबिक 2050 तक शंघाई में एक बुज़ुर्ग पर केवल 1.6 जवान (60 से कम के) लोग होंगे. 1975 में यह अनुपात एक बुज़ुर्ग पर 7.7 लोगों का था.

नए तेवर से मैदान-ए-जंग में उतरेगी अमेरिकी सेना

कहते हैं खुली मुट्ठी ख़ाक की, और बंद मुट्ठी लाख की होती है. लगता है यह कहावत अब अमेरिका सेना को समझ में आ गई है. कई सालों से अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के साथ संघर्ष में उलझी अमेरिकी सेना ने अब अपने तरीक़े में थोड़ा बदलाव लाने की योजना बनाई है. पाकिस्तानी अख़बार द न्यूज़ इंटरनेशनल में छपी ख़बर के मुताबिक अब अमेरिकी सेना तालिबान से निपटने के लिए अपने ख़ुफ़िया तंत्र को संगठित कर रही है. ख़ुफ़िया सूचना जुटाने के अलग-अलग तरीक़ों को एक साथ जोड़कर अमेरिकी सेना अब तालिबान पर ज़ोरदार प्रहार करने की कोशिश में जुटा है.

अमेरिका के सहायक रक्षा सचिव माइकल विकर्स ने कहा है कि अब सेना ने मानव-रहित ड्रोन और अन्य हवाई जहाज़ों से जुटाई सूचना, तालिबान के पकड़े गए आपसी संदेशों, ज़मीनी फौजों से मिली जानकारी और अन्य स्रोतों की जानकारी को पहली बार एक साथ लाकर उनसे ठोस सूचना निकालने की योजना बनाई है.

इसके अलावा अब ख़ुफ़िया जानकारी जुटाने के लिए नई तकनीकें और उपाय भी शामिल किए गए हैं. अमेरिकी सेना कई तरह के मानव-रहित हवाई जहाज़ों को तैयार कर रहा है. इसमें दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकने वाले प्रीजेटर ड्रोन और लंबे समय तक ऊंचाई से नज़र रख सकने वाले रिपर ड्रोन जहाज़ शामिल हैं. इन ड्रोन जहाज़ों के अलावा सूचना जुटाने के लिए सी-12 पेट्रोल हवाई जहाज़ भी लाए जा रहे हैं. इन जहाज़ों को ज़मीनी ख़ुफ़िया तंत्र, विश्लेषकों, ख़ुफ़िया संकेतों के साथ मिलाकर एक मज़बूत फौज तैयार की जा रही है.

हालांकि विकर्स का मानना है कि इससे तालिबान का ख़ात्मा हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है. उनका पहला उद्देश्य आतंकी घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी को रोकना होगा. ज़ाहिर है, सालों तालिबान से जूझने के बाद अमेरिका को समझ में आ रहा है कि बिना अपने ख़ुफ़िया तंत्र को तगड़ा किए जीत दूर ही रहेगी. ख़ैर उन्हें तो यही उम्मीद होगी कि इस अमेरिकी कोशिश के लिए-देर आए लेकिन दुरुस्त आए- का मुहावरा सच साबित हो.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

लिट्टे के ख़ात्मे के बाद अब माफ़िया के ख़िलाफ़ नई जंग

■ आतंकवाद के ख़ात्मे के बाद माफ़िया पर लगाम ज़रूरी

राहुल मिश्र

> लिट्टे के आतंक का सफाया करने के बाद अब श्रीलंका सरकार माफिया संगठनों का ख़ात्मा करने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों को हरी झंडी दे चुकी है. इसके साथ ही राष्ट्रपति राजपक्षे ने देश के राजनीतिक नेतृत्व को सख्त हिदायत भी दी है कि वे पुलिस और सुरक्षा बल की इस नई मुहिम के रास्ते में न आएं. ताकि जल्द से जल्द श्रीलंका में माफियाओं के कहर से निजात पाई जा सके.

आतंकवाद किस तरह से समाज में कभी धर्म और कभी अंडरवर्ल्ड माफिया का सहारा लेता है, यह दक्षिण एशियाई देशों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता. जहां एक तरफ़ पाकिस्तान में तालिबान और अल-क़ायदा ने धर्म की आड़ लेकर मासूम और बेगुनाह लोगों को अपना शिकार बनाया, वहीं पाकिस्तान और श्रीलंका में यह भी साफ-साफ देखने को मिलता है कि आतंकवाद के लिए देश के अंडरवर्ल्ड माफिया से सांठगांठ करना मुनाफ़े का सौदा होता है. पाकिस्तान की सेना फ़िलहाल तालिबानी आतंकवादियों से सीधा मुक़ाबला कर रही है. सेना का सूचना और ख़ुफ़िया तंत्र फ़िलहाल इस्लामाबाद और कराची में बैठे माफिया सरगनाओं को निष्क्रिय कर उनसे तालिबानियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्रित करने में लगा है. हालांकि एक बार जब आतंकवाद का सफाया हो जाएगा, तब इन माफिया सरगनाओं को भी ख़त्म करना ज़रूरी हो जाएगा. ऐसा इसलिए कि उनको उनके किए की सज़ा दी जाए, ताकि भविष्य में किसी नए स्वरूप के आतंकवाद और इन माफिया हुक्मरानों में गठजोड़ न होने पाए. श्रीलंका सरकार इस बात को अच्छी तरह समझ रही है कि लिट्टे का ख़तरा अगर दोबारा सिर उठा सकता है तो वह इन्हीं माफियाओं के सहारे. लिहाज़ा, ठीक आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ी गई जंग की तर्ज़ पर इन स्थापित माफियाओं को भी ख़त्म करने के लिए नई जंग ज़रूरी है.

लिट्टे के आतंक का सफाया करने के बाद अब श्रीलंका सरकार माफिया संगठनों का ख़ात्मा करने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों को हरी झंडी दे चुकी है. इसके साथ ही राष्ट्रपति राजपक्षे ने देश के राजनीतिक नेतृत्व को सख्त हिदायत भी दी है कि वे पुलिस और सुरक्षा बल की इस नई मुहिम के रास्ते में न आएं. वजह यह कि जल्द से जल्द श्रीलंका में माफियाओं के कहर से निजात पाई जा सके.

दरअसल, श्रीलंकाई सेना से आर-पार की लड़ाई शुरू होने के पहले लिट्टे दक्षिण श्रीलंका में संगठित माफियाओं की मदद से उत्तर और पूर्वी श्रीलंका में आतंकी वारदातों को अंजाम देता था.

सरकार के पास जो ख़ुफिया जानकारी है, उसके मुताबिक कोलंबो और उसके इर्द-गिर्द दहशत फैलाने में माफियाओं की मदद ली जाती थी. इनमें प्रमुख माफिया गिरोह कंबूला-इला गुने, बोरेले ओल्कॉट और आइस मंजू हैं. इन लोगों की मदद से लिट्टे ने कोलंबो में कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया. इनमें टाउन हॉल में पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंगे की हत्या की कोशिश भी शामिल है. सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बात के पुख्ता और पर्याप्त सबूत हैं कि कुमारतुंगे पर आत्मघाती हमले के पीछे कंबूला-इला-गुने का ही षड्यंत्र था.

इसके अलावा आइस मंजू भी कोलंबो और आसपास के इलाक़ों में आतंकी हमले करने में लिट्टे की मदद करता रहा है. इसके एवज़ में लिट्टे इन माफियाओं को उनकी ज़रूरतों के लिए बड़ी रक़म देता था. आइस मंजू के लिट्टे से संबंध का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सेना से लिट्टे के संघर्ष के दौरान मंजू अक्सर उन इलाक़ों में पाया जाता था जहां लिट्टे का वर्चस्व क़ायम था. ख़बर यह भी है कि इस लड़ाई के आख़िरी दौर में मंजू की श्रीलंका सेना के ख़िलाफ़ लड़ते हुए मौत हो गई थी.

इन तथ्यों को देखते हुए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लिट्टे कोलंबो के संगठिक माफिया का सहारा लेकर अपने आतंक के नेटवर्क को फैला रहा था. कोलंबो पुलिस के मुताबिक, वहां पर प्रमुख तौर पर छह माफिया संगठनों का वर्चस्व था. ये सभी माफिया बोरेला, मालिगवट्टा, कादूवेला और ब्लोमेंधाल इलाक़ों से अपनी गतिविधियां चलाते थे. किसी भी माफिया संगठन की तरह इनकी भी आय का प्रमुख जरिया अपहरण, कांट्रैक्ट किलिंग, डकैती और रीयल इस्टेट में जबरन वसूली ही है. इनमें से ज़्यादातर माफियाओं को बड़े राजनेताओं और शीर्ष पुलिस अधिकारियों का संरक्षण भी मिला है. कुछ रिपोर्ट यह भी इशारा करती हैं कि बड़े राजनेता माफिया को हथियार मुहैया कराते हैं. यहां तक कि वारदातों को अंजाम देने के लिए अक्सर ये माफिया सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल भी करते हैं.

मौजूदा समय में फाज़ी ग्रुप सबसे ख़तरनाक है और यह कोलंबो के मालिगवाटा इलाक़े में बसा है. इस ग्रुप का सरगना फाज़ी है और कुछ राजनेताओं की मदद से उसने अपने काले कारनामों को अंजाम देकर संगठित ग्रुप बनाया.

इसके अलावा, जिहाद ग्रुप एक मुस्लिम माफिया संगठन है और इसे भी कुछ राजनेताओं से संरक्षण मिला हुआ है. यह ग्रुप भी पूर्वी श्रीलंका, कोलंबो और आसपास के इलाक़ों में अपना दबदबा बनाए हुए है. इस समूह के बारे में जानकारी यह है कि ये लोग बहुत ही घातक हथियारों से लैस हैं, जैसे कि ऊजी राइफल. श्रीलंका सरकार जिहाद ग्रुप से होने वाले ख़तरे को भांपते हुए इस समूह के भी सफाए को प्राथमिकता दे रही है. श्रीलंका सेना ने जिहाद ग्रुप से समर्पण करने को कहा है. इसके बदले उनके ख़िलाफ़ कोई मुक़दमा न चलाए जाने की पेशकश है. इस अपील का फ़िलहाल ज़्यादा असर नहीं दिख रहा, क्योंकि ख़ुफ़िया जानकारी के मुताबिक जिहाद ग्रुप के पास हज़ारों की संख्या में हथियार और भारी गोला बारूद मौजूद हैं.

हाल ही में जनरल फोनेस्का ने इन माफिया सरगनाओं से अपील की है कि वे सेना और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दें. उन्होंने यह बात इसके मद्देनज़र कही कि श्रीलंका में क़ानून व्यवस्था क़ायम करने और भविष्य में शांति बहाल रखने के लिए ऐसे गुटों के ख़िलाफ़ कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए जा चुके हैं. इसके साथ ही उन राजनेताओं और अधिकारियों को भी कड़े निर्देश जारी किए हैं कि वे पुलिस और सेना की इस नई मुहिम के रास्ते में न आएं और श्रीलंका के सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए ऐसी ताक़तों का पूरी तरह से सफाया करने में सरकार की मदद करें.

इन निर्देशों के बाद ही कोलंबो पुलिस की दो टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है, जिसे सेना के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा गया है. इस टास्क फोर्स ने पिछले कुछ ही दिनों में कई बड़े माफियाओं और असामाजिक तत्वों को गिरफ़्तार कर निष्क्रिय करने में सफलता पाई है. चंद हफ़्तों पहले ही अनामलू इम्तियाज़ समेत कई बड़े माफिया कोलंबो में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मार गिराए गए हैं. बचे-खुचे या तो अपने सूत्रों के माध्यम से सरकार के सामने हथियार डालने की कवायद में हैं या फिर श्रीलंका की सरहदों से निकलने की कोशिश में हैं.

ग़ौरतलब है कि पाकिस्तान में भी मौजूद सभी प्रमुख आतंकवादी संगठनों के तार संगठित माफियाओं और काले कारोबार से सीधे तौर पर जुड़ने के साक्ष्य मिलते रहे हैं. मौजूदा वक़्त में पाकिस्तानी सेना और ख़ुफ़िया तंत्र इन माफिया संगठनों में अपने संपर्क सूत्रों की मदद से आतंकियों की गतिविधियों के बारे में ज़रूरी जानकारियां इकट्ठा कर रही हैं. लेकिन ठीक श्रीलंका की तरह यह पहल पाकिस्तान को भी करनी पड़ेगी, ताकि आतंकवाद के ख़ात्मे के बाद माफिया संगठन भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएं.

rahul@chauthiduniya.com

लिट्टे की फंडिंग का सबसे बड़ा स्रोत था कनाडा

हाल ही में कनाडा की एक ख़ुफ़िया रिपोर्ट ने यह ख़ुलासा किया है कि श्रीलंका में तमिल मुक्ति चीतों को सहायता करने वालों में कनाडा सबसे प्रमुख था. रिपोर्ट के अनुसार कनाडा से लिट्टे (लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम) को प्रति वर्ष 12 मिलियन डॉलर की सहायता मिलती थी.

रिपोर्ट बताती है कि कनाडा के तमिल समुदाय के लोग लिट्टे की आर्थिक सहायता का सबसे बड़ा ज़रिया थे. उन्होंने एलटीटीई को 10 से 12 मिलियन डॉलर की वार्षिक मदद की. रिपोर्ट, जिसे पिछले जून में लिखा गया, में कहा गया है कि लिट्टे के कई देशों में संगठन हैं, जिसमें कनाडा भी शामिल है. इन संगठनों के ज़रिए उसने श्रीलंका में लिट्टे की मदद के लिए बड़े पैमाने पर फंड जुटाए हैं और दूसरे कार्यक्रमों को भी संचालित किया है.

टोरेंटो स्थित वर्ल्ड तमिल मूवमेंट को तमिल विद्रोहियों का संगठन बताती इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राय: दबाव बनाकर ही पैसा जमा किया जाता था. इस तरह डब्ल्यूटीएम (वर्ल्ड तमिल मूवमेंट) की लिट्टे के नाम पर कनाडा में फंड जुटाने में अहम भूमिका थी. 2002 आरसीएमपी ने कनाडा में तमिल टाइगर्स के फंड जुटाने के तरीक़े को लेकर जांच शुरू कर दी थी. हालांकि पुलिस यह मानती है कि विद्रोहियों ने टोरेंटों और मोंट्रियल से जो उगाही की उससे हथियार ख़रीदे गए, लेकिन जांचकर्ताओं ने कभी नहीं रहा कि उगाही गई रक़म इतनी बड़ी थी.

2006 में पुलिस ने ओंटैरियो और क्यूबेक में वर्ल्ड तमिल मूवमेंट के ऑफिसों की तलाशी ली. पिछले वर्ष सरकार ने एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत इस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया. संघीय वकीलों ने कोर्ट में उसकी संपति और बैंक एकाउंटों को जब्त करने की अपील की है. हालांकि संगठन ने किसी भी तरह के ग़लत काम से इंकार किया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि लिट्टे की कनाडा में रुचि इसलिए थी क्योंकि यहां फंड जुटाने का बहुत बड़ा ज़रिया मौजूद था, जिसमें अधिकतर कनाडा में रह रहे तमिल मूल के लोग थे.

लिट्टे का भविष्य और केपी

इस सप्ताह की शुरुआत में लिट्टे की कथित कार्यकारी समिति ने मीडिया में एक बयान दिया. उस बयान का मतलब यह था कि लिट्टे को पहले हथियार मुहैया कराने वाला सेल्वरासा पथमनाथन उर्फ केपी ही अब लिट्टे का मुखिया है और वह इस आतंकी समूह का पुनर्गठन करेगा, ताकि आतंकी गतिविधियां बेरोकटोक चल सकें. यह ख़बर लिट्टे समर्थक तमिलनेट ने प्रकाशित की. इसमें लिट्टे के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ऐसा संगठन की साख को फिर से बहाल करने और ज़मीनी स्तर पर संगठन को खड़ा करने के लिए किया जा रहा है. साथ ही बाहर रह रहे तमिलों के बीच फिर से ताक़तवर अभियान चला कर इस राष्ट्रीय मसले को ज्वलंत बनाना भी केपी का मक़सद है.

इस कथित कार्यकारी समिति ने एक बयान भी जारी किया है. इसमें कहा गया है कि तमिल लोगों को अभी हाल ही में बेहद गंभीर और दुखद हालात झेलने पड़े हैं. इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि जितना नुक़सान ईलम के मसले पर हाल के दौर में हुआ है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता.

यहां बताना ज़रूरी होगा कि केपी हथियारों का कुख्यात सौदागर रहा है. लिट्टे ने हमेशा उसका इस्तेमाल गोला और बारूद जुटाने और तस्करी के लिए किया. प्रभाकरन ने केपी को अंतरराष्ट्रीय संबंधों की ज़िम्मेदारी दी थी और लड़ाई के आख़िरी दिनों में उसे प्रवक्ता भी बनाया था. हालांकि, इसके बावजूद प्रभाकरन केपी पर इतना विश्वास भी नहीं करता था कि लिट्टे में प्रशासन के स्तर पर केपी को कोई ज़िम्मेदारी दे.

प्रभाकरन ने केपी को जो ज़िम्मेदारी दी, वह केवल इसलिए क्योंकि अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को संभालने में केपी की क्षमता का कोई आदमी उसके पास नहीं था. यह साफ है कि बाहरी देशों में रह रहे तमिल प्रवासियों का प्रभाकरन की मौत के बाद केपी की गतिविधियों को देख कर कोई विश्वास नहीं रहता है. केपी पर आरोप है कि उसने सारी आमदनी (जो भी इस आतंकी संगठन को होती है) का रुख़ अपनी ओर मोड़ लिया और लिट्टे के बाक़ी अंतरराष्ट्रीय नेताओं से कोई संपर्क नहीं किया. प्रभाकरन की मौत के तुरंत बाद ही केपी और लिट्टे के एक प्रभावी व्यक्ति कास्त्रो (यूरोप का निवासी) के विरोधाभासी बयान आने लगे. लिट्टे की पराजय के बाद ही संगठन में एक आंतरिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि केपी और कास्त्रो दोनों ही एक-दूसरे के विरोधी हैं और अपने नेता की मौत के बाद से ही विरोधी बयान दिए. इसके बाद ही कास्त्रो ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि संगठन के बाक़ी बचे सदस्यों के बीच कुछ ग़लतफहमी है. इसी बयान में यह भी कहा गया कि केपी ने कुछ विरोधाभासी बयान दिए.

इन सभी हालातों और स्थितियों के मद्देनज़र यह बात तयशुदा लगती है कि प्रभाकरन जैसे मजबूत नेता के अभाव में लिट्टे पूरी तरह नेतृत्वहीन हो चुका है. केपी अब उसका नया नेता बन सकेगा, यह भी संदेह के घेरे में ही है. श्रीलंका सरकार ने लिट्टे का जिस तरह से सफाया किया है, उसके बाद लिट्टे के फिर से खड़ा होने की उम्मीद नहीं की जा सकती.

इस्लाम कहता है...

सूरज गहन के मौके पर नमाज़ और दुआ की जाए

हमारे मुल्क के कुछ हिस्सों में 22 जुलाई 2009 को मुकम्मल और कुछ हिस्सों में आधा सूरज गहन हुआ. इस दौरान वैज्ञानिक मुल्क की ख़ास जगहों से अपने तजुर्बे और अध्ययन के लिए गहन के नज़ारे को देखते हैं. किसी सलाहियत रखनेवाले आदमी के हिसाब से भी कुछ एहतियात बरतने को कहा जाता है. गहन के सिलसिले में मजहब का भी एक ख़ास नज़रिया है, उपरोक्त बातों के अनुसार यह बताने की कोशिश की गई है कि गहन की शरीअत में क्या हैसियत है, और जब गहन हो, तो मुसलमनों को क्या करना चाहिए.

चांद, सूरज, ज़मीन और दूसरे तमाम सितारे अल्लाह की निशानियों में से हैं. और अपने-अपने दायरे में गर्दिश कर रहे हैं. इनमें से हर एक की गर्दिश का समय मुक़र्रर है.

एक का दूसरे से फ़ासला भी तय है. न कभी यह समय कमोबेश होता है न फ़ासले में कमी व ज़्यादती होती है. सूरज अपने दायरे में गर्दिश कर रहा है. ज़मीन सूरज के इर्द-गिर्द घूम रही है. चांद ज़मीन के चारों तरफ़ घूम रहा है. अगर ज़मीन सूरज और चांद के बीच आ जाए तो उसे चांद गहन (ख़ूसूफ़) कहते हैं. इसी तरह चांद जब ज़मीन और सूरज के बीच आ जाए तो उसे सूरज पर गहन लगना (कुसूफ़) कहते हैं. ख़ूसूफ़ के वक़्त चांद बेनूर यानी अंधेरा हो जाता है. और कुसूफ़ के वक़्त सूर्य की रोशनी ज़ाइल (ढल) हो जाती है.

> चांद, सूरज, ज़मीन और दूसरे तमाम सितारे अल्लाह की निशानियों में से हैं. और अपने-अपने दायरे में गर्दिश कर रहे हैं. इनमें से हर एक की गर्दिश का समय मुक़र्रर है. एक का दूसरे से फ़ासला भी तय है. न कभी यह समय कमोबेश होता है न फ़ासले में कमी व ज़्यादती होती है. सूरज अपने दायरे में गर्दिश कर रहा है. ज़मीन सूरज के इर्द-गिर्द घूम रही है. चांद ज़मीन के चारों तरफ़ घूम रहा है.

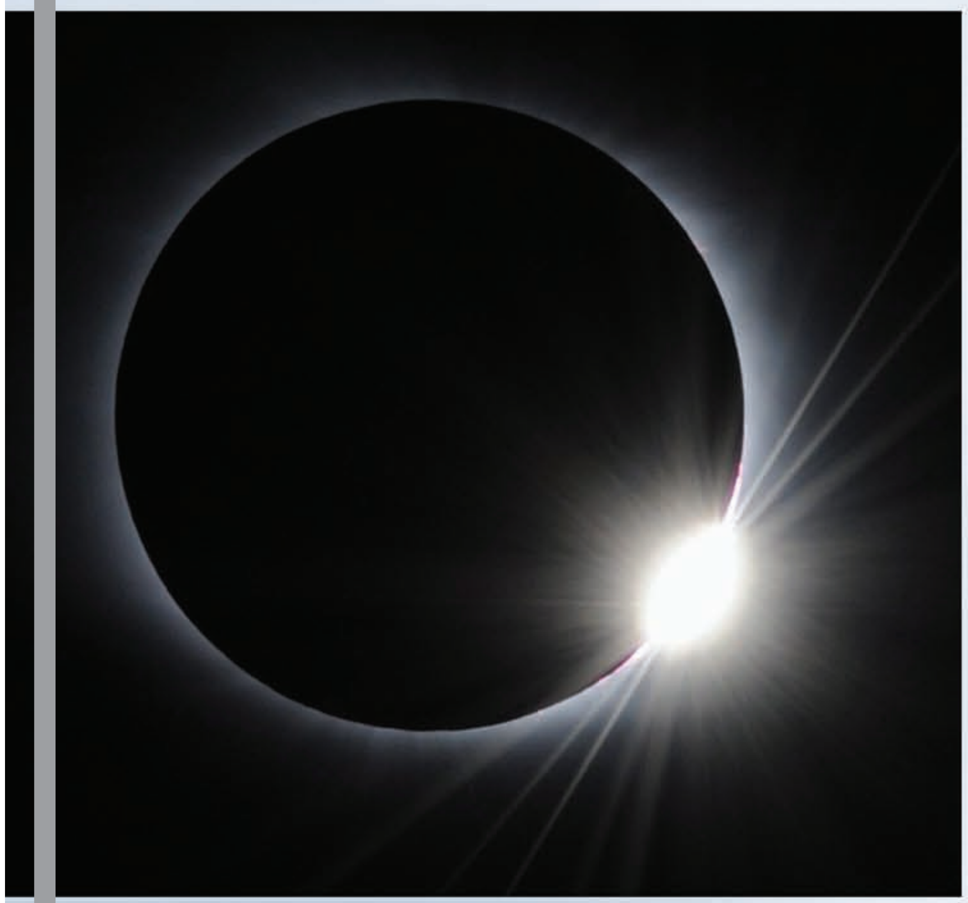

उसका एक पहलू तो वह है जो माहिर फ़न की तहतीक के नतीजे में सामने आया कि चांद और सूरज का गहन तभी असबाब के नतीजे होता है. इसका हिसाब पहले से तय शुदा है.

बहरहाल सालों पहले ये बतलाया जा सकता है कि फ़लां साल, फ़लां तारीख़ इतने बज कर इतने मिनट पर सूरज गहन होगा और फ़लां-फ़लां ज़गह होगा और इतनी-इतनी देर तक रहेगा. दूसरा पहलू वह है जिसे हम शरीअत का नज़रिया कहते हैं. एक मुसलमान होने की हैसियत से हम शरई पहलू पर यक़ीन रखते हैं और वह यह है कि सूरज का बेनूर होना अल्लाह की नाराज़गी का एक हिस्सा है. जिस तरह बारिश का न होना भी बंदों के लिए ख़ुदा की नाराज़गी का सबक़ है. इसलिए उसे बड़ी आज़माइश और ख़बर देने का ज़रिया कहा जाता है, उस मौक़े के लिए हुक्म दिया गया है कि तमाम बंदगान ख़ुद अल्लाह की तरफ़ रूबरू हों. नमाज़, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी और इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम करे, ताकि अल्लाह की नाराज़गी दूर हो और रहमत की बारिश नसीब हो. उसी तरह कुसूफ़ के वक़्त भी नमाज का हुक्म दिया गया है, सच्चा प्रेमी इस तरह के मौके पर नमाज़ों के एहतिमाम और अल्लाह की ओर झुकता है. इनका ख़याल है कि ये तमाम वाक़ियात अच्छाई की वजह से ज़ाहिर होते हैं. इनको अल्लाह की ख़ुशी और नाराज़गी से जोड़ना कोई मतलब नहीं रखता है.

> सालों पहले यह बतलाया जा सकता है कि फ़लां साल, फ़लां तारीख़ इतने बज कर इतने मिनट पर सूरज गहन होगा और फ़लां-फ़लां जगह होगा और इतनी-इतनी देर तक रहेगा. दूसरा पहलू वह है जिसे हम शरीअत का नज़रिया कहते हैं. एक मुसलमान होने की हैसियत से हम शरई पहलू पर यक़ीन रखते हैं और वह यह है कि सूरज का बेनूर होना अल्लाह की नाराज़गी का एक हिस्सा है.

अगर यह मान भी लिया जाए कि कुसूफ़ जैसे वाक़ियात अच्छाई की वजह से पेश आते हैं, तब भी उन्हें मामूली वाक़ियात समझ कर नज़रअंदाज़ करना ग़लत है. यह अल्लाह की जलालत, शान और कमाल-ओ- क़ुदरत का अनोखा करिश्मा है.

वह जिस तरह चाहता है उन सितारों को घुमा देता है. और जिस तरह चाहता है उनको रोशनी देता है. जब चाहता है, बेनूर कर देता है. उसकी अज़मत व जलालत और क़ुदरत के इस नज़ारे के बाद ज़रूरी है कि ख़ुदा के बंदे अपने अज्ज़ (अनोखी क़ुदरती देन) को समझें और झुक कर तसलीम करे कि तमाम कायनात उसी ख़ुदा के हाथ और तसर्रुफ में है. ख़ुदा जिस तरह चाहता है, उसमें उलटफेर करता रहता है.

माना कि कुसूफ़ और ख़ुसूफ़ तयशुदा और एक नियत निज़ाम के तहत होते हैं, लेकिन उस निज़ाम में अगर ज़रा भी ख़लल पैदा हो जाए तो बड़ी तबाही हो सकती है. जैसा कि अर्ज किया गया कि कुसूफ़ के वक़्त चांद, सूरज और ज़मीन के बीच आ जाता है. उस हालत में सूरज और ज़मीन दोनों उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं. यह कशिश-ए-सक़्ल (भारी ढंग से खींचना) कहलाती है. अगर इस कशिश में संतुलन बाक़ी न रहे और कोई एक तरफ़ भारी हो जाए तो कोई भी दो ग्रह एक-दूसरे से टकरा जाएं. यह ख़ुदा ही है, जिसने उस कशिश में संतुलन रख कर एक को दूसरे पर भारी होने से रोक रखा है. कुरान मजीद के मुताबिक-

बिलाशुबह अल्लाह ही ने आसमानों और ज़मीन को थाम रखा है. वह अपनी जगह से हट न जाए और अगर वह अपनी जगह से टल गए तो अल्लाह के सिवा उनको कोई थाम नहीं सकता.

इसी हालत में तबाही सिर पर खड़ी हो, तो अल्लाह के बंदों के पास उसके सिवाय कोई चारा नहीं कि वह दुनिया बनाने वाले की तरफ मुख़ातिब हों. जिसने तमाम कायनात को ख़ास निज़ाम का पाबंद रहने पर मजबूर कर रखा है. वह उस ख़ास निज़ाम से अलग होने वाले मख़लूक़ (पैदा किया हुआ) के लिए अज़ाब (तबाही) की शक्ल एख़्तियार कर सकता है.

बहरहाल ***क़ौम-ए-नूह पर बेपनाह बारिश बरसाई गई. यहां तक कि उसने बाढ़ की शक्ल ले ली, क़ौम-ए-आद पर सख़्त आंधी का अज़ाब नाज़िल किया गया.***

यही वजह है कि जब भी मामूली से ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती, सरकार- ए- दोआलम सल्लल्लाहो ओलैहि वसल्लम का चेहराई मुबारक़ उस ख़ौफ़ से मुतग़युर (अचंभित) हो जाता कि कहीं ये तेज़ हवाएं अज़ाब की शक्ल अख्तियार न कर ले. (बुख़ारी शरीफ़ से)

बहरहाल हुज़ूर साहब ऐसे मौके पर दुआ और मग़्फ़िरत में मशगूल हो जाते.

कुसूफ़ व खूसूफ़ उन वाक़ियात का एक नमूना भी है, जो क़यामत के रोज़ आने वाले हैं. जब तमाम कायनात, चांद और सूरज वग़ैरह बेनूर हो जाएंगे, आख़िरत को याद करने का उससे बेहतर क्या तरीक़ा हो सकता है कि बंदा अपने मौला की तरफ झुके और उसके सामने हिफ़ाज़त व मग़्फ़िरत के लिए दस्ते दुआ दराज़ करे, बुज़ुर्गाने-दीन का एक नज़रिया यह भी है कि जब बंदे का अंतिम समय आता है, तो अल्लाह कुछ देर के लिए चांद और सूरज को बेनूर कर देता है, ताकि बंदे यह जान लें कि उनके गुनाहों का असर उनकी जात तक ही रुका नहीं है. चांद और सूरज तक उनसे प्रभावित होते हैं. जब वे उनके गुनाहों की वजह से बेनूर हो सकते हैं तो बंदों के दिलों की ज़ुल्मात और तारीकी (अंधेरा) का क्या हाल होगा? गोया खूसूफ़ व कुसूफ़ गुनाहों के असरात की निशानदेही करते हैं. सूरज गहन के वक़्त नमाज़ ज़रूरी है और ***फ़ोकहा*** ने उसे ***सुन्नते मुअक्किदा*** या वुजूब का दर्जा दिया है.

नमाज़े कुसूफ़ का तरीक़ा वही है जो तमाम नमाज़ों का है. बहरहाल इस मौके पर दो रिक्अतें उसी तरीके पर अदा की जाएंगी, जिस तरह दूसरी तमाम नमाज़ें पर की जाती है. यानी उसी तरह के रुकु व सुजूद और क़िरात वग़ैरह, अलबत्ता उस नमाज़ में इतनी लंबी क़िरात करना कि गहन ख़त्म हो जाए. मसनून है, अगर नमाज़ बा जमाअत का एहतिमाम न हो सके तो लोग तन्हा-तन्हा भी नमाज़ पढ़ सकते हैं.

उस सूरत में दो के बजाय चार रिक्अतें भी पढ़ी जा सकती है. सहीह बुख़ारी शरीफ़ में **हज़रत अबु होरैरा** से रवायत है. ***अहदे रिसालत में सूर्य ग्रहण हुआ तो आप अपनी चादर मुबारक खींचते हुए (ऊजलत में) मस्जिद में तशरीफ लाए और लोग भी इधर दौड़े आपने उन्हें दो रिक्अत नमाज़ पढ़ाई.*** **(बुख़ारी शरीफ़ से)** निसाई शरीफ में **हज़रत समरा इब्ने जन्दब** की रवायत में है कि ***आपने नमाज़ पढ़ाई और इतनी देर क़याम फरमाया कि उससे पहले कभी भी नमाज़ पढ़ाते हुए इतना लंबा कयाम नहीं फरमाया था. उस दौरान हमने आपकी कोई आवाज़ भी नहीं सुनी. आपने लंबा रुकू फ़रमाया. उससे पहले हमारे साथ तभी इतना लंबा रुकू नहीं फ़रमाया था. उसमें भी हमने आपकी कोई आवाज़ नहीं सुनी. फिर आपने निहायत लंबे सजदे फ़रमाए. उससे पहले आपने हमारे साथ किसी नमाज़ में इतने लंबे सजदे नहीं फ़रमाए थे, सजदों की हालत में भी हमने आपकी कोई आवाज़ नहीं सुनी. इसी तरह आपने दूसरी रिक्अत में भी किया.*** **(निसाई शरीफ़ से)** इस रिवायत से ज़ाहिर है कि यह नमाज़ पूरे तौर पर बेहतर थी.

आपने दोनों रिक्अतों में लंबीतरीन क़िरआत फ़रमाई और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता तलावत फ़रमाई कि पीछे खड़े हुए सहाबा कराम आवाज़ सुन न सके. लंबे-लंबे रुकू व सुजूद किए. लंबे क़िरआत से मुतअल्लिक़ हजरात सहाबा से नक़्ल किया हुआ है. आपने सूरह बक़रा जैसी सूरत की तलावत फ़रमाई **(बुख़ारी शरीफ़ से).**

अहदे रिसालत में कुसूफ़ सिर्फ़ एक ही मर्तबा है. बहरहाल माहिरों ने इसकी तज़वीज़ की है कि अहदे रिसालत के कुसूफ़े शम्स वाक्या 29 शव्वाल सन 10 हिजरी में पेश आया. इत्तिफ़ाक़ से उसी रोज सरकार दो आलम सल्लल्लाहो अलैहे व सल्लम के साहेबज़ादे हज़रत इब्राहीम का इंतिक़ाल हुआ. उस हादसा -ए-फ़ाजेआ की वजह से लोगों में यह शोहरत फैल गई कि सूरज का गहन हज़रत इब्राहीम की मौत की वजह से हुआ है.

आपने नमाज़े कुसूफ़ के बाद ख़ुत्बा दिया. और फ़रमाया कि ***सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं. और उन दोनों में किसी के मरने या जीने से गहन नहीं लगता. अगर गहन देखो तो जैसी फर्ज नमाज़ तुमने अभी पढ़ी वैसी पढ़ लो.*** **(निसाई शरीफ़ से)** इस एतवार से करीबतरीन नमाज़ फ़जर की नमाज़ थी. इसी जैसी नमाज़ पढ़ने की ताकीद की गई.

कुसूफ़ की नमाज़ के बाद या पहले कोई ख़ुत्बा वग़ैरह नहीं है. कुछ रवायात ने आपसे ख़ुत्बा नक़ल किया हुआ है. उस ग़लतफहमी के लिए आपने नमाज़ से स्वागत के बाद कुछ फ़रमाया, जो हज़रत इब्राहीम की मौत की वजह से फैली हुई थी. यही वजह है कि आपने उसी ग़लतफहमी पर काफी बात कही. बाकायदा ख़ुत्बा होता तो ज़्यादा कुछ इरशाद फ़रमाते. यूं भी नमाज़े कुसूफ़ के सिलसिले में जिस कदर रवायात मज़्कूर है. उनमें से किसी भी ख़ुत्बे का हुक्म नहीं दिया गया. इसके बजाय ये अल्फ़ाज़ मिलते हैं कि

जब तुम गहन देखो तो अल्लाह से दुआ करो. तकबीर कहो और नमाज़ पढ़ो और सदक़ा ख़ैरात करो. **(बुख़ारी शरीफ़ से)** इस रवायात से यह भी साबित होता है कि नमाज़ों और दुआओं के साथ-साथ सदक़ा व ख़ैरात का भी एहतेमाम करना चाहिए, क्योंकि गहन अल्लाह के गुस्से की निशानी है. और सदका से अल्लाह की नाराज़गी दूर होती है. इसलिए ख़ुदा के बंदों को चाहिए कि वह ऐसे मौकों पर ग़रीबों और ज़रूरतमंदों को सदक़ा व ख़ैरात दे ताकि जल्द से जल्द सूरज अपनी हालत पर वापस आ जाए.

इस सिलसिले में ये वज़ाहत भी ज़रूरी है कि नमाज़े कुसूफ़ के लिए शहर से बाहर जंगलों और मैदानों का रुख़ करने की ज़रूरत नहीं है. बल्कि मस्जिदों में भी ये नमाज़ अदा की जा सकती है.

ईदैन (ईद-उल-जुहा और ईद-उल-फितर) और जुमा की तरह इस नमाज़ में भी औरतों की शिरकत पसंदीदा नहीं है. अलबत्ता वह घरों के अंदर रह कर यह नमाज़ पढ़ सकती है. नमाज़े कुसूफ़ के लिए अज़ान व अक़ामत नहीं है. अलबत्ता लोगों को नमाज़ की इत्तिला देने के लिए कोई ऐलान वग़ैरह किया जा सकता है.

मौलाना नदीम अलवाजदी

feedback@chauthiduniya.com

दुनिया

उत्तराखंड में हो रही वनों की बेरोकटोक कटाई

राजकुमार शर्मा

उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तो इसके जल, जंगल और देवालयों के कारण ही. वैसे, इन दिनों उत्तराखंड के जल-जंगलों पर आफत आई हुई है. यहां के जंगलों पर न तो सरकार का राज है, न क़ानून का ज़ोर. यहां तो बस जो जंगल राज चला सके, वही इन जंगलों का वास्तविक राजा है. बाक़ी अगर इस सूबे में किसी का राज है, तो बस जंगल माफियाओं का. यह सारा खेल संरक्षित वन में दीवार बना कर हो रहा है. वन विभाग के खानपुर रेंज में तो यह वन माफिया इतना ताक़तवर निकला कि एक किनारे से तीन सौ बीघे में लगे मोटे-मोटे पेड़ों को काट डाला. इस खेल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को वन के अधिकारियों ने बेख़ौफ होकर अंगूठा दिखाया. इस गंदे खेल को वन-अधिकारियों ने वन माफिया से मिल कर खेला. इस तरह से वन के कटने की जानकारी मिलते ही पूरे इलाक़े की जनता ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई. वन माफिया और अधिकारियों को जब लगा कि जनता हर हाल में उनको बेनक़ाब कर देगी तो उन्होंने चाल चली. उन गांववालों की आवाज़ दबाने के लिए शिकायत करने वालों के खेत में मरा बाघ बरामद कर उन्हें परेशान करने की कोशिश की. जब इसके बाद भी जनता की आवाज़ नहीं दबी, तो एक-दो कर्मचारियों पर दिखावे की कार्रवाई कर वन-अधिकारियों ने अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली.

खानपुर के जंगल को लूटने की योजना मुज़फ़्फ़रनगर निवासी कमरुज़्ज़मा ने डीएफओ नरेश कुमार से मिल कर रची. उसने एक प्रार्थना पत्र डीएफओ को देकर वन क्षेत्र में अपनी ज़मीन निकलने का दावा किया. इसी प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्व विभाग या सूबे की सरकार की अनुमति के बिना ही डीएफओ ने अपने मातहतों के साथ घालमेल कर ग़लत दावा करने वाले कमरुज़्ज़मा के हवाले कर दिया. इसने मौका मिलते ही सौ से अधिक खैर और सागवान के हरे-भरे पेड़ों को बिना किसी अनुमति के ही काट दिया गया. हद तो तब हो गई, जब पेड़ों को काटने के बाद आनन-फानन में जेबीसी मशीनों को लगा कर पेड़ों की जड़ तक को निकाल लिया गया. यह सब करके यहां पेड़ों के होने तक के सबूत मिटाने की कोशिश की गई.

यह मामला अब तूल पकड़ चुका है. बहुजन समाज पार्टी के विधायक सुरेंद्र राकेश ने इस मामले को विधानसभा में ज़ोर-शोर से उठाया. विधायक सदन में इस मुद्दे पर चर्चा कराना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने अनुमति नहीं दी. विधायक राकेश हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गए. उनके पीछे बसपा विधायक दल के नेता मोहम्मद शहजाद, विधायक तस्लीमुद्दीन, हरिदास प्रेमानंद महाजन एवं नारायण पाल भी सदन के बीचो बीच पहुंच गए. कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत ने भी बसपा विधायकों की मांग का समर्थन करते हुए स्पीकर से आग्रह किया कि मसले की गंभीरता को देखते हुए इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन स्पीकर ने चर्चा कराना स्वीकार नहीं किया.

फ़िलहाल इस प्रकरण की जांच मुख्य सचिव नृपसिंह नृपच्याल ने पौड़ी सर्किल के वन संरक्षक की अगुआई में बनाई गई टीम को सौंप दी है. इस टीम का नेतृत्व वन संरक्षक जेएस सुहाग कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस घोटाले की जांच के लिए सर्वे आफ इंडिया के राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों को भी टीम में शामिल किया गया है. इस घोटाले का ख़ुलासा जिस कर्मचारी ने अपनी रिपोर्ट में किया, उसे वन के घोटालेवाज अघिकारियों के इशारे पर लगातार तंग किया जा रहा है, इस प्रकरण में पहली जांच करने जब वन संरक्षक सुहाग घटनास्थल पर पहुंचे तो दर्जनों ग्रामीणों ने डबडबाई आंखों से वन माफिआओं एवं वन-अधिकारियों की काली करतूत बयान की. उसी समय वन विभाग के खानपुर रेंजर नवीन चंद्र जोशी ने इसकी जांच सीबीसीआईडी से कराने का प्रस्ताव रखा. इस पर जनता भड़क उठी, जिस पर उनको आश्वासन मिला कि मामले में किसी तरह की लीपापोती नहीं की जाएगी.

इस अवैध जंगल कटाई की ख़बर अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि राजा जी पार्क के बुलंदावाला बीट से भी सागवान व खैर के सौ से अधिक पेड़ों के काटने की ख़बर आई है. इससे सरकारी कर्मचारियों एवं वन माफिया के मिले होने की बात उजागर हो गई है. सरकार ने जंगली जानवरों से ग्रामीणों को बचाने के लिए सुरक्षा दीवार बनाई. अब यही दीवार जंगल एवं उसकी बहुमूल्य संपदा के लिए असुरक्षा का कारण बन गई है. राजा जी पार्क की स्थापना 1985 में हुई. इससे पहले यह रिजर्व फॉरेस्ट था. इसी दौरान बुलंदावाला बीट में सागवान, खैर, सेमल और यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए गए थे. मौजूदा समय में ये पेड़ काफी लंबे-चौड़े हो गए थे.

वन के लूटने- कटने की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है. गजणा, मोतीचूर, धौलखंड और हाल के खानपुर प्रकरण, सभी में वन विभाग हर कहीं वन तस्करों के सामने लाचार नज़र आता है. कार्रवाई कुछ छोटे कर्मचारियों पर ही हो पाती है और बड़े अधिकारी अपनी ऊंची पहुंच के कारण बच जाते हैं. राजा जी पार्क में पहले भी अवैध कटान के लगभग 250 मामले प्रकाश में आए थे, इनमें से एक में भी कोई दोषी हत्थे नहीं चढ़ा. गाजणा प्रकरण में प्रमुख वन संरक्षक रैंक के एक अधिकारी का नाम आया था, जिसने ज़मीन की प्लाटिंग करके बेचा था. हालांकि इस मामले में एक डीएफओ रैंक के अधिकारी को निलंबित एवं नीचे के कुछ अधिकारियों को ही दंडित किया गया. बड़े अधिकारी को बचा लिया गया. 14 और 18 मार्च को मोतीचूर रेंज में दो बड़ी घटनाएं हुई और दोनों में अभियुक्त फ़रार हो गए. 19 मई को वन कर्मियों ने धौलखंड में वन तस्करों का पीछा किया, लेकिन मुख्य अभियुक्तों तक वन कर्मी नहीं पहुंच सके.खानपुर प्रकरण में डीएफओ नरेश कुमार की भूमिका जगज़ाहिर है, लेकिन सिर्फ़ दो वन रक्षकों पर ही गाज गिरी.

हमारे जीवन-मरण से जुड़े जंगलों की हर हाल में रक्षा होनी चाहिए. इसी साल गर्मी में उत्तराखंड के जंगलों में सौ से अधिक जगह आग लगने की घटना घटी, जिनमें बड़ी वन संपदा जल कर राख हो गई. लेकिन आज तक किसी बड़े अधिकारी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि जंगलों में आग किसने और कैसे लगाई? मुख्यमंत्री पद पर डॉ. रमेश पोखरियाल के आने के बाद लोगों में आस जगी थी, लेकिन जिस तरह जंगल पर आफत बढ़ती जा रही है, उससे लोगों की उम्मीदें टूटने लगी हैं.

feedback@chauthiduniya.com

प्रकृति की गोद में खिले भविष्य

रीतिका सोनाली

जंगल हमारी धरती और समाज का महत्वपूर्ण अंग हैं. कई जीव-जंतुओं और बंजारों को पनाह देने के अलावा यह वाता-वरण को शुद्ध और संतुलित बनाए रखने में सहायक होते हैं. अपने अंदर कई प्रकार की प्राकृतिक संपदा समेटे ये जंगल मानव-जाति के सच्चे मित्र भी होते हैं. शहरीकरण की वजह से जंगल भले कटते जा रहे हैं, लेकिन इनका महत्व और ज़रूरत देखकर सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से जंगल बचाने की कोशिशें भी की जा रही हैं. वर्ष 2009 के आम बजट में वनों को पांच सौ करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है. वनों के संरक्षण और वन्य जीव-जंतुओं की देखभाल की ओर उठे क़दम का एक महत्वपूर्ण भाग है, कृषि और वन की देखभाल की जानकारी देने वाले कोर्स यानी फॉरेस्ट्री विषय की शिक्षा का प्रसार. फॉरेस्ट्री एक ऐसा विषय है जिसमें वन-संरक्षण के वैज्ञानिक तथा प्राकृतिक उपायों के बारे में जानकारी दी जाती है. इसके अलावा जंगल की संपदा के इस्तेमाल का ध्यान रखना और नष्ट हो रही चीज़ों के संरक्षण के तरीक़े सिखाए जाते हैं. हालिया आंकड़ों के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं. जंगलों की दुर्दशा देखते हुए वन विभाग को जंगल संरक्षण के लिए प्रशिक्षित लोगों की ज़रूरत है. फॉरेस्ट्री/एग्रो फॉरेस्ट्री प्रबंधन एक महत्वपूर्ण ज़रूरत है जिससे जंगली पर्यावरण को बचाने के प्रयास के लिए शोध आधारित प्रणाली का विकास किया जा सके. पर्यावरण संरक्षण की वैज्ञानिक पद्धति के शिक्षण की शुरुआत भारत में 1864 में हुई. इसके तहत फॉरेस्ट्री विषय में शिक्षा ले रहे फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल्स को फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी वन्य प्रबंधन की शिक्षा दी जाती है. देश में विश्वविद्यालय स्तर पर फॉरेस्ट्री की पढ़ाई राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से शुरू हुई थी. वन व कृषि मंत्रालय मुख्य तौर से आठ संस्थानों का संचालन करता है जिनमें देहरादून स्थित इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन प्रमुख हैं. इसके अलावा वन व कृषि विभाग में रिसर्च प्रशिक्षण, एक्सटेंशन व शिक्षण के लिए इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकादमी, देहरादून व डायक्टरेट ऑफ फॉरेस्ट्री एजुकेशन के तहत स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज कॉलेज (राज्य स्तरीय), वाइल्डलाइफ इंस्टीटयूट ऑफ इंडिया, देहरादून, इंडियन प्लाईवुड इंड्स्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीटयूट, बेंगलुरू, जीबी पंत इंस्टीटयूट ऑफ हिमालयन इंवॉयरमेंट एंड डेव-लेपमेंट, अल्मोड़ा बड़े नाम हैं. इन संस्थानों में फॉरेस्ट्री प्रबंधन जैसे विषयों की विश्वस्तरीय शिक्षा दी जाती है.

फॉरेस्ट्री में स्नातक कोर्स के लिए :-

इंटरमीडिएट स्तर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायलॉजी विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी फॉरेस्ट्री के स्नातक स्तर में प्रवेश पा सकते हैं. इसके बाद विश्वविद्यालयों व संस्थानों की ओर से ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होकर ही नामांकन पा सकते हैं. कुछ विश्वविद्यालयों में परीक्षार्थी के मेरिट के अनुसार प्रवेश दिया जाता हैं, जबकि कुछ में उन्हें तरजीह दी जाती है, जिन्होंने वार्षिक तौर पर आईसीएआर द्वारा कराई गई अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण किया हो.

स्नातक से आगे के कोर्स के लिए-:

पोस्ट-ग्रेजुएट स्तर पर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स, वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वाइल्डलाइफ साइंस, वेटरेनरी साइंस जैसे क्षेत्रों में पढ़ाई के लिए सोच सकते हैं. फॉरेस्ट्री में स्नातक स्तर के विद्यार्थी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए आ-वेदन भर सकते हैं. शोध उपाधि के लिए चुने हुए विषय में तीन वर्ष का पठन-पाठन अनिवार्य है. भोपाल स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट देश का इकलौता संस्थान है, जहां फॉरेस्ट मैनेजमेंट का पाठ्यक्रम उपलब्ध है. स्नातक कर चुके विद्यार्थी राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों व अन्य संस्थानों में फॉरेस्ट्री या एग्रो फॉरेस्ट्री की मास्टर्स डिग्री के लिए आवेदन भर सकते हैं. इसमें चयनित होने के लिए या तो मेरिट अंक की आवश्यकता होती है या प्रवेश परीक्षा में बैठना होता है. आईसीएआर की ओर से जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा देनी होती है. इसके तहत उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय के 25 प्रतिशत सीटों में जगह मिल जाती है. इसी तरह पीएचडी करने के लिए भी राज्य स्तरीय संस्थान व विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं. जबकि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के तहत फॉरेस्ट्री में प्राध्यापक की डिग्री मिल जाती है. यह परीक्षा आईसीएआर के तहत सालाना एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से लिया जाता है.

नौकरी के अवसर

1 **वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी/वाइल्ड लाइफ पत्रकारिता:** अभी नए होने की वजह से इन विषयों की काफी मांग है. ग्लैमर होने के साथ इसमें कमाई भी अच्छी होती है.

2 **फिल्ममेकिंग :** टेलीविजन चैनलों जैसे डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक इत्यादि की लोकप्रियता देखकर ये समझा जा सकता है कि जंगल जनजीवन पर आधारित फिल्मों में लोगों की रुचि कितनी ज़्यादा है. इसके अलावा सरकारी, ग़ैर-सरकारी संस्थान भी वन्यजीवन पर बनी फिल्मों या वृत्तचित्रों की मांग करते हैं.

3 **वाइल्डलाइफ वकील :** वन्य जनजीवन को क्षति पहुंचाने वाली ग़ैर-क़ानूनी हरकतें जैसे पोचिंग (शिकार), स्मगलिंग(तस्करी) व जानवरों के साथ दुर्व्यवहार के ख़िलाफ़ कार्रवाई में वाइल्डलाइफ वकील की आवश्यकता पड़ती है. वन्य जीवन के क़ानूनों की जानकारी रखने वालों के लिए एक शानदार भविष्य के साथ ही इस क्षेत्र में पैसे की भी कोई कमी नहीं है.

4 **पर्यावरणविद :** अगर आप प्रकृति से प्रेम करते हैं तो आप विभिन्न संस्थानों में आप इसके अलग-अलग पहलुओं को समझ सकते हैं. इस तरह पयार्वरण में विशेषज्ञता हासिल कर आप सरकारी या ग़ैर-सरकारी संस्थानों के साथ काम कर सकते हैं. एक पर्यावरणविद इन संस्थाओं को पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर सलाह देता है.

5 **वाइल्डलाइफ इतिहासकार :** इनकी आवश्यकता भी सरकारी-ग़ैर सरकारी संस्थाओं को पड़ती रहती है. बहुत कम लोगों को इस क्षेत्र के बारे में जानकारी है. ऐसे में इसमें करियर बनाने का सुनहरा अवसर धरा रह जाता है.

6 **वाइल्डलाइफ कंसलटेंट :** अहमदाबाद स्थित सेंटर फॉर एनवायर्नमेंट एजुकेशन, वर्ल्ड वा-इल्डलाइफ फंड, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट व कंसलटेंसी फर्म जैसे अर्नस्ट और केपीएमजी अपने वातावरण संबंधी प्रोजेक्टों के लिए वाइल्डलाइफ कंसलटेंटों को अच्छे वेतन पर नियुक्त करते हैं.

7 **एनजीओ :** वन संरक्षण के लिए कई कॉरपोरेट व स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी क़दम बढ़ाए हैं, इनसे जुड़ कर भी शोहरत व पैसा कमाया जा सकता है. इनसे जुड़कर एक अच्छे काम का हिस्सा बनने का संतोष भी मिलता है.

8 **अध्यापन :** पर्यावरण संबंधी मामलों में अच्छी जानकारी होने पर इसी क्षेत्र में शिक्षण का कार्य भी किया जा सकता है.

9 **वन्य उद्यान :** पार्कों व चिड़ियाघरों की कमान संभाल कर भी अच्छा वेतन पाया जा सकता है. इस क्षेत्र में जीवन यापन की सुविधाओं की कोई कमी नहीं है. इसके अलावा आकर्षक वेतन का लाभ तो है ही. इसलिए फॉरेस्ट्री का कोर्स करने वालों के लिए मौके ही मौके हैं. बस एक बार फ़ैसला करके तो देखें.

ritika@chauthiduniya.com

लुप्त होती जा रही हैं बुंदेली लोक नृत्यकला

बुंदेलखंड की लोक संस्कृति में सामाजिक तथा जातीय गुणों को पेशेवर तरीक़े से सामाजिक परिवेश में जोड़ने के लिए विभिन्न नृत्यों की परंपरा विद्यमान है. सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन के दौर में संक्रमण काल से गुज़र रहे बुंदेली भू-भाग में लोक नृत्य अब विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं. बुंदेली लोक नृत्य परंपराओं को बचाने के लिए समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो सैरा नृत्य, डोमरहा नृत्य, जवारा नृत्य, कीर्तन नृत्य, कानड़ा नृत्य, चांचरा या पाइ-डंडा नृत्य, झांझिया नृत्य, मोनिया नृत्य, देवी नाच, चमराहा नृत्य, कहारों का नाच, राई नृत्य, ढिमराई नृत्य, कुम्हराई नृत्य, दुलदुल घोड़ी नाच, खशुआ नाच और चांगलिया नाच सिर्फ़ अतीत का हिस्सा बनकर रह जाएंगे.

कानड़ा नृत्य धोबी जाति का परंपरागत नृत्य है. भगवान कृष्ण या कान्हा से संबंधित इस नृत्य को नया जीवन तथा नया संबल दिलाने वाले सागर के लक्ष्मीनारायण रजक ने कहा था कि किसी जमाने में कानड़ा नर्तकों को समाज में इतना सम्मान और नेग मिलता था कि उसे और कहीं जीविकोपार्जन के लिए नहीं भटकना पड़ता था. पहले विवाह में पग-पग पर कनाड़ियाई होती थी. आजकल कानड़ा को कोई बुलाते नहीं हैं. पहले कानड़ा विवाह का अनिवार्य अंग था इसलिए कानड़ा के बहुत से कलाकार होते थे लेकिन आजकल कानड़ा नृत्य के स्थान पर विवाह में लोग बैंड बाजों या रिकार्डिंग से काम निकालने लगे हैं, इसलिए कानड़ा नृत्य के कलाकार आज न के बराबर हैं. इससे हमारे लोक कला जगत की एक महत्वपूर्ण विधा को बहुत बड़ी हानि हुई है. पहले एक ही विवाह में दो-तीन कानड़ा नर्तक पहुंचते थे और वहां प्रतिस्पर्धा होती थी. प्रत्येक कानड़ा कलाकार अपनी-अपनी कला के माध्यम से श्रेष्ठता सिद्ध करता था. अब तो गणेश उत्सव या नवरात्रि उत्सव ही कानड़ा नृत्य के अवसर रह गए है. कभी-कभी शिशु जन्म पर ख़ुशी से कोई-कोई कनिड़ाई गंवाते नचवाते हैं. जब सारंगी, मृदंग, लोटा, झूला, कसावरी, टिमकी और खजरी की संगत के साथ कानड़ा गीत में बुंदेली शब्द, बिरहा, रमपुरिया, राई सैरा, दादरों की धुन लय ताल में निकालते हैं, तो कानड़ा नर्तक की पैरों की थिरकन और कमर की लचक तथा नृत्य की वृत्तीय गतियां देखते ही बनती है. लक्ष्मीनारायण रजक कानड़ा के दक्ष कलाकार हैं. उन्होंने इस नृत्य को नई गति प्रदान की थी. श्री रजक ने कृष्ण लीला, रामचरित महाभारत की कथाओं श्रृंगार तथा सामाजिक विषयों पर कानड़ा की परंपरागत धुनों में बुंदेली की कई रचनाएं की और अन्य कवियों के छंदों को गाना शुरू किया.

> **लोक संस्कृति विभाग सिर्फ़ नाम के आयोजन करके भारी धनराशि लोक संस्कृति के नाम पर व्यय तो कर रही है लेकिन इन नृत्यों को बचाने के लिए कुछ सार्थक प्रयास नहीं हो रहे हैं. झांझिया नर्तक द्वारा गाए जाने वाला यह गीत *हरी री चिरैया, तोरे पियेर रे पंख, सो उड़-उड़ जाए, बबुरा तोरी डार* की गति हो रही है. राई नृत्य करने वाली बेड़नी की हालत अत्यंत ख़राब है.**

लोक संस्कृति विभाग सिर्फ़ नाम के आयोजन करके भारी धनराशि लोक संस्कृति के नाम पर व्यय तो कर रही है लेकिन इन नृत्यों को बचाने के लिए कुछ सार्थक प्रयास नहीं हो रहे हैं. झांझिया नर्तक द्वारा गाए जाने वाला यह गीत *हरी री चिरैया, तोरे पियेर रे पंख, सो उड़-उड़ जाए, बबुरा तोरी डार* की गति हो रही है. राई नृत्य करने वाली बेड़नी की हालत अत्यंत ख़राब है. राई, बुंदेलखंड के श्रेष्ठतम लोक नृत्यों में से हैं. भादो में कृष्ण जन्माष्टमी से प्रारम्भ होकर, यह नृत्य फाल्गुन माह में होली तक चलता है. बेड़िनियां यह नृत्य करते हुए, अपने शरीर को इस प्रकार लोच और रूप देती हैं कि बादलों की गड़गड़ाहट पर मस्त होकर नाचने वाले मोर की आकृति का आभास मिलता है. इसका लहंगा सात गज से लेकर सत्तर गज तक घेरे का हो सकता है. मुख्य नृत्य मुद्रा में अपने चेहरे को घूंघट से ढंककर लहंगे को दो सिरों से जब नर्तकी अपने दोनों हाथों से पृथ्वी के सामानांतर कंधे तक उठा लेती है, तो उसके पावों पर से अर्द्ध चंद्राकार होकर, कंधे तक उठा यह लहंगा नर्तकों को मयूर के खुले पंखों का आभास देता है. नृत्य में पद संचालन इतना कोमल होता है कि नर्तकी हवा में तैरती सी लगती है. इसमें ताल दादरा होती है. पर अंत में कहरवा अद्धा हो जाता है साथ में पुरुष लोक धुन गाते हैं.

नृत्य की गति धीरे-धीरे तीव्र होती जाती है. राई में ढोलकिया की भी विशिष्ट भूमिका होती है. एक से अधिक छोलकिए भी नृत्य में हो सकते है. ढोलकिएं नाचती हुई नर्तकी के साथ ढोलक की थाप पर उसके साथ आगे-पीछे बढ़ते हैं, बैठते हैं, चक्कर लगाते हैं. नृत्य चरम पर ढोलकियां दोनों हाथों के पंजों पर अपने शरीर का पूरा बोझ संभाले हुए, टांगे आकाश की ओर कर, अर्द्धवाकार रेखा बनाकर आगे-पीछे चलता है. इस मुद्रा में इसे बिच्छू कहा जाता है. राई नृत्य में नर्तकी की मुख्य पोशाक-लहंगा और ओढ़नी होती है. वस्त्र विभिन्न चमकदार रंगों के होते हैं.

दोनों हाथों में रूमाल तथा पांवों में घूंघरू होते हैं. पुरुष (वादक) बुंदेलखंडी पगड़ी, सलूका और धोती पहनते हैं. राई के मुख्य वाद्य ढोलक, डफला, झींका, मंजीरा, तथा रमतुला हैं. इस लोक नृत्यों को बचाने के लिए बुंदेलखंड में ही लोक संस्कृति केंद्र की स्थापना ज़रूरी है. तभी बुंदेली लोक गीत, नृत्य, तथा लोक वाद्य सुरक्षित और संरक्षित रह सकेंगे.

सुरेंद्र अग्निहोत्री

feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

(3 अगस्त से 9 अगस्त तक)

मेष 21 मार्च से 20 अप्रैल
वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, नहीं तो दुर्घटना होने की आशंका है. आपको किसी भी कार्य में अधीनस्थ कर्मचारी का सहयोग प्राप्त होगा. आप अगर आर्थिक क्षेत्र में कुछ कार्य करने की सोच रहे हैं तो संभल कर करें, क्योंकि कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

वृष 21 अप्रैल से 20 मई
आप कार्यों में अधिक व्यस्त रहेंगे, जिसके कारण आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आएगा. परिवार के साथ आपका समय सुख के साथ गुज़रेगा. शासन सत्ता का सहयोग रहेगा. व्यावसायिक कार्य अगर आप साझे में करना चाहते हैं तो विचार-विमर्श करके ही निर्णय लें.

मिथुन 21 मई से 20 जून
आप अपने किसी कार्य में अगर किसी संबंधित अधिकारी या बड़े भाई से सहयोग लेंगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी. आपको अनचाही यात्रा भी करनी पड़ सकती है. साथ ही अनचाहे लोगों से मिलना हो सकता है. किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि सफलता के योग हैं.

कर्क 21 जून से 20 जुलाई
आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकता है, जिससे मन बेहद ख़ुश रहेगा. पारिवारिक मामलों में अगर कोई प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होगी. पेट से संबंधित कोई शिकायत हो सकती है, डॉक्टर से सलाह लें.

सिंह 21 जुलाई से 20 अगस्त
समाज के लिए काम करेंगे तो उसमें प्रतिष्ठा प्राप्त होगी. किसी भी कार्य में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. कार्य क्षेत्र में आप जो प्रयास कर रहे थे, वह सफल हो जाएगा. पारिवारिक मामलों में किया जा रहा प्रयास सफल होगा. आपको कहीं से अचानक लाभ मिलने की संभावना है.

कन्या 21 अगस्त से 20 सितंबर
कुछ ऐसा न करें जिससे बाद में आपको व्यर्थ की परेशानी से जूझना पड़े. अगर किसी के साथ मनमुटाव चल रहा था, तो वह समाप्त हो जाएगा. रचनात्मक कार्य और ज़मीन जायदाद मामले में अगर लगे हैं तो पूरे हो जाएंगे. आर्थिक मामलों में किए जा रहे प्रयास सफल होंगे.

तुला 21 सितंबर से 20 अक्तूबर
संतान के दायित्व की पूर्ति होगी. सोच-समझ कर निर्णय लेंगे तो हर काम में सफलता ज़रूर मिलेगी. जीवनसाथी का भरपूर साथ मिलेगा. सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि पिता से छोटी-छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं. अपनी वाणी की मधुरता बनाए रखें.

वृश्चिक 21 अक्तूबर से 20 नवंबर
आप अगर घर में किसी मांगलिक कार्य की दिशा में सक्रिय हैं, तो उसमें सफलता मिल सकती है. पारिवारिक मामलों में किए जा रहे प्रयास आसानी से सफल होंगे. आमोद-प्रमोद के अवसर प्राप्त होंगे. घर से कहीं बाहर रहने की स्थिति आ सकती है, लेकिन उसे टालने में ही भलाई है.

धनु 21 नवंबर से 20 दिसंबर
आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. कार्यक्षेत्र का विस्तार तो होगा, साथ ही आप बहुत व्यस्त भी रहेंगे. कार्यस्थल पर सहयोगी साथ देंगे. भक्ति भावना में वृद्धि होगी. अगर आप उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं तो अपने स्वास्थ्य की तरफ़ ध्यान ज़रूर दें.

मकर 21 दिसंबर से 20 जनवरी
किसी पर अधिक विश्वास न करें, क्योंकि वह आपके लिए हानिकारक हो सकता है. आपका कोई काम जो अधूरा पड़ा है, वह पूरा होगा. ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी. काम में आपको आलस्य अधिक आएगा. किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है.

कुंभ 21 जनवरी से 20 फरवरी
आपको कहीं लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है. आर्थिक मामलों में पिता से अपेक्षित सहयोग मिलेगा. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. साथ ही समय-समय पर चिकित्सक से सलाह अवश्य करें. बाज़ार में साख और विश्वसनीयता बढ़ेगी.

मीन 21 फरवरी से 20 मार्च
दूसरों से काम निकालने में सफल होंगे. कुछ ऐसा न करें जिससे आपको बेकार की परेशानी के कारण तनावग्रस्त रहना पड़े. लेन-देन करेंगे तो विवाद अवश्य ही होगा, लेकिन परिवार वालों का सहयोग मिलेगा. किसी दिशा में प्रयासरत हैं तो सफलता प्राप्त होगी.

ज्योतिषाचार्य पं. सुदर्शन

धार्मिक यातना गाथा

अनंत विजय

जब आस्था से धर्म का संगम होता है तो वह श्रद्धा में बदल जाता है. जहां श्रद्धा हो, वहां आप सवाल खड़े नहीं कर सकते क्योंकि श्रद्धा और आस्था हर तरह के सवालों और प्रश्नों से परे हैं. अगर हम भारतीय साहित्य ख़ासतौर पर हिंदी के रचनात्मक लेखन पर ग़ौर करें तो यही बात हमें साफ़-साफ़ दिखाई देती है. भाषणों और लेखों में तो धर्म की कुरीतियों और अंधविश्वास पर जमकर हमले हुए हैं या होते रहे हैं, लेकिन कहानी, उपन्यास या फिर कविता में देवी-देवताओं या फिर धार्मिक मान्यताओं पर लिखने में लेखक हिचकते रहे हैं. हिंदू देवी-देवताओं और मान्यताओं और रूढ़ियों पर तो हज़ारों लेख लिखे जा चुके हैं, सैकड़ों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, और कई तो उल-जलूल तर्कों के आधार पर सिर्फ़ प्रचार पाने की लालसा में लिखे गए हैं, तर्क और वैज्ञानिक आधार के बिना. मुझे याद है बचपन में जब मैं *चंपक* पढ़ा करता था तो उसमें दिल्ली बुक कंपनी की एक पुस्तक *हिंदू समाज पथभ्रष्टक तुलसीदास*- का विज्ञापन प्रमुखता से छपा करता था. चूंकि हिंदू धर्म में सहिष्णुता की गुंजाइश है, इसलिए इस पर उठने वाले सवालों और तीखी आलोचनाओं पर बवाल नहीं मचा करता है. हालांकि हाल के दिनों में कुछ संगठन राजनैतिक लाभ के लिए विरोध और हिंसा पर उतारू हो जाते हैं लेकिन आमतौर पर उन्हें लोगों का ज़्यादा समर्थन हासिल नहीं होता है, लेकिन भारत में किसी और धर्म के साथ यह स्थिति नहीं है. जैसे आप इस्लाम, जैन या फिर ईसाई धर्म पर सवाल खड़े नहीं कर सकते. अगर किसी कोने-अंतरे से कोई सवाल खड़ा होता है तो उसके ख़िलाफ़ लगभग पूरा का पूरा समुदाय खड़ा हो जाता है. मुझे यहां कोई उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है. हर धर्म में अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं, पर कोई भी धर्म क्वेश्चनिंग से परे नहीं हो सकता. प्रगतिशीलता की पहली शर्त ही संदेह है. जो है उस पर संदेह करो, सवाल खड़े करो और बग़ैर बहस के किसी भी सिद्धांत को न मानो. लेकिन मेरे जानते हिंदी में इस्लाम और जैन धर्म पर सवाल करते रचनात्मक लेखन जरा कम ही हुए हैं.

पिछले दिनों कोलकाता की कथाकार मधु कांकरिया का उपन्यास *सेज पर संस्कृत* प्रकाशित हुआ. उपन्यास के शीर्षक से मैं चौंका ज़रूर, लेकिन जब पढ़ना शुरू किया तो तमाम संदेह दफ़न होते गए और लेखिका के साहस से मैं हतप्रभ रह गया. *सेज पर संस्कृत* जैन धर्म में व्याप्त कुरीतियों को तार्किक आधार पर जोख़िम मोल लेते हुए साहसपूर्ण तरीक़े से उठाता है. यह उपन्यास एक ऐसी जवान लड़की की यातना गाथा है जो अपने और अपने परिवार के भविष्य के सुंदर सपने देखती है और उसे पूरा करने के लिए संघर्ष भी करती है, लेकिन धार्मिक आस्थाओं में जकड़ी उसकी ही मां उसके सपनों पर ग्रहण लगाने को आमादा है.

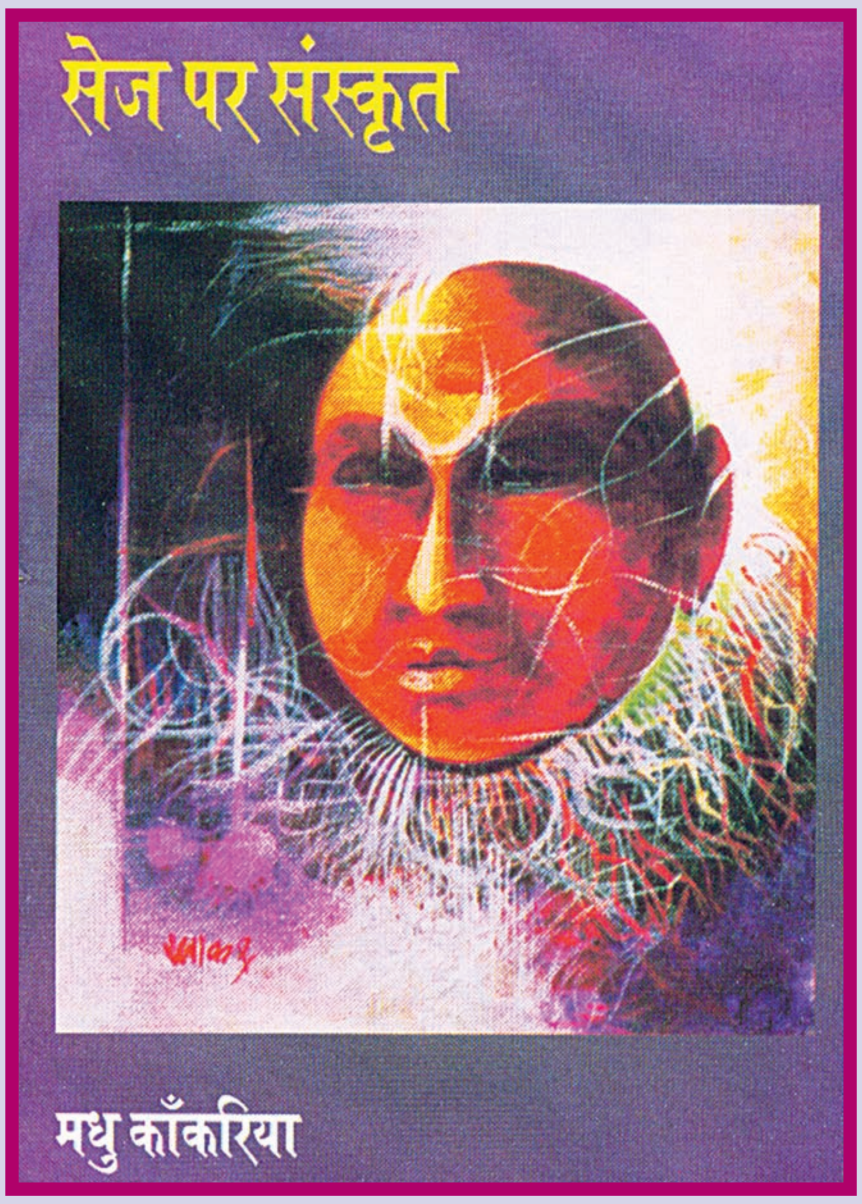

दरअसल यह पूरा उपन्यास एक ऐसी लड़की या यूं कहें कि परिवार के इर्द-गिर्द घूमता है जिसमें पिता की मौत के बाद दो बेटियां अपनी मां के साथ रह जाती है. रिश्तेदारों की नज़र उनकी संपत्ति पर है. बड़ी लड़की संघमित्रा कॉलेज की अपनी पढ़ाई के साथ-साथ घर के लिए आवश्यक ख़र्च जुटाने के लिए दिन रात मेहनत करती है, लेकिन आर्थिक विपन्नता में जकड़े इस परिवार में मां अपने आप को धर्म को समर्पित कर देती है, साथ ही उसकी इच्छा दोनों बेटियां को भी धर्म पर कुर्बान कर देने की है. इस कथा के बहाने लेखिका जैन धर्म में चल रहे अनैतिक कृत्यों को भी बेनकाब करती चलती हैं. इस उपन्यास की केंद्रीय पात्र संघमित्रा बार-बार जैन धर्म पर सवाल करती है, जिसका उत्तर उसे किसी भी श्रमण से नहीं मिल पाता है और उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है. संघमित्रा की मां अपनी छोटी बेटी- छुटकी को जैन धर्म में दीक्षित कराने के लिए कटिबद्ध है. छुटकी की उम्र इतनी कम है कि उसे इन चीज़ों की समझ ही नहीं है और वह दीक्षा के मौके पर होने वाले समारोह को लेकर ही उत्साहित है. लेखिका ने श्रमपूर्वक दीक्षा के वक़्त केश-लुंचन का बेहद ही मार्मिक चित्रण किया है. धर्म के नाम पर एक मासूम बच्ची की भावनाओं के साथ खिलवाड़ और अत्याचार को श्रद्धा समारोह में तब्दील कर सामूहिक हर्ष का अवसर बना दिया जाता है, वह शर्मनाक है. दीक्षा समारोह के बाद लेखिका ने कथा के माध्यम से संघ के अंदर के श्रमणों की कुंठित यौनाकांक्षा का वर्णन किया है. संघ में जो बच्चियां दीक्षित होती हैं, कालांतर में वे जब जवान होती हैं तो उनके अंदर भी सांसारिक सुख-सुविधाओं को भोगने की आकांक्षा हिलोरें लेने लगती हैं. धर्म और मर्यादा के बंधन में जकड़े जवान साधु- साध्वियों के दिलों में एक-दूसरे के प्रति दैहिक आकर्षण उभरता है. उसका एक नमूना विजयेंद्र मुनि और छुटकी, जो दीक्षा के बाद साध्वी दिव्यप्रभा हो चुकी है, के बीच पनपे प्रेम से लगाया जा सकता है. दिव्यप्रभा और विजयेंद्र संघ को छोड़कर नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन विजयेंद्र एक ग़लती कर बैठते हैं और अपने दिल की बात अपने ही एक साथी साधु अभयमुनि को बता देते हैं.

अभयमुनि ख़ुद ही काम की अग्नि में जल रहा होता है और उसे जब इस प्रेम-प्रसंग के बारे में जानकारी मिलती है तो उसकी यौन-लिप्सा इस कदर बेकाबू हो जाती है कि वह छल से साध्वी दिव्यप्रभा का बलात्कार कर डालता है. साध्वी के इंतज़ार में खड़े विजयेंद्र मुनि को झूठी ख़बर दे कर विक्षिप्त भी कर देता है. इस बलात्कार की परिणति साध्वी के मां बनने में होती है और धर्म की पवित्रता की आड़ लेकर वही धर्मगुरु, साध्वी को संघ से निष्कासित कर देते हैं जहां कभी समारोह पूर्वक उसे दीक्षित किया गया था .

ज़िंदगी में हर तरह से ठुकराई साध्वी दिव्यप्रभा एक वेश्या बना दी जाती है, जिसकी बदौलत वह अपनी बेटी ऋषिकन्या का भरण पोषण करने लग जाती है. कहानी में एक बेहद नाटकीय मोड़ आता है और छुटकी से साध्वी बनी दिव्यप्रभा की मुलाक़ात उसकी बड़ी बहन संघमित्रा से होती है, जो एक बड़ा एनजीओ चला रही होती है. छुटकी अपनी बेटी को बहन को सौंप कर दम तोड़ देती है, लेकिन मरने के पहले वह पूरी आपबीती जीजी को सुना जाती है. इंतकाम की आग में जल रही संघमित्रा बेहद ही योजनाबद्ध तरीक़े से अभयमुनि का क़त्ल कर अपनी बहन के साथ हुए अन्याय का बदला लेती है.

इस पुस्तक को पढ़ते हुए मुझे केरल की सिस्टर जेस्मी की आत्मकथा-एन ऑटोबॉयोग्राफी ऑफ अ नन-के कई प्रसंगों की याद आ जाती है कि किस तरह से होली किस के नाम पर फादर ननों का चुंबन लेते हैं और अपने इस कृत्य के लिए धर्म और धर्मग्रंथों की आड़ लेते हैं. ऐसा नहीं है कि ये कुरीतियां सिर्फ़ जैन और ईसाई धर्म में ही हैं. हिंदू धर्म में तो देवदासी प्रथा से लेकर शादी के बाद पंडितों द्वारा लड़कियों के शुद्धिकरण की प्रथा रही है. दरअसल धर्म के नाम पर स्त्रियों के शोषण की ये दास्तां बेहद पुरानी है लेकिन जिस साहस के साथ मधु कांकरिया ने अपने उपन्यास *सेज पर संस्कृत* में उसे उजागर किया है, उसके लिए उन्हें दाद देनी पड़ेगी.

(लेखक आईबीएन7 से जुड़े हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

बौद्ध धर्म और सनातन धर्म

व्यालोक

इसे विडंबना कहें या सनातन धर्म की पचाने की क्षमता, जो भी धर्म या आंदोलन इसकी बुराइयों से निपटने के लिए शुरू हुए, वे भी इसके ही रंग में ही ढल गए. जो भी इसके विरोध में किया गया, कालांतर में वही ठीक सनातनी कलेवर में रंग गया. यही बात बौद्ध धर्म के साथ भी लागू होती है. जाति-व्यवस्था और ढकोसलों के ख़िलाफ़ ही इसकी शुरुआत हुई, लेकिन बाद में चलकर बौद्ध धर्म में भी वही सारे विकार आ गए. जाति-प्रथा बौद्ध धर्म में भी लागू रही, बस शीर्ष पर ब्राह्मण की जगह क्षत्रिय विराजमान हो गया.

बुद्ध ने अवतार की, मूर्तिपूजा की और पुनर्जन्म वग़ैरह को सिरे से नकार दिया था, लेकिन बौद्ध धर्म की महायान शाखा में तो देवताओं की लड़ी ही लग गई. बुद्ध को अवतार घोषित कर दिया गया और बड़ी-बड़ी मूर्तियां मठों में स्थापित कर मूर्ति पूजा भी होने लगी. बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में तो इतनी गंदगी हुई, कि लोग वज्रयानियों को कापालिकों से भी बुरा समझने लगे. ख़ैर, इस पर चर्चा फिर कभी.

कुल मिलाकर इतना ही कि बुद्ध की यह बात लगभग सही सिद्ध हो गई जो उन्होंने आनंद से कही थी. मठों में भिक्षुणियों को शामिल होने की इजाज़त देते हुए बुद्ध ने कहा था- आनंद, पहले यह धर्म शायद 5000 वर्षों तक चलता, लेकिन अब तो यह केवल 500 साल चलेगा, क्योंकि धर्म में भिक्षुणियों को भी आज्ञा मिल गई है. हालांकि बौद्ध धर्म के कालबाह्य होने के पीछे कई कारण थे. बौद्ध धर्म में शुरू से ही तीन मार्ग थे. अर्हत-यान का पालन वे श्रावक करते थे, जिनका लक्ष्य अपना मोक्ष होता था. इसके अलावा जो साधक या श्रावक अपने साथ ही कुछ और लोगों के लिए भी कष्ट सहने को तैयार थे, उनका रास्ता प्रत्येक-बुद्ध-यान था. तीसरा और सबसे कठिन रास्ता बुद्ध-यान का था, जिसपर वही साधक चलता था, जो तमाम जीवों का मार्गदर्शक बनने के लिए अपनी मुक्ति और मोक्ष की फ़िक्र न कर बहुत कष्ट और परिश्रम के बाद ही स्वयं प्राप्त निर्वाण को अपना लक्ष्य मानते थे. आरंभ में तो सभी बौद्ध तीनों यान को मानते थे, लेकिन कालांतर में बौद्ध धर्म का विभाजन इन्हीं के आधार पर हीनयान और महायान में हुआ. कालक्रम में बुद्धयान निःस्वार्थ यान होने के कारण ही महायान कहा जाने लगा जबकि बाक़ी दोनों यानों को हीनयान कहा जाने लगा.

इसके बाद सनातन धर्म का प्रभाव बौद्ध धर्म पर भी पड़ा. मानव स्वभाव मूल रूप से साकार को खोजता है, निराकार से वह ख़ुद को जोड़ नहीं पाता. यही वजह रही कि बाद में बुद्ध की भी विशाल मूर्तियां बनने लगीं और बाक़ायदा उनकी पूजा की जाने लगी. अंधविश्वास और रूढ़ियों का भी बौद्ध धर्म में प्रवेश हो गया और वज्रयान संप्रदाय तो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा कलंक बन गया. भिक्षुणियों के आगमन से नारी-समागम की भी शुरुआत हो गई और मुद्रा के नाम पर कई तरह के अनाचार बौद्ध धर्म का भी हिस्सा बन गए.

महायान का हालांकि ऐतिहासिक महत्व इस वजह से है क्योंकि करुणा और मैत्री का शिखर हम महायान में देखते हैं, ठीक उसी तरह जैसे, अहिंसा का चरम विकास हम जैन धर्म के अनेकांत दर्शन में देखते हैं. बाद में तो ख़ैर बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा भी आ गई और इस पर शाक्त प्रभाव भी पड़ा. अवतारवाद की धारणा भी बौद्ध धर्म का हिस्सा बन गई. इसी वजह से बोधिसत्वों का भी उल्लेख होने लगा. ख़ैर, इन सब पर चर्चा अगले अंकों में.

vyalok@chauthiduniya.com

मुसलमान

पिछले अंक में आपने पढ़ा कि तस्करी का माल उतारते हुए इक़बाल बुरी तरह भींग गया और उसे बुख़ार ने जकड़ लिया. उधर रशीद नशे में गाफ़िल हो चुका था. अब आगे पढ़िए...

इस बीच नींबू, पानी का एक गिलास पीकर रशीद ने अपने नशे को क़ाबू में कर लिया था. इसके बाद दो घंटे की नींद भी उसने ले ली थी. अब वह इक़बाल की ओर देख रहा था. बाक़ी आठों साथी गोला बनाकर खड़े थे. लांच बंबई के किनारे की तरफ़ आगे बढ़ रही थी.

रशीद को शंका हुई-कहीं वह मर तो नहीं गया? उसने इक़बाल के होंठ पर हाथ धरा. गर्म उच्छ्वास का स्पर्श हुआ. फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ. उसने इक़बाल की कलाई अपने हाथ में ली और वह चौंक उठा, इसको तो बुख़ार है. साथियों के सामने देखते हुए उसने ज़ाहिर किया.

लांच घड़ियाल गोदी के घाट में प्रवेश करे, इसके पहले रशीद की दोनों एंबेसडर कारों के साथ एक लॉरी भी आकर डॉक में तैयार खड़ी थी. फौरन सभी आदमी फिर काम में लग गए.

स्टीम लांच में से टंडेल माल उठाकर देते गए. कतारबद्ध खड़े आदमी एक-दूसरे को पास करते गए. पेटियां लॉरी में चढ़ाई जाती रहीं. अंत में बेहोश इक़बाल का शरीर भी पेटी की तरह बाहर आया.

कार में इतनी नहीं थी कि उसे लिटाया जा सके, इसलिए रशीद ने उसे पेटियों के ऊपर लॉरी में ही सुला दिया. सावधानी के लिए दो आदमी उसके पास बैठा दिए गए.

तीनों गाड़ियों का क़ाफ़िला बंदरगाह से निकलकर डोंगरी की दिशा में आगे बढ़ा तो भोर हो चुकी थी. हवा और पानी का तूफ़ान थम गया था. पर अभी सूर्य नहीं दिखाई दे रहा था. मकानों, वृक्षों से अभी भी बूंदें टपक रही थीं. गटरों में पानी बह रहा था.

गाड़ियों का क़ाफ़िला बाड़ीबंदर से डोंगरी की तरफ़ मुड़ा और इक़बाल जाग उठा. सिर के ऊपर दौड़ते मैले बादल थे. शरीर तप रहा था. कंपकंपी के साथ अब ऐंठन भी आ रही थी.

साथ में सफ़र कर रहे रशीद के दोनों आदमियों ने उसे तालपत्री ओढ़ा दी. इससे कोई ख़ास फ़र्क़ नहीं पड़ा. उसके कांपते शरीर के साथ तालपत्री भी कांपने लगी.

डोंगरी चारनल आकर क़ाफ़िले ने फिर मोड़ लिया. आगे लॉरी थी. उससे थोड़ा अंतर रखकर दोनों एंबेसडर कारें आ रही थीं. पालागली में दाख़िल होकर क़ाफ़िला रुक गया. यहीं रशीद का घर था और गोदाम भी.

कार से निकलकर रशीद ने लॉरी तक दौड़कर आते हुए पूछा, इक़बाल को होश आया?

ऊपर बैठे दोनों साथियों में से एक ने हां में जवाब दिया. फिर जोड़ा, लेकिन हालत पतली है.

साथियों को माल उतारने का आदेश देकर वह डॉक्टर की खोज में दौड़ गया. लगभग आधे घंटे बाद वह किसी डॉक्टर को कच्ची नींद में से जगाकर यहां तक लाने में कामयाब हुआ था.

अब तक लॉरी ख़ाली हो चुकी थी. विदेशी शराब की 175 पेटियां गोदाम में पहुंच चुकी थीं. इक़बाल को उठाकर रशीद परकार के घर में सुला दिया गया था.

डॉक्टर ने इक़बाल की जांच कर बताया, न्यूमोनिया हो गया है. (मैं टायफायड का शिकार होने वाला था.)

स्कूल लाइफ़ पूरी कर कॉलेज में प्रवेश करना एक अनोखा आनंद होता है, जिसे भोगना सभी विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं होता. इसके अनेक कारण गिनाए जा सकते हैं. पर इसका एक मुख्य कारण ग़रीबी है.

उस समय हमारे विद्यालय हबीब हाईस्कूल के लगभग सभी विद्यार्थी मध्यम-वर्ग और उससे निम्न तबके के, यानी कंगाल थे. उन्हें प्रोत्साहन देने में हमारे हेडमास्टर शेख़ हसन ने पूरा जीवन दांव पर लगा दिया. शिक्षा और भूख इन दोनों मोर्चों पर वे सतत लड़ते रहे, लेकिन मुसलमानों की ग़रीबी के सामने वे प्रभावशाली टक्कर नहीं ले सके. अलबत्ता यह उनका क्षेत्र भी नहीं था.

हबीब हाईस्कूल का इतिहास देखें तो पता चलेगा कि यहां के विद्यार्थी आज टॉप के इंजीनियर हैं तो टॉप के तस्कर भी. टॉप के वकील, डॉक्टर, कलाकार हैं तो टॉप के गुंडे भी. टॉप के व्यापारी हैं तो बेजोड़ जेबकतरे भी.

साथियों को माल उतारने का आदेश देकर वह डॉक्टर की खोज में दौड़ गया. लगभग आधे घंटे बाद वह किसी डॉक्टर को कच्ची नींद में से जगाकर यहां तक लाने में कामयाब हुआ था. अब तक लॉरी ख़ाली हो चुकी थी. विदेशी शराब की 175 पेटियां गोदाम में पहुंच चुकी थीं. इक़बाल को उठाकर रशीद परकार के घर में सुला दिया गया था.

ऐसा स्पष्ट विरोधाभास आपको शायद किसी दूसरे स्कूल के भूतपूर्व विद्यार्थियों में देखने को न मिले. स्वर्गवासी शेख़ हसन जैसे शिक्षक भी लाखों में एक होते हैं (इक़बाल उनके आख़िरी बैच में था.).

कॉलेज में पहला क़दम रखना यानी बचपन से जवानी में छलांग लगाना. जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश के समय मुझे लगा कि मेरा बचपन मुझसे छूटकर कहीं पीछे रह गया है. मेरे सामने मेरी जवानी का फूलों से गमकता हरियाला मार्ग है. नई दुनिया है, नए चेहरे, नई जान-पहचान है.

न मैं किसी फिल्म स्टार जैसा ख़ूबसूरत था, न मिस्टर यूनिवर्स जैसा हृष्ट-पुष्ट. इक़बाल की तरह मेरा भी हुलिया एक सामान्य युवक जैसा था. छोटे-छोटे बाल, तीखी नाक, आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा, उठी हुई चीक-बोन, लंबी गर्दन और पतली काया. फिर भी मेरी लोकप्रियता बढ़ती गई. युवकों की अपेक्षा युवतियां मेरे प्रति आकर्षित होती गईं. कारण?

कॉलेज के पहले वर्ष में ही मैंने पढ़ाई और खेलकूद में अपना सिक्का जमा दिया था. टेबल-टेनिस की वार्षिक प्रतियोगिता में मैं हर वर्ष एक कप जीतने वाला था. हर वर्ष प्रथम पांच में स्थान प्राप्त करने के कारण मुझे छात्र-वृत्ति भी मिलने वाली थी. पांचों साल के अभ्यास-क्रम के लिए मेरी फीस माफ़ हो जाने वाली थी. इसके अलावा अंतर-कॉलेज हिंदी नाट्य-स्पर्धा में श्रेष्ठ अभिनय के लिए मैं पुरस्कार भी जीतने वाला था.

कॉलेज के पहले वर्ष में एक साथ चार दिनों की छुट्टियां आईं. मेरे वर्ग की एक ईरानी लड़की ने तीन दिन की एक ट्रिप रखने का निश्चय किया. दहाणू में उसकी चीकू की बाड़ी और बंगला था. इस ट्रिप के बारे में उसने मेरा विचार पूछा. मुझे क्या एतराज़ होता?

फ़ौरन हम दोनों ने एक साथ बैठकर लगभग एक दर्जन विद्यार्थियों के नामों की एक सूची तैयार कर ली (छह युवक और छह युवतियां). जाने के लिए गुरुवार का दिन तय हुआ. शुक्रवार और शनिवार वहां बिताकर रविवार को हम वापस लौटने वाले थे.

गुरुवार आए इसके पहले ही मेरे सिर में दर्द होना शुरू हो गया. एकाएक ऐसा क्यों हुआ होगा, यह मैं नहीं समझ पाया. मैंने सिर-दर्द की दो टिकियां लीं और दर्द रुक गया.

ट्रिप के दिन सुबह मैं अपना बैग तैयार कर रहा था और सिर में फिर से दर्द कुलबुलाने लगा. कुछ समय तक मैं दुविधा में खड़ा रहा-ट्रिप में जाऊं कि नहीं? कॉलेज का मेरा यह पहला वर्ष और पहली ट्रिप थी. इस उत्साह के कारण सिर के दर्द को अहमियत न देते हुए मैंने दो और गोलियां लीं और घर से निकल पड़ा. दादर स्टेशन पर चार लोग रंग-बिरंगे लिबास में मेरा इंतज़ार करते खड़े थे. एक मित्र स्ट्रो-हैट भी पहनकर आया था. लड़कियां जंपसूट, जींस तथा स्कर्ट-ब्लाउज़ में थीं. मेरे शरीर पर हैंडलूम का गुलाबी शर्ट तथा गहरे रंग का पैंट था. वातावरण हंसी और मुस्कानों में छलक रहा था. गोलियों के असर से मेरा सिर-दर्द ग़ायब हो गया था.

प्लेटफॉर्म पर गाड़ी के आते ही हम डिब्बे में घुसे. शांत कंपार्टमेंट होहल्ले से भर गया. गीत गाते, मौज-मज़ा करते हम दो घंटे में दहाणू पहुंच गए.

स्टेशन से चीकू की बाड़ी ज़्यादा दूर नहीं थी. मौसम ख़ुशनुमा था. दिन बरसात के थे. सड़क कहीं-कहीं टुकड़े-टुकड़े में भीगी थी. शायद रात में यहां थोड़ी बरसात पड़ी होगी. खुली हवा में क़दम बढ़ाते, पानी के चहबच्चों में पांव पछाड़ते हम बाड़ी पार करके बंगले पर पहुंचे तो उस समय सुबह के दस बजे थे. बंगले के पीछे कहीं समुद्र गुर्रा रहा था.

मैं वहां सिर्फ़ सैर करने के लिए नहीं आया था. अपने साथ मैंने स्केच-बुक तथा रंग का डिब्बा भी ले लिया था. मेरी योजना आधा समय दहाणू के रेखाचित्र खींचने तथा बाक़ी आधा समय मित्रों के साथ बिताने की थी.

न मैं मौज-मज़ा कर सका, न चित्र का ही काम. बंगले में पांव पसारते ही मेरे सिर में नगाड़ा बजने लगा. साथ बुख़ार भी शुरू हुआ. बाहर खुले चौगान में दोस्त म्यूजिकल चेयर का खेल खेलने के लिए कुर्सियां लगा रहे थे. खिड़की के क़रीब बैठकर मैं सब कुछ देख रहा था.

(अगले अंक में जारी)

हंस बचाएगा हैकिंग से

वर्ष 2005 की बात है. एक 18 वर्षीय विद्यार्थी की ई-मेल हैक हो गई और उसका महत्वपूर्ण आंकड़ा जाता रहा. उस आंकड़े को फिर पाने के लिए उसने न जाने कहां-कहां की खाक छानी, लेकिन सब जगह निराशा हाथ लगी. वह जिस किसी भी हैकर के पास जाता, उससे मोटी रक़म की डिमांड की जाती. इसके अलावा उसे पक्का आश्वासन भी नहीं मिलता कि डाटा मिल जाएगा. मोटी रकम ख़र्च करने में असमर्थ इस विद्यार्थी ने ठान लिया कि वह अपनी तरह की परेशानी से जूझने वाले दूसरे लोगों की मदद के लिए शोध करेगा. उसने सोचा कि वह इस तरह की परेशानियों से दो-चार हो रहे लोगों की बिना पैसे लिए मदद करेगा. उसने सबसे पहले जालंधर से अंकित फाड़िया सर्टिफाइड ऐथिकल हैकर्स नामक कोर्स किया. उसके बाद एक साल तक उसने रोज़ाना 16 से 18 घंटे मेहनत की. उसने कंप्यूटर और सूचना-तकनीक के हरेक आयाम को खंगाला. अपने अनुभवों को उस विद्यार्थी ने सितंबर 2007 में एक किताब का रूप दिया. किताब का नाम उसने *गूगल हैकिंग एट यूअर फिंगर टिप्स* रखा. हालांकि आर्थिक समस्याओं के चलते इस किताब की महज़ कुछ हज़ार प्रतियां ही प्रकाशित हो पाईं. इसके छपने के बाद इसकी चर्चा भारत के सभी बड़े अख़बारों में हुई. आज यह किताब सूचना-तकनीक से संबंधित भारत के हरेक कॉलेज की लाइब्रेरी में उपलब्ध है. किताब के प्रसार के बाद उस विद्यार्थी से कई ऐसे लोगों ने संपर्क किया, जिनकी समस्या भी कुछ इसी तरह की थी. और यहीं से संस्था *हंस* की नींव पड़ी. इतने मज़बूत इरादे वाला वह होनहार विद्यार्थी था ऋषि अग्रवाल. ऋषि अग्रवाल ने सात सदस्यों के साथ *हंस एंटी हैकिंग एंटीस्पेशन नेशनल सोसायटी* का गठन किया. इस सोसायटी ने 2007 में लुधियाना व फगवाड़ा पुलिस की आईटी से संबंधित विभिन्न मामलों में सहायता की. वक़्त का पहिया घूमता रहा और ऋषि अग्रवाल ने बीसीए की पढ़ाई समाप्त कर पुणे में एमसीए में दाख़िला लिया. पुणे में इस विषय से संबंधित विभिन्न विद्यार्थियों के संपर्क में आने पर ऋषि अग्रवाल को और प्रोत्साहन मिला और उसने 2009 में *हंस एंटी हैकिंग एंटीस्पेशन सोसायटी* को रजिस्टर्ड करा लिया. इस संस्था की एंटी हैकिंग टीम में सोसायटी के प्रधान ऋषि के अलावा रीतिका गोयल, पल्लवी अग्रवाल व पुनीत मनचंदा हैं, जो एमसीए के विद्यार्थी हैं व कुणाल कपूर इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है. जालंधर का 17 वर्षीय प्रसिद्ध हैकर पारुल खन्ना इस संस्था का सुरक्षा प्रमुख है.

पुलिस के साथ हंस की टीम

> **मोटी रक़म ख़र्च करने में असमर्थ इस विद्यार्थी ने ठान लिया कि वह अपनी तरह की परेशानी से जूझने वाले दूसरे लोगों की मदद के लिए शोध करेगा. उसने सोचा कि वह इस तरह की परेशानियों से दो-चार हो रहे लोगों की बिना पैसे लिए मदद करेगा. उसने सबसे पहले जालंधर से अंकित फाड़िया सर्टिफाइड ऐथिकल हैकर्स नामक कोर्स किया. उसके बाद एक साल तक उसने रोज़ाना 16 से 18 घंटे मेहनत की.**

कुलदीप शर्मा
feedback@chauthiduniya.com

अपने मोबाइल को ऐसे बचाएं हैकिंग से

आपराधिक तत्व हमेशा ही सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में सुरक्षा एजेंसियों से दो क़दम आगे रहे हैं. मोबाइल टेरर के मामले में विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से तैयार करने में अभी समय लगेगा. *हंस* की पूरी टीम इसके अनुसंधान में लगी हुई है. जब तक दुरुपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर की काट नहीं खोज ली जाती या कुछ दूसरे उपाय नहीं कर लिए जाते, तब तक कुछ सावधानियां ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं.

1. जहां तक हो सके मोबाइल का ब्ल्यूटूथ बंद रखा जाए अथवा छिपा कर रखें.
2. अनजान नंबर से लगातार एसएमएस आने पर भेजने वाले व्यक्ति से अतिशीघ्र संपर्क कर उसे चेतावनी दी जाए. संपर्क न होने की स्थिति में कम से कम एक दिन के लिए हैंडसेट ऑफ कर देना चाहिए.
3. सिम कार्ड गुम होने की स्थिति में डुप्लीकेट सिम जारी कराने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि गुम हुए सिम कार्ड की सभी सेवाएं स्थगित हो गई हैं.
4. यदि आपको मोबाइल के बैलेंस अथवा बिल में कोई गड़बड़ी नजर आए तो तुरंत संबंधित नेटवर्क कंपनी से संपर्क कर शंका दूर करनी चाहिए.

कैमरे में है दम, फीचर्स भी नहीं कम

क्या आप कैमरे के शौक़ीन हैं? क्या फोटोग्राफी आपकी आदत में शुमार है? क्या हर समय आप कुछ नया तलाशते हैं, ताकि उसे कैमरे के अंदर क़ैद कर सकें? क्या क्लिक की आवाज़ आपको उत्साहित कर देती है? क्या नया कैमरा आपकी कमज़ोरी है? अगर हां, तो फिर आप एक और कैमरा ख़रीदने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि फ्यूजी फिल्म ने एक नया डिजिटल कैमरा (फ्यूजी फिल्म फाइनपिक्स एस 1500) लांच किया है. इसका लुक काफी आकर्षक है और आपको यह हर दुकान पर मिल जाएगा.

उम्मीद की जा रही है कि यह कैमरा फोटोग्राफी के शौक़ीन लोगों को अपनी ओर खींचेगा. वैसे यह कैमरा नौसिखिए या ग़ैर-पेशेवर लोगों के लिए है, ताकि वे आसानी से फोटोग्राफी कर सकें. दस मेगा पिक्सल वाले इस कैमरे में सुपर ज़ूम सुविधा के साथ ही फ्यूजीनॉन 12* ऑप्टिकल ज़ूम (33एमएम-369एमएम के बराबर) है. फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी के अलावा ऑटोमैटिक रेड आई रिमूवल भी है. ड्यूएल इमेज स्टैबिलाइजेशन की सुविधा भी इसके अंदर है. इसमें एक नया ट्रैकिंग ऑटो फोकस फंक्शन है, जो नौसिखुओं के लिए काफी फ़ायदेमंद साबित होगा. इसमें पैनोरमा शूटिंग मोड और इंस्टैंट ज़ूम के फीचर्स भी मौजूद हैं. बैटरी की खपत भी कम होती है. एक बार चार्ज करने के बाद एए बैटरी से 300 फोटो खींचे जा सकते हैं, जबकि एए लिथियम बैटरी से 700 फोटो खींचे जा सकते हैं. इसकी क़ीमत 15,499 रु. है और यह सभी रिटेल दुकानों पर मिलता है.

रोज़ बचाएं थोड़ी-थोड़ी ऊर्जा

climate savers
smart computing

आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां डेल, गूगल, एचपी, इंटेल, लेनोवो और माइक्रोसॉफ्ट भले ही आईटी मामले में एक-दूसरे की प्रतिद्वंद्वी हों, लेकिन जब बात पर्यावरण और ऊर्जा बचाने की हो तो सब एकसाथ हैं. वैश्विक पहल द *क्लाइमेट सेवर्स कप्यूटिंग इनिशिएटिव* (सीएससीआई) ने अब भारत में भी इस अभियान की शुरुआत की है. इसके साथ ही डेल, इंटेल, एचपी, गूगल, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, टेरी, सीआईआई-आईटीसी सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एमएआईआई और नासकॉम ने रोज़मर्रा की कंप्यूटिंग में ऊर्जा बचाने वाली आदतों की जानकारी देने और लोगों को जागरूक बनाने के लिए आपस में हाथ मिलाया है.

ग़ौरतलब है कि 2007 में सीएससी, डेल, गूगल, एचपी, इंटेल, लेनोवो और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी आईटी कंपनियों ने अमेरिका में सीएससीआई नाम से एक वैश्विक अभियान की शुरुआत की थी. यह समूह रोज़मर्रा की कंप्यूटिंग के लिए आधुनिक और उन्नत तकनीक के इस्तेमाल पर ज़ोर देता है, ताकि ऊर्जा की कम से कम खपत हो. ख़ासकर जब कंप्यूटर पर काम नहीं हो रहा हो, तब उस पर कम से कम बिजली ख़र्च हो, इस पर ज़ोर दिया जाता है. पत्रिका *पीसी ट्रैकर* के मुताबिक 2009 तक भारत में 41 लाख से ज़्यादा डेस्कटॉप और 24 लाख से ज़्यादा नोटबुक हो जाएंगे. विशेषज्ञों की मानें तो डेस्कटॉप कंप्यूटरों में आधी से ज़्यादा ऊर्जा गर्मी के कारण बेकार हो जाती है. यहां तक कि सर्वर, जो डेस्कटॉप की तुलना में कम ऊर्जा खपत करते हैं, भी 30 से 40 फ़ीसदी ऊर्जा बर्बाद करते हैं. इस बर्बादी का मुख्य कारण लोगों में जानकारी का अभाव है. उदाहरण के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर में स्लीप मोड के लिए डिफॉल्ट सेटिंग होती है, जिससे ज़्यादा देर काम न करने पर कंप्यूटर इनएक्टिव मोड में चला जाता है, लेकिन अधिकतर घरेलू कंप्यूटरों में यह सुविधा ऑफ होती है. सीएससीआई इंडिया के नौ संस्थापक सदस्यों ने अगले तीन साल में कार्बन उत्सर्जन में 40 लाख टन की कमी लाने और कंप्यूटिंग पर बिजली खपत में 50 फ़ीसदी कटौती करने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए वे अपने ग्राहकों को इन फीचर्स के बारे में जागरूक करेंगे जिससे बिजली की बचत होती हो. टेरी के महानिदेशक और जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र के पचौरी ने इस अभियान के भारत में शुरू होने पर कहा कि भविष्य में आईटी उपकरणों की संख्या में संभावित वृद्धि के मद्देनज़र यह ज़रूरी है कि आईटी उद्योग ऊर्जा की खपत में बढ़ोतरी के नतीजों के प्रति सचेत रहे.

नया नोट बुक मचाएगा धमाल

नोट बुक के दीवानों को आकर्षित करने के लिए बाज़ार में तोशिबा का नया नोटबुक (सेटेलाइट एम-500) आ चुका है. नोट बुक की श्रेणी में तोशिबा ने एक नया नोटबुक लांच किया है, जो काफी हल्के वजन का है. इसमें नए फीचर्स हैं और इसे देखते ही आपका मन ख़रीदने को मचल उठेगा.

अब आधिकारिक तौर पर तोशिबा ने इसकी क़ीमत की घोषणा कर दी है. क़ीमत 53,490 रुपये हैं. अभी यह बाज़ार में प्रीमियर ब्लैक रंग में ही उपलब्ध है. नोटबुक की बॉडी काले रंग की है, जिस पर कई तरह के पैटर्न हैं. इससे इसकी ख़ूबसूरती और भी बढ़ जाती है.

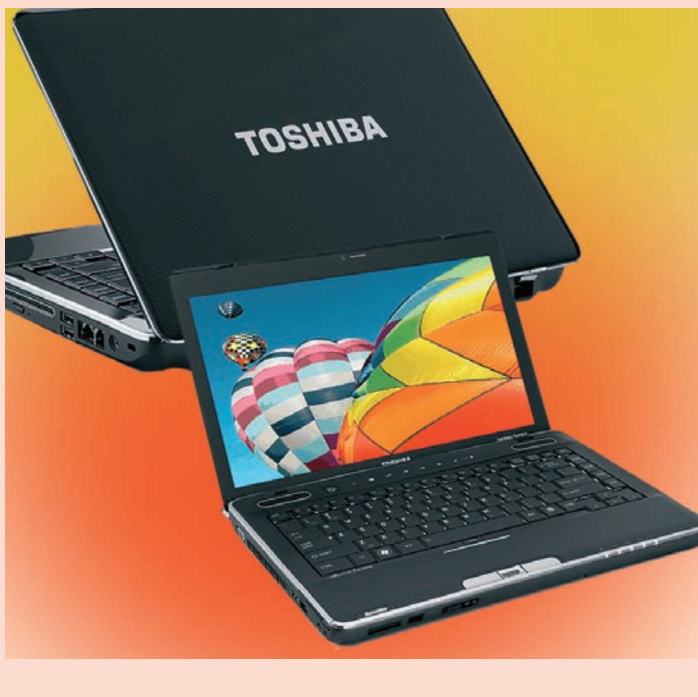

तोशिबा सेटेलाइट एम-500 में इंटेल कोर 2 ड्यूओ प्रोसेसर टी-6500 लगा है. इसमें 4 जीबी डीडीआर2, 800 एमएचजेड मेमोरी, 320 जीबी हार्डडिस्कड्राइव, 5400 आरपीएम की स्टोरेज क्षमता और डूअल लेयर डीवीडी सुपर मल्टी ऑप्टिकल ड्राइव है. इसमें विंडो विस्टा होम प्रीमियम (एसपी1, 64-बाइट) भी है.

सेटेलाइट एम-500 का एक मुख्य फीचर हार्ड ड्राइव मोशन सेंसर है, जो इस नोट बुक के गिरने, हिलने या वाइब्रेशन से ख़ुद-ब-ख़ुद ऑफ हो जाता है. इसका एलसीडी आईएमआर (इन मॉल्ड रोलिंग) टेक्नोलॉजी पर आधारित है. इसकी 14.1 इंच चौड़ी स्क्रीन ख़ास तोशिबा की तकनीक से बनी है, जिससे इसकी तस्वीरें काफी साफ दिखती हैं. इंटेल जीएमए 4500 एमएचडी के साथ ही 128 एमबी-1759 एमबी इस नोट बुक में ग्राफिक्स के लिए लगाया गया है. इनबिल्ट एचडी कैमरे की रिकॉर्डिंग आउटपुट काफी अच्छी आती है.

वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए एम 500 डब्ल्यूएलएएन (802.11 ए/जी/एन) को सपोर्ट करता है. इसके अलवा इसमें ईडीआर के साथ ब्ल्यूटूथ 2.1, वेबकैम के साथ माइक, इनपुट टच कंट्रोल, मल्टी टच ट्रैक पैड, ऊर्जा बचाने के लिए इकोमोड, फिंगर प्रिंट रीडर, मैमोरी कार्ड रीडर, एक्सप्रेस कार्ड स्लॉट. इसके साथ ही फायर वायर, दो यूएसबी 2.0 पोर्ट्स और एक इएसटीए/यूएसबी 2.0 कॉम्बो पोर्ट जैसी आम सुविधाएं तो हैं ही.

मलाई बनाएं भी और खाएं भी

तकनीक की वजह से आज हर क्षेत्र में कामयाबी मिल रही है. लोग आज चांद तक पहुंच गए हैं. नित नए-नए प्रयोगों और आविष्कारों से ज़िंदगी आसान बनती जा रही है. अब देखिए न, पहले लोग दूध से मलाई निकालने के लिए जो पुराना तरीक़ा अपनाते थे, उसमें काफी समय बर्बाद होता था. इतना ही नहीं, अगर दिन भर इस काम में लगे रहते थे तब भी एक-दो किलो ही मलाई बनती थी. अब धीरे-धीरे यहां भी तकनीक का प्रयोग शुरू हो गया और परिणाम भी अच्छे आने लगे हैं. पुराने तरीक़े की जगह मिल्क क्रीम सेपरेटर मशीन आने लगी. हालांकि इनकी थोड़ी ज़्यादा क़ीमत तो होती थी, लेकिन इससे समय बर्बाद नहीं होता था और मलाई भी अधिक निकलती थी. समय के साथ सब कुछ बदलता गया और इस क्षेत्र में भी प्रयोगों का दौर चलता रहा. अभी सर्वोदय इंजीनियरिंग कंपनी ने लोगों की सहूलियत और उनकी जेब का ध्यान रखते हुए नई तरह की मिल्क कई क्रीम सेपरेटर मशीनें बनाई हैं.

इस मशीन से छोटे किसानों को फ़ायदा होगा. इस मशीन की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह हाथ से चलने के अलावा बिजली से भी चलती है. यह एक बड़ी सुविधा है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मिल्क क्रीम सेपरेटर मशीन से मक्खन बना रहा हो तो बिजली चली जाने के बाद भी वह मलाई बना सकता है. साथ ही गांवों और ज़्यादा बिजली कटौती वाली जगहों में भी इनका इस्तेमाल हो सकता है. इनकी मलाई बनाने की क्षमता भी अलग-अलग है. जैसे 10 लीटर, 12 लीटर, 16 लीटर और 20 लीटर इत्यादि. मतलब यह कि कोई मिल्क क्रीम सेपरेटर मशीन अगर एक घंटा में 60 किलो मक्खन बनाए तो हो सकता है कि कोई 80 किलो. लोग इनमें से अपने ज़रूरतों के हिसाब से चुन सकते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

क्या भारतीय हॉकी में कुछ बदलेगा?

नई दिल्ली के उस पांच सितारा होटल में हर चेहरे पर एक ही सवाल था. क्या वाकई कुछ बदलेगा? थके हुए शरीर, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की मजबूरी. मीडिया का पागलपन, ज़्यादातर इसलिए, क्योंकि उन्हें नेगेटिव स्टोरी मिल रही है. हॉकी टीम से जुड़े एक शख्स ने हैरान होकर पूछा– क्या ये सारे लोग टीम से मिलने आए हैं? उसे भी पता था कि सवाल का जवाब क्या है. लोग आए थे तो सिर्फ़ इसलिए, क्योंकि पुणे में फ्लाइट छूट जाने को लेकर कुछ और मसाला मिलने की उम्मीद थी. यह जानने की कोई उत्सुकता नहीं थी कि चार यूरोपियन मुल्कों में टीम कहां कितने मैच खेलेगी. उसी बीच हॉकी इंडिया के एक अधिकारी बताने में लगे थे कि फ्लाइट छूट जाना कितनी मामूली बात है. उनका तर्क था कि हमारी–आपकी फ्लाइट या ट्रेन कभी न कभी तो छूटी होगी. वह ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि आम लोगों और नेशनल टीम में कोई फ़र्क़ होता है. तभी ये सवाल ज़्यादा शिद्दत से उभरकर आया कि क्या वाकई भारतीय हॉकी में कुछ बदलेगा?

पिछले दिनों में बदला है तो कोच. स्पेन के होजे ब्रासा आ गए हैं, लेकिन सिर्फ़ कोच ले आना क्या टीम के सितारे बदल सकता है. कम से कम ऐसा लगता तो नहीं. आख़िर कोच के पास कोई जादू की छड़ी तो होती नहीं. उसके पास अपनी सोच होती है. उसे लागू करने के लिए तमाम लोगों की मदद की दरकार होती है, लेकिन क्या वह मदद मिल रही है. ब्रासा को आए काफी समय हो रहा है, लेकिन वो तकनीकी मदद उन्हें अब तक नसीब नहीं हुई हैं, जिनके बारे में उन्होंने भारत आने से पहले ही कहा था. ब्रासा कह भी गए कि साई यानी भारतीय खेल प्राधिकरण में फ़ैसले धीमे होते हैं, लेकिन तकनीक उससे बहुत तेज़ है. ऐसे में टीम इंडिया तकनीक के साथ नहीं चलेगी, तो बहुत पीछे रह जाएगी.

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

साई के एक अधिकारी से उनकी झड़प तक हो चुकी है. आईएएस रैंक के इस अधिकारी को कॉमनवेल्थ खेलों के लिए ख़ास तौर पर मंत्रालय से साई में लाया गया है. झड़प कोई आपसी मामले पर नहीं, उन उपकरणों को लेकर ही हुई, जो अभी तक आए नहीं हैं.

ब्रासा दुखी दिखते हैं. वह असहाय नज़र आते हैं. साई के अधिकारी ये ज़रूर बताएंगे कि ब्रासा को तमाम आधुनिक उपकरण दिए गए हैं. लेकिन समस्या यह है कि वे उपकरण कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, यह बताने वाला कोई नहीं. ज़्यादातर के बारे में ब्रासा ही बताते हैं, लेकिन कोच का काम इतना कम नहीं होता कि वह फिजिकल से मेंटल ट्रेनिंग तक इस्तेमाल होने वाले हर उपकरण के साथ समय बिताए. ब्रासा पूछते भी हैं कि ऐसे उपकरण मंगाने से क्या फ़ायदा, अगर उन्हें इस्तेमाल में लाने वाला कोई शख्स हमारे साथ नहीं जोड़ा जाता. इन्हीं सारे सवालों के मद्देनज़र ब्रासा को उनकी औकात दिखाए जाने की कोशिश की गई. ज़ाहिर है, साई के अधिकारी ब्रासा को अपने सामने कहां कुछ समझेंगे.

याद कीजिए कुछ समय पहले की घटना. महिला हॉकी टीम को विदेश यात्रा से पहले कुछ ज़रूरतें थीं. तब उन्हें कुछ सामान नहीं मिले थे. पूरी टीम और कोच साई के सचिव से मिलना चाहते थे. ओलंपिक गोल्ड मैडलिस्ट कोच एम.के. कौशिक ढाई घंटे तक साई सचिव के कमरे के बाहर इंतज़ार करते रहे, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया. कौशिक वही कोच हैं, जिनके कोचिंग स्टाइल पर फिल्म *चक दे इंडिया* बनी और हिट हुई है, लेकिन कौशिक ज़रूर जानना चाहते होंगे कि उस फिल्म के कबीर ख़ान को ऐसे ही दर–दर भटकना है, तो वह कब तक सीमितताओं में रहकर सफलता दिलाएगा. यही भारतीय हॉकी की असली समस्या है. यहां अधिकारी किसी खिलाड़ी को सम्मान नहीं देना चाहते. एक अधिकारी ने खिलाड़ी को बाहर करने की पेशकश महज़ इसलिए की थी, क्योंकि वह उनके साथ रखी कुर्सी पर बैठ गया था. यह अधिकारी महोदय को रास नहीं आया. जहां ऐसी सोच हो, वहां कैसे बदलाव होंगे, इनका फ़ैसला आप ख़ुद कर सकते हैं.

ब्रासा का आना उस सोच को बदलने वाला है. खिलाड़ी कहते हैं कि इस तरह ट्रेनिंग कभी नहीं देखी. एक खिलाड़ी का कहना है कि मुझे पहली बार पता चला कि भद्दी–भद्दी गालियां खाए बिना भी हॉकी खिलाड़ी ट्रेनिंग कर सकता है. ब्रासा ने उन्हें सवाल पूछना सिखाया है. उनमें भरोसा भरने की कोशिश की है. यह भरोसा कि तुम्हें बिना किसी कारण टीम से बाहर नहीं किया जाएगा. ब्रासा के लिए टीम के हर लड़के में सम्मान नज़र आता है. यह सिर्फ़ इसलिए है, क्योंकि ब्रासा ने आने के बाद खिलाड़ियों के सम्मान की बात की है, लेकिन सवाल यही है कि ये सब चलेगा कब तक. कब तक वे अधिकारी चलने देंगे, जो बेहतर भविष्य की मांग को बदतमीज़ी मानते हैं. मानते हैं कि इस तरह की मांग करने का हक़ किसी को नहीं है. तभी इस तरह के अधिकारी ब्रासा को लेकर लामबंद होने लगे हैं. आश्चर्य मत कीजिएगा अगर वर्ल्ड कप के बाद ख़ुद किसी दिन होजे ब्रासा अपना बैग उठाकर स्पेन का रुख़ करते दिखाई दें. वह अगर रुकेंगे, तो सिर्फ़ इसलिए कि उनके पास कोई और अच्छा ऑफर न हो. वरना पिछले एक–डेढ़ महीने में उन्होंने देख लिया है कि इस देश में खेल कैसे चलता है. खेल तो यहां जमकर होता है. इसमें किसी को शक़ नहीं. लेकिन अफसोस, यह महज़ फाइलों में होता है. मैदान पर जैसे ही यह खेल रवानी पकड़ता है, ब्रासा जैसे किसी कोच को टीम से या मुल्क से रवाना करने की कोशिश शुरू हो जाती है.

राकेश चतुर्वेदी

feedback@chauthiduniya.com

क्या ओलंपिक पदक जीतनेवाले नहीं हैं खेल रत्न के क़ाबिल?

भारत में ओलंपिक का इतिहास 115 साल पुराना है. इस 115 साल के इतिहास में भारत ने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में महज़ सात पदक जीते हैं. ओलंपिक में व्यक्तिगत स्तर पर पदक जीतना भारतीय खेलों के लिए एक ख़ास उपलब्धि रही है, तभी तो पिछले साल ओलंपिक में व्यक्तिगत स्तर पर पदक जीतने पर जैसी ख़ुशी मनाई गई, पहले कभी नहीं मनाई गई थी. ख़ुशी भी किसी एक पदक की नहीं, तीन–तीन पदकों की थी. अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार और विजेंदर के रूप में भारत को उसके नए नायक मिल गए थे. हालांकि, सरकार और जनता दोनों की याददाश्त बड़ी छोटी है. ओलंपिक की लहर ख़त्म होते–होते इनकी उपलब्धियां बिसरा दी गईं. आश्चर्य यह कि ऐसा होने में साल भर का भी वक़्त नहीं लगा. कम–से–कम विजेंदर और सुशील तो यह समझ ही गए होंगे. देश का पहला व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाले अभिनव बिंद्रा की उपलब्धि ने भले ही बाक़ियों की उपलब्धियों को दबा दिया हो लेकिन उनकी उपलब्धि भी भारत के खेलों के लिए कोई कम नहीं थी. हरियाणा के विजेंदर और दिल्ली के सुशील को मिले कांस्य की चमक भले ही अभिनव के सोने से थोड़ी कम थी, लेकिन पदक के लिए तरसते भारतीय खेलों के लिए उनकी अहमियत कम नहीं थी. बिंद्रा, सुशील और विजेंदर पर पुरस्कारों , प्लाटों और तरक़्क़ी की बरसात होने लगी. यह सब कुछ बीते वर्ष अगस्त में हुआ था. लेकिन धीरे–धीरे जोश ठंडा पड़ने लगा. जनवरी में पद्म पुरस्कारों की सूची में उन्हें जगह नहीं मिली. छह महीने बाद अब सुशील और विजेंदर को

स्पेशल केस के तहत संयुक्त रूप से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफ़ारिश की गई है. यह सिफ़ारिश भी सीधे तौर पर नहीं की गई. खेल रत्न पुरस्कार के लिए महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियन एमसी मैरीकॉम का नाम नामांकित किया गया. उसके अगले दिन सुशील और विजेंदर के केस पर विचार करने की दलील दी गई. सिफ़ारिश करने वाले पैनल की अध्यक्षता इंदु पुरी–आठ बार राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन– कर रही थीं.

दरअसल मेरीकॉम के नाम पर कोई विवाद नहीं है. यहां सवाल उससे बड़ा है. क्या ओलंपिक पदक विजेता खेल रत्न पुरस्कार के लिए अपने–आप पहली पसंद नहीं होने चाहिए? क्या ओलंपिक के तीनों नायकों को खेल रत्न पुरस्कार के लिए दावेदार नहीं होना चाहिए था? आख़िरी फ़ैसला बिंद्रा के पक्ष में दिया जा सकता था. हालांकि खेल रत्न के इस अतार्किक नियम–कि यह पुरस्कार दोबारा उसी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है जिसे एक बार दे दिया गया हो–की वजह से बिंद्रा का नाम सूची से हटा दिया गया. ग़ौरतलब है कि यह पुरस्कार उन्हें 2001 में मिल चुका है. हालांकि अगर नोबल, ऑस्कर और लॉरियस खेल पुरस्कार– रोजर फेडरर इसे 2005 से चार बार लगातार जीते – दोबारा दिए जा सकते हैं, तो फिर यह पुरस्कार दोबारा नहीं देने का यह तर्क समझ से परे है.

अगर बिंद्रा को यह पुरस्कार नहीं दिया जा सकता था तो क्या उसके बाद सुशील और विजेंदर सीधे इसके लिए अगली पसंद नहीं होने चाहिए थे? वैसे भी यह पुरस्कार पूरे वर्ष में खिलाड़ी के प्रदर्शन से संबंधित होता है न कि उसकी पूरी उपलब्धि से. नियमानुसार किसी खिलाड़ी को खेल के क्षेत्र में एक वर्ष में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है. भारत के लिए ओलंपिक का व्यक्तिगत पदक जीतने वाले हर खिलाड़ी को (के डी जाधव को छोड़कर जिन्होंने इसे 1952 में जीता था) खेल रत्न मिल चुका है. ऐसे में सुशील और विजेंदर को क्यों नहीं चुना नहीं गया, यह लाख कोशिश के बाद भी समझ में आने वाला नहीं है.

ग़ौरतलब है कि पिछले साल पद्म पुरस्कारों में खेल मंत्रालय की सिफ़ारिश नहीं माने जाने पर खेल मंत्री एम एस गिल बड़े नाराज़ हुए थे. इस बार फ़ैसला उन्हीं के हाथ में है. उन्हें सोच समझकर फ़ैसला लेना चाहिए. जहां तक मेरीकॉम की बात है तो इसमें कोई शक़ नहीं है कि वह बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं. लेकिन उन्हें शायद दूसरा मौका मिल जाए, पर क्या विजेंदर और सुशील को फिर से मौका मिलेगा? उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या ओलंपिक पदक जीतकर भी लोग खेल रत्न के क़ाबिल नहीं होते? अब इन सवालों के जवाब गिल साहब ही दे सकते हैं.

किंग ख़ान ने दी दादा को ज़िम्मेदारी

सौरभ गांगुली के भारत के सफलतम कप्तान होने की बात सब करते हैं, लेकिन यह लोग अकसर भूल जाते हैं कि उनमें विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का ग़ज़ब का माद्दा है. हालात को अपने अनुकूल कैसे बनाया जाता है, यह कोई उनसे सीखे. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद यह मान लिया गया था कि वह अब गुमनामी में चले जाएंगे. आईपीएल–2 में उनके कमज़ोर प्रदर्शन ने इस तरह की आशंकाओं को और बल दिया. ऊपर से केकेआर के कोच जॉन बुकैनन ने वापसी की दिशा में उनके सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए. लेकिन वक़्त का पहिया ऐसा घूमा कि आज बुकैनन बाहर हो गए हैं और दादा अगले साल होने वाली आईपीएल में केकेआर की कप्तानी करते एक बार फिर नज़र आएंगे.

यह सब अचानक नहीं हुआ है. ऐसा इसलिए भी नहीं हुआ है कि दादा ने इस बीच कोई धमाकेदार क्रिकेट खेली है. ऐसा हुआ है तो सिर्फ़ इसलिए कि सौरभ गांगुली ने राजनीति को हथियार बना लिया है.

बीसीसीआई की राजनीति करने की उनकी एक घोषणा ने भारतीय क्रिकेट में तूफ़ान ला दिया. इससे उठी लहरों से केकेआर के मालिक शाहरुख़ ख़ान भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए. उन्होंने जिसे डूबा हुआ मान लिया था, वह तो उगता हुआ सूरज निकला.

यह तय है कि सौरभ कोलकाता क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव लड़ेंगे. तय तो यह भी माना जा रहा है कि वह एकतरफा जीत भी करेंगे. ऐसे में दादा को नाराज़ करने का जोख़िम भला कौन मोल लेगा? किंग ख़ान तो कतई नहीं, जो पहले ही हाथ जला चुके हैं. आईपीएल–2 में बुकैनन के कहने पर उन्होंने दादा से कप्तानी छीन कर न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज मैकुलम को सौंप दी थी. वह भी काफी लंबी–चौड़ी भूमिका बांधने के बाद. पहले चार–चार कप्तान बनाने की बात की गई, फिर कहा गया कि दादा में दम ही नहीं रह गया है. बाद में टीम प्रबंधन पर रंगभेद तक के आरोप लगे. इन सबसे किंग ख़ान की बड़ी भद्द पिटी थी. टीम का मनोबल इतना गिर गया कि केकेआर पिछले साल की तरह इस बार भी आईपीएल में फिसड्डी ही साबित हुई, जबकि टीम में क्रिस गेल जैसे स्टार क्रिकेटर थे.

बहरहाल, दादा अबकी न सिर्फ़ केकेआर का कप्तान बने हैं बल्कि वह कोच से लेकर खिलाड़ी चुनने तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. सूत्रों के मुताबिक केकेआर टीम प्रबंधन डेव व्हाटमोर को नया कोच बनाना चाहता है, लेकिन गांगुली ने इसका विरोध कर दिया है. वह भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच जॉन राइट को केकेआर में लाना चाहते हैं. ग़ौरतलब है कि जब गांगुली भारतीय टीम के कप्तान थे, तब राइट ही कोच की भूमिका में थे. उस दौरान भारत को मिली सफलता का काफी हद तक श्रेय जॉन राइट को भी जाता है.

सूत्रों के मुताबिक केकेआर प्रबंधन दादा की पसंद पर राजी हो गया है. इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि सौरभ गांगुली और जॉन राइट की टीम एक बार फिर बनेगी और केकेआर की क़िस्मत बदल देगी.

सगाई से चमकी सानिया की क़िस्मत!

कहते हैं कि शादी के बाद कई बार लोगों की क़िस्मत पलट जाती है. *लेडी लक* के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इस बार बात थोड़ी सी अलग है. इस बार भारतीय टेनिस की सनसनी सानिया मिर्ज़ा के लिए उनकी सगाई अच्छी क़िस्मत का तोहफ़ा लेकर आई है. उनका जीवनसाथी उनके लिए *जेंटलमैन्स लक* लेकर आया है. हैदराबादी उद्योगपति सोहराब मिर्ज़ा से सगाई के बाद सानिया ने लेक्सिंगटन चैलेंजर टूर्नामेंट में जीत दर्ज की. ज़ाहिर है, इससे सानिया की ख़ुशी दोगुनी हो गई होगी. वैसे भी हाल के दिनों में सानिया अपने खेल और अपनी जीत की ख़बरों से ज़्यादा विवादों, चोटों, दीवाने फैंस और अपनी शादी की ख़बरों के लिए चर्चा में रही हैं. हालांकि वह कई टेनिस टूर्नामेंटों के शुरुआती दौरों में अच्छा खेल दिखाती रही हैं लेकिन ज़्यादा आगे बढ़ने में कोई न कोई रोड़ा ज़रूर आता रहा. वैसे महेश भूपति के मिक्स्ड डबल और शहार पीर व वानिया जैसे जोड़ीदारों के साथ डबल्स में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था लेकिन सिंगल्स में उनकी रैंकिंग गिरती जा रही थी. अब सानिया को असल ज़िंदगी में भी जोड़ीदार मिल गया है तो लगता है कि सिंगल्स में भी वह कमाल दिखाएंगी. पहले ही टूर्नामेंट में जीत से उन्होंने इसकी झलक भी दिखला दी है. वैसे भी किसी भी खेल में शीर्ष तक पहुंचने के लिए अच्छे खेल के साथ क़िस्मत का साथ भी मिलना ज़रूरी होता है. हालांकि अगर सच में सानिया की क़िस्मत बदली है तो इससे उनके और भारतीय टेनिस फैंस भी ख़ुद को लकी समझ रहे होंगे. उन्हें उम्मीद रहेगी कि सानिया ऐसा ही खेल दिखाती रहेंगी और उनकी क़िस्मत भी साथ देती रहेगी. फ़िलहाल तो हम उन्हें बधाई ही दे सकते हैं, और कह सकते हैं–गुड लक सानिया.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

दो बहनों के बीच मुक़ाबला

अगर बॉलीवुड में एक ही फिल्म में दो नायिकाएं काम करें तो ज़ाहिर सी बात है कि विवाद पैदा होगा ही. ऐसे में अगर दो बहनें साथ काम करें तो क्या होगा? यह अलग बात है कि पहले भी दो बहनों ने बॉलीवुड में काम किया है. शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी हों या अभी की सेन बहनें. लेकिन एक ही फिल्म में दो सगी बहनों के साथ काम करने का अवसर विरले ही आया है. यह गौरव हासिल हुआ है रिया और राइमा सेन को. दोनों ऋतुपर्णो घोष की फिल्म *नौकाडूबी* में एक साथ काम कर रही हैं. इस फिल्म की ख़ास बात यह है कि रिया और राइमा के रोल दोनों की अब तक की इमेज से कतई मेल नहीं खाते हैं. सेक्सी लुक में दिखने वाली रिया पहले से ही लोगों की नींदें उड़ाती रही हैं. यानी लोगों के बीच उनकी इमेज हॉट एक्ट्रेस की है. लेकिन *नौकाडूबी* में उनके रोल में ग्लैमर तो ढूंढ़ने से भी नहीं मिल पाएगा. दूसरी राइमा को संवेदनशील अभिनेत्री के रूप में जाना जाता रहा है. लेकिन ऋतुपर्णो ने रिया के बजाय उनसे ग्लैमरस रोल करा कर चौंका दिया है. ऐसे में दोनों एक-दूसरे से बेहतर निकलने में जी-जान से जुट गई हैं.

छोटे पर्दे ने पकड़ी बड़े पर्दे की राह

आजकल छोटे पर्दे पर जितने भी सीरियल चल रहे हैं, वे सारे किसी-न-किसी फिल्म पर आधारित हैं. पहले तो बॉलीवुड ही हॉलीवुड की नक़ल के मामले में बदनाम था, अब तो छोटा पर्दा भी इस होड़ में शामिल हो गया है. विदेशों के रियलिटी शो की नक़ल कर कार्यक्रम तो बनाए ही जा रहे हैं, मज़े की बात यह कि अब बॉलीवुड की कहानियों को चुराकर सीरियल बनाए जा रहे हैं. जैसे, स्टार प्लस पर जो सीरियल *ये रिश्ता क्या कहलाता है* चल रहा है उसकी कहानी राजश्री की फिल्म *विवाह* से उड़ा ली गई है. *मितवा* सीरियल की कहानी भी *अनाड़ी* (वेंकटेश-करिश्मा वाली) फिल्म से मिलती-जुलती है. इसमें भी नायक-नायिका की सामाजिक बैकग्राउंड को केंद्र में रखा गया है. *बालिका वधू* देखने और सराहने वाले दर्शकों को बताते चलें कि इस सीरियल की कहानी मूल तौर पर एक फिल्म बनाने के लिए लिखी गई थी. यह कहानी 1992 में सीरियल के डॉयरेक्टर पुर्णेदु शेखर ने लिखी थी. जब वह फिल्म नहीं बना सके तो उन्होंने सीरियल बनाने की सोच ली. उसके बाद *कुमकुम, अस्तित्व, साथी* रे जैसे पॉपुलर सीरियल की कहानी लिखी. सही समय का इंतज़ार करते हुए अब से कुछ दिनों पहले *बालिका-वधू* की कहानी बेच दी. यह सीरियल आज के समय में सबसे ज़्यादा टीआरपी बटोर रहा है. ऐसे ही फिल्म *सीता और गीता* की कहानी पर एनडीटीवी इमेजिन ने इसी नाम से सीरियल का प्रसारण शुरू किया है. ऐसे ही सोनी पर शुरू हुआ *भास्कर भारती* भी फिल्म *मिस्टर या मिस* की कॉपी है. फिल्म में निभाए आफताब के रोल को एजाज ख़ान ने तो अंतरा माली के निभाए किरदार को रागिनी खन्ना निभा रही हैं.

अभी कुछ दिनों पहले जीटीवी पर चल रहे सीरियल *घर की लक्ष्मी बेटियां* की कहानी में फिल्म *आजा नच ले* की छाया दिखी. जब, जाह्नवी आश्रम को बचाने के लिए गांव वालों को डांस के लिए प्रेरित करती है, तो ज़ाहिर तौर पर लोगों को माधुरी की भूमिका याद आ गई. जी टीवी का ही दूसरा सीरियल छोटी बहू की कहानी भी काफी हद तक फिल्म *आईना* से मेल खाती है. *तुझ संग प्रीत लगाई सजना* सीरियल तो लगता है फिल्म *रब ने बना दी जोड़ी* से फ्रेम दर फ्रेम उठा ली गई है. वहीं, *मेरे घर आई नन्हीं परी* की कहानी फिल्म *दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे* से मेल खाती है. अभी हाल ही में जी टीवी पर शुरू हुआ *आपकी अंतरा* की कहानी *तारे ज़मीं पर* की झलक दे रही है.

अब रानी के साथ जुड़ा शाहिद का नाम

शाहिद कपूर का तो कहना ही क्या. चॉकलेटी शाहिद कपूर करीना से ब्रेकअप के बाद अभी तक तो सिंगल ही हैं, भले ही इस बीच उनका नाम विद्या बालन से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक के साथ जुड़ा हो. अब रानी मुखर्जी के साथ शाहिद का नाम जोड़ा जा रहा है. वैसे हो सकता है कि यह एक पब्लिसिटी स्टंट हो, क्योंकि इन दोनों की फिल्म *दिल बोले हड़िप्पा* कुछ दिनों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में दोनों के कई रोमांटिक सीन भी फिल्माए गए हैं. ऐसे दृश्यों की वजह से ही दोनों एक-दूसरे के क़रीब आए, ऐसा सूत्रों का कहना है. शाहिद का नाम हालांकि पहले भी कई हीरोइनों के साथ जोड़ा जा चुका है. फिल्म *कमीने* के समय प्रियंका के साथ, तो *किस्मत कनेक्शन* के दौरान विद्या बालन का नाम शाहिद के साथ जुड़ा था. हालांकि संभावना इसी बात की है कि बाक़ी दो की तरह शाहिद का यह अफेयर भी फिल्म की शूटिंग के साथ ही ख़त्म हो जाएगा.

दक्षिण की एक और हीरोइन बॉलीवुड में

आए दिन ही बॉलीवुड में नई हीरोइनों का आना-जाना लगा रहता है. साउथ की हीरोइनों का तो आना लंबे समय से लगा रहा है. आज के दौर में यह सिलसिला कुछ अधिक ही हो गया है. अब असिन, जेनेलिया डिसूज़ा, श्रेया सरन और तृषा की एंट्री तो हो ही चुकी है. कमल हासन की बेटी श्रुति हासन भी फिल्म *लक* में बतौर हीरोइन नज़र आने वाली हैं. अब बारी है दक्षिण की ही प्रियामणि की. वह मणिरत्नम की अगली फिल्म *रावण* में काम कर रही हैं. वैसे तो इसमें ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन प्रमुख भूमिका में दिखाई देंगे, लेकिन प्रियामणि की भी एक अहम भूमिका इस फिल्म में है. फिल्म तमिल और हिंदी दोनों में बनेंगी और दोनों ही भाषाओं में प्रिया का रोल एक ही होगा. प्रिया को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं. हो भी क्यों नहीं, भई पहली फिल्म ही अगर मणिरत्नम के साथ हो, तो उम्मीदें तो जगेंगी ही. अब तो यही देखना बाक़ी है कि प्रिया को असिन और जेनिलिया जैसी सफलता मिल पाएगी या नहीं.

रामू की पहली पसंद प्रियंका कोठारी

प्रियंका कोठारी याद हैं आपको. वही, जिन्होंने अपना नाम निशा कोठारी की जगह प्रियंका कोठारी कर लिया था. वही जो सिर्फ़ राम गोपाल वर्मा की फिल्मों में नज़र आती हैं. अभी कुछ दिनों में रिलीज होने वाली रामू की फिल्म *अज्ञात* में भी अभिनेत्री के रूप में प्रियंका ही नज़र आएंगी. यह फिल्म सुपर नेचुरल थ्रिलर है. इससे पहले रामू की *भूत* में उर्मिला मातोंडकर के काम की काफी तारीफ़ हुई थी. अब प्रियंका को भी *अज्ञात* से ऐसी ही उम्मीदें होंगी. शायद यही वजह है कि जब भी रामू के बारे में पूछा जाता है, तो वह उनकी तारीफ़ के पुल बांध देती हैं. वैसे, एक बात तो तय है कि रामू की फिल्मों में हमेशा ही उनकी हीरोइनों की चर्चा होती है. बात चाहे प्रियंका कोठारी से लेकर अंतरा माली और उर्मिला मातोंडकर की हो. चाहे वह बड़े रोल में हो या छोटे, प्रियंका भी रामू को मना नहीं करतीं. हैरानी का बात यह है कि वह रामू की फ्लॉप फिल्मों में तो नज़र आ जाती हैं, लेकिन जो उनकी अच्छी या सराही जाने वाली फिल्में होती हैं, वह उसमें नहीं होतीं. जैसे *आग, गो, जेम्स* जैसी फिल्मों में प्रियंका वह सब करती नज़र आईं जो हिट होने के लिए कोई अभिनेत्री करती है, फ़ायदा फिर भी नहीं हुआ. ख़ैर, प्रियंका अभी भी उनके साथ ही हैं, करें भी तो क्या? आख़िर एक रामू ही तो हैं, उनकी नैया के खेवनहार.

बालिका वधू पर भी साधा निशाना

सबसे चर्चित सीरियल *बालिका वधू* पर भी लगता है कि ग्रहण लगने वाला है. लोगों का कहना है कि इसमें बाल विवाह पर अधिक ज़ोर दिया गया है, और उसका महिमामंडन किया गया है. कुछ दिनों पहले ही जनता दल-यू के अध्यक्ष शरद यादव ने पिछले दिनों लोकसभा में बाल-विवाह को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए सीरियल को बंद करने की मांग की थी. उनकी शिकायत पर केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने सीरियल देखकर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है. इसे बहुत जल्द ही लोकसभा में रखा जाएगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

कृपया अपने सबस्क्रिप्शन चेक अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर अपने नाम और पूरे पते के साथ यहां भेजें : (गैनन) के-2, दूसरी मंज़िल, चौधरी बिल्डिंग, मिडिल सर्किल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली -110001

वार्षिक शुल्क :1000 रु.

सफलता की प्यासी पायल

हर अभिनेत्री का मन होता है कि उन्हें सफलता मिले. यही हाल अपनी पायल रोहतगी का भी है. *बिग बॉस* के घर में राहुल महाजन से मसाज कराकर सनसनाती हुई निकली पायल ने सोचा कि पहले सुर्ख़ियां तो बटोर लें. मशहूर होने के बाद फिल्मों में काम के साथ नाम तो मिल ही जाएगा. उन्हें क्या पता था कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती. सफलता हासिल करने के चक्कर में बेचारी पायल ने कितने पापड़ नहीं बेले. न जाने कितने शार्टकट अपनाए. मिनी स्कर्ट में बोल्ड दृश्य देकर दर्शकों को लुभाने की कोशिश की. उनको लगा कि इन सब हरकतों से उनके करियर में जान पड़ जाएगी. अफ़सोस, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. पहले तो एकाध फिल्मों में छोटा-मोटा रोल मिल भी जाता था, अब तो वह भी नहीं मिल रहा.हां, एक नया काम इधर उन्होंने ज़रूर शुरू कर दिया है. वह भी बॉलीवुड के टेक्नो-सैवी ब्रिगेड में शामिल हो गई हैं. उन्होंने भी ब्लॉग लिखना शुरू किया है. उनके मुताबिक इसके दो लाभ हैं- एक तो वह अब अपने मन की बात सबसे शेयर करने सकती हैं. दूसरे, वह अब अपने चहेतों से सीधी जुड़ रही हैं. अब उनको कौन समझाए कि चहेतों से मुखातिब होने के लिए चहेते होने भी तो चाहिए.